खण्ड-07 सत्र-05 (भाग-02) / अंक-72

शुक्रवार 27 सितम्बर, 2024 / 05 अश्विन, 1946 (शक)

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

सत्यमेव जयते

सातवीं विधान सभा

पाँचवां सत्र

अधिकृत विवरण

(खण्ड-07, सत्र-5 (भाग-02) में अंक 71 से 72 तक सम्मिलित हैं।)

दिल्ली विधान सभा सचिवालय

पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054

सम्पादक वर्ग

EDITORIAL BOARD

रंजीत सिंह

सचिव

RANJEET SINGH

Secretary

महेन्द्र गुप्ता

उप-सचिव (सम्पादन)

MAHENDRA GUPTA

Deputy Secretary (Editing)

विषय सूची

सत्र-5 (भाग-02) शुक्रवार, 27 सितंबर, 2024/05 अश्विन, 1946 (शक) अंक-72

क्र.सं.	विषय	पृष्ठ सं.
1.	सदन में उपस्थित सदस्यों की सूची	1-2
2.	माननीय पर्यावरण मंत्री का वक्तव्य	3-9
3.	सदन में अव्यवस्था	10-13
4.	धन्यवाद प्रस्ताव (नियम-114)	14-26
5.	ध्यानाकर्षण (नियम-54)	27-30
6.	दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति के चुनाव में माननीय उप राज्यपाल के कथित हस्तक्षेप के संबंध में ध्यानाकर्षण	31-60
7.	संकल्प (नियम-89)	61-89
8.	सदन में अव्यवस्था	90-98
9.	अल्पकालिक चर्चा (नियम-55)	99-192
10.	विधेयक पर विचार एवं पारण	193-196

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

सत्र-5 (भाग-02) शुक्रवार, 27 सितंबर, 2024/05 अश्विन, 1946 (शक) अंक-72

दिल्ली विधान सभा

निम्नलिखित सदस्य सदन में उपस्थित हुए:

1. श्री अजेश यादव
2. श्री अखिलेशपति त्रिपाठी
3. श्रीमती ए. धनवंती चंदीला ए.
4. श्री अब्दुल रहमान
5. श्रीमती बंदना कुमारी
6. सुश्री भावना गौड
7. श्री बी. एस. जून
8. श्री दिनेश मोहनिया
9. श्री दुर्गेश कुमार
10. श्री गिरीश सोनी
11. श्री गुलाब सिंह
12. श्री हाजी युनूस
13. श्री जय भगवान
14. श्री जरनैल सिंह
15. श्री कुलदीप कुमार
16. श्री नरेश यादव
17. श्री प्रीति जितेंद्र तोमर
18. श्री प्रलाद सिंह साहनी
19. श्री राजेश गुप्ता
20. श्रीमती राजकुमारी ढिल्लों

21. श्री रोहित कुमार
22. श्री संजीव झा
23. श्री सोमदत्त
24. श्री शिव चरण गोयल
25. श्री सोमनाथ भारती
26. श्री सही राम
27. श्री एस. के. बग्गा
28. श्री सुरेंद्र कुमार
29. श्री विनय मिश्रा
30. श्री वीरेंद्र सिंह कादियान
31. श्री अजय दत्त
32. श्री अभय वर्मा
33. श्री अनिल कुमार बाजपेयी
34. श्री अजय कुमार महावर
35. श्री जितेंद्र महाजन
36. श्री महेंद्र गोयल
37. श्री मदन लाल
38. श्री मोहन सिंह बिष्ट
39. श्री ओमप्रकाश शर्मा
40. श्री पवन शर्मा
41. श्री प्रवीण कुमार
42. श्री ऋतुराज गोविंद
43. श्री रघुविंदर शौकीन
44. श्री राजेश ऋषि
45. श्री शोएब इकबाल
46. श्री विजेंद्र गुप्ता
47. श्री विशेष रवि

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

सत्र-5 (भाग-02) शुक्रवार, 27 सितंबर, 2024/05 अश्विन, 1946 (शक) अंक-72

सदन पूर्वाह्न 11.24 बजे समवेत हुआ।

माननीय अध्यक्ष (श्री राम निवास गोयल) पीठासीन हुए।

माननीय अध्यक्षः सभी माननीय सदस्यों का आज दूसरे दिन हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। विषय कई चर्चा में हैं।

माननीय पर्यावरण एवं वन मंत्री (श्री गोपाल राय): माननीय अध्यक्ष जी, मुझे एक बात रखनी थी बहुत महत्वपूर्ण है। कल सदन में चर्चा के दौरान माननीय नेता, प्रतिपक्ष विजेन्द्र गुप्ता जी ने अपनी बात रखी थी और मैंने कहा था कि जो पेड़ कटिंग हुई है वो ट्री आफिसर की परमीशन के बगैर हुई है। तो अगर नेता, प्रतिपक्ष परमीशन की कापी लाए हों तो वो सदन पटल पर रख दें और नहीं लाए हों, क्योंकि जब दी ही नहीं गई तो होगी ही नहीं। एक बार आप उनसे पूछ लें कि अगर लाए हों तो हम चाहते हैं कि वो ऑन रिकार्ड हो जाए।

श्री विजेंद्र गुप्ता (माननीय नेता प्रतिपक्ष): क्या ऑन रिकार्ड हो जाए, मैंने कौन सा...... मैंने कब कहा...

...व्यवधान...

माननीय पर्यावरण एवं वन मंत्रीः सुनो-सुनो, आप सुनो।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः चलिए-चलिए अब।

...व्यवधान...

माननीय पर्यावरण एवं वन मंत्रीः दिल्ली के अंदर, अध्यक्ष जी,

...व्यवधान...

माननीय पर्यावरण एवं वन मंत्रीः अध्यक्ष जी, सदन पटल पर.

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः एक सेकेंड संजीव जी, माननीय मंत्री जी कुछ बोल रहे हैं।

माननीय पर्यावरण एवं वन मंत्रीः सदन पटल पर मैं दो कागज रखना चाह रहा हूं क्योंकि विजेन्द्र जी की उसमें कोई गलती नहीं है क्योंकि उनको वही नोटिंग की कापी दी गई। नोटिंग की कापी से पेड़ नहीं कटते। ये जब एलजी साहब के दौरे के बाद मौखिक आदेश पर जब पेड़ कटवा दिये गये, डीडीए ने काट दिये अवैध तरीके से जिसकी स्वीकारोक्ति सुप्रीम कोर्ट में डीडीए के इंजीनियर ने दी उसके बाद ये ट्री आफिसर का नोटिस है इल्लीगल पेड़ काटने के लिए डीडीए को

दिया गया। ट्री आफिसर ने जो है 5 मार्च, 2024 को ये नोटिस दिया डीडीए को कि आपने इल्लीगल पेड़ काटे हैं इसका जवाब दीजिए, ये दिया श्री पंकज वर्मा, चीफ इंजीनियर, साउथ जोन, डीडीए को। उसके बाद उन्होंने जवाब नहीं दिया। फिर दोबारा 22 मार्च को ये नोटिस उनको दिया कि आपकी तरफ से अभी भी इल्लीगल तरीके से पेड़ काटने के लिए कोई जवाब नहीं आया है अब इस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी और फिर भी डीडीए ने नहीं दिया और इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट में सारा मुकदमा शुरु हुआ। मैं चाहता हूं कि रिकार्ड के लिए दोनों कागज सदन के पटल पर रख दिये जाएं।

माननीय शहरी विकास मंत्री (श्री सौरभ भारद्वाज): सर एक बार और विजेन्द्र जी से पूछ लीजिए अगर ये रखना चाहते हैं तो।

श्री विजेंद्र गुप्ता: हां मैं कहना चाहता हूं।

माननीय पर्यावरण एवं वन मंत्री: नहीं रखना है कागज रखो, कहने को तो आप कुछ भी कहोगे, कागज लाओ आप।

...व्यवधान...

श्री विजेंद्र गुप्ता: इनको कहा पेड़ काटो।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्ष: सौरभ जी विषय को मत बढ़ाओ, सौरभ जी।

श्री विजेंद्र गुप्ताः ..मैं कोई गलत नहीं कह रहा हूं क्योंकि 2200 करोड़ रुपये...

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः वो अपनी बात पर अडिग रहेंगे। चलिए, विजेन्द्र जी बैठिये, विजेन्द्र जी बैठिये।

माननीय पर्यावरण एवं वन मंत्रीः विजेन्द्र जी हास्पिटल, मेडिकल जो कुछ है उसके लिए रोड बनना चाहिए वो बात सत्य है ठीक है न, सुनिये।

श्री विजेंद्र गुप्ताः वो नहीं चाहते..

माननीय पर्यावरण एवं वन मंत्रीः सुनिए, न, हम चाहते हैं।

श्री विजेंद्र गुप्ताः नहीं चाहते आप।

माननीय पर्यावरण एवं वन मंत्रीः लेकिन फार्म हाउस को छोड़कर..

...व्यवधान...

माननीय पर्यावरण एवं वन मंत्रीः न,

श्री विजेंद्र गुप्ताः ..... जब मुख्यमंत्री ने साइन कर दिये, एलजी ने साइन कर दिये..... फिर रह क्या गया..

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्ष: चलिए अब, ठीक है।

...व्यवधान...

माननीय पर्यावरण एवं वन मंत्री: विजेन्द्र जी फिर आप फंस रहे हो खुद ही।

...व्यवधान...

माननीय पर्यावरण एवं वन मंत्री: आप पहले समझ लो।

...व्यवधान...

श्री विजेंद्र गुप्ता: ..आपकी अप्रूवल नहीं होती तब आप कहते, आपके साइन नहीं होते तब आप कहते...

...व्यवधान...

श्री विजेंद्र गुप्ता: ...आपके साइन चाहिए बस.

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्ष: ये विषय आज के सारे रह जाएंगे।

...व्यवधान....

श्रीमतीराखी बिरला: एक सेकेंड से ज्यादा नहीं सर।

माननीय अध्यक्षः भई माननीय मंत्री जी बोल रहे हैं, पहले मंत्री जी की तो बात पूरी होने दो।

श्रीमती राखी बिरलाः मैं मंत्री जी के विषय पर ही बोल रही हूं। मैं कल से सदन में देख रही हूं, बहुत गलत परंपरा ये विजेन्द्र गुप्ता जी के माध्यम से स्थापित की जा रही है। मंत्रियों से प्रत्यक्ष तौर पर वन टू वन कनवर्सेशन कर रहे हैं, मुझे लगता है इन्हें सदन की गरिमा की जरा सी भी लिहाज नहीं है, ये बिलकुल सम्मान नहीं करते हैं। जो भी बात इन्हें करनी है आपसे करें, चेयर को संबोधित करें। आप दूसरी बार लीडर ऑफ अपोजिशन बनें हैं थोड़ा तो सम्मान कर लो अपनी कुर्सी का, थोड़ी तो मर्यादा रख लो, इन्हें शर्म ही..

माननीय अध्यक्षः चलिए बैठिये-बैठिये।

श्रीमती राखी बिरलाः नहीं सर इन्हें शर्म ही नहीं है। कल से लगे हैं लगातार गोपाल राय जी से डायरेक्ट प्रत्यक्ष तौर पर बात कर रहे हैं

माननीय अध्यक्षः बैठिये, हो गई।

श्रीमती राखी बिरलाः इनको प्रिविलेज में भेजो और ये अगर आपने दोबारा करा तो मैं इनके खिलाफ फिर कानूनी कार्रवाई करूंगी। ये मंत्रियों का अपमान नहीं सहेंगे हम और अपने पद की भी गरिमा रखो। अभी भी बेशर्मों की तरह आप हंस रहे हो, शर्म नाम की चीज ही

नहीं रह गई है। सारी गरिमा, सारा सदन का सम्मान तहस-नहस हो रहा है।

...व्यवधान....

माननीय अध्यक्षः भई अब हो गई न बात।

श्रीमती राखी बिरलाः बेहद अपमान जनक स्थिति है कल से।

माननीय अध्यक्षः बैठिये-बैठिये प्लीज बैठिये, माननीय मंत्री जी।

माननीय पर्यावरण एवं वन मंत्रीः माननीय अध्यक्ष जी, मैं केवल इस बात को चूंकि सदन में कल चर्चा हुई थी। सदन में फैक्ट सामने रखना चाहिए। मैं एक बार फिर सदन को आपके माध्यम से अवगत कराना चाहता हूं दिल्ली के अंदर जो एक्ट है 'ट्री कटिंग एक्ट' है उसके तहत ट्री आफिसर की परमीशन के बगैर कोई एक पेड़ भी नहीं काट सकता, एक बात। दूसरी बात, इसलिए मैंने कहा था कि ट्री आफिसर का दिल्ली में एक नहीं सेंटर गवर्नमेंट के बहुत बड़े-बड़े प्रोजेक्ट के काम हुए हैं। स्टेट गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट के काम हो रहे हैं। लोगों को व्यक्तिगत भी बहुत सारे पेड़ कटिंग हुई है लेकिन एक बार विजेन्द्र गुप्ता जी जो हमारे नेता, प्रतिपक्ष हैं आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं इसको चैक कर लें क्योंकि जानकारी पूरी रहनी चाहिए। दूसरी बात, कि अगर परमीशन है, सदन में कल चर्चा हुई आप एक बार पूछ लें, नहीं है तो कोई बात नहीं, नहीं है, हमारे पास जो डाक्यूमेंट था वो हमने सदन के पटल पर रख दिया, थैंक यू।

माननीय अध्यक्षः धन्यवाद, आज कई बहुत महत्वपूर्ण विषय हैं। 280 आज भी मैं माननीय सदस्यों से क्षमा चाहते हुए, पढ़ा हुआ माना जा रहा है। आज 10 लोगों के नाम लॉट ऑफ ड्रा में आये हैं अभय वर्मा जी, हाजी युनूस जी, जयभगवान जी, अजय महावर जी, विजेन्द्र गुप्ता जी, अखिलेश पति त्रिपाठी जी, राजेश जी, नरेश यादव जी, अनिल कुमार बाजपेयी जी, ओमप्रकाश जी।

...व्यवधान....

माननीय अध्यक्षः श्री दिलीप पांडे जी, माननीय मुख्य सचेतक निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

...व्यवधान....

श्री दिलीप पांडे (मुख्य सचेतक): बहुत–बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय,..

...व्यवधान....

श्री विजेंद्र गुप्ताः अध्यक्ष जी, मैंने एक.

...व्यवधान....

श्री दिलीप पांडेः इस धन्यवाद प्रस्ताव को सदन पटल पर रखने की अनुमति देने के लिए।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः मैंने जो विषय लिये हैं अभी आपके सामने आ जाएंगे सब इश्यू।

श्री विजेंद्र गुप्ताः ..पहले ये तो बताईये।

माननीय अध्यक्षः क्या बताउं?

...व्यवधान....

श्री विजेंद्र गुप्ताः ये ग्राउंड वाटर जो सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड है उसकी रिपोर्ट गोपाल राय जी के पास 1 महीने से है, उसको दबाया हुआ है इन्होंने।

माननीय अध्यक्षः चलिए कोई बात नहीं।

...व्यवधान....

श्री विजेंद्र गुप्ताः और दिल्ली का जो कंटेमिनेशन हो रहा है वॉटर का..

माननीय अध्यक्षः अभी बहुत रिपोर्टें आ रही हैं।

श्री विजेंद्र गुप्ताः अध्यक्ष जी सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड की रिपोर्ट कहां गायब कर दी?

माननीय अध्यक्षः विजेन्द्र जी बैठिये आप, प्लीज विजेन्द्र जी।

श्री विजेंद्र गुप्ताः दिल्ली के ग्रांउड वाटर के 80 परसेंट सैंपल फेल हो गये।

माननीय अध्यक्षः विजेन्द्र जी बैठिये, ये माइक बंद करें, विजेन्द्र जी बैठिये प्लीज।

...व्यवधान....

माननीय अध्यक्षः बैठिये।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः अभी विषय आने वाला है। श्रीमान दिलीप पांडे जी।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः बैठिये अब, बैठिये आप बैठिये प्लीज, विजेन्द्र जी बैठिये प्लीज। हां बैठिये, कोई बात नहीं मैंने जो लेने थे वो विषय ले लिये।

...व्यवधान...

श्री दिलीप पांडेः अध्यक्ष महोदय, आप निर्देशित करें आदरणीय विजेन्द्र जी को कि वो अपना स्थान ग्रहण करें। मेरे..

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः देखिये विजेन्द्र जी ये हर रोज का नहीं मैंने जो विषय लेने थे ले लिये बैठिये आप।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः अभी विषय आएंगे आपके सामने, अभी विषय आएंगे आपके सामने। चलिए दिलीप पांडे जी, बताईये।

...व्यवधान...

श्री दिलीप पांडेः धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं यह प्रस्ताव..

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः दिलीप पांडे जी जहां ध्यान दिलवा रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण विषय रहा है। इसको एक बार..

...व्यवधान...

श्री ओमप्रकाश शर्माः अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः नहीं ओमप्रकाश जी आप भी परेशान रहें, मैं भी परेशान रहा हूं दो मिनट बैठ जाईये।

श्री दिलीप पांडेः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहूंगा कि मुझे बोलने का अवसर मिला है, बोलने का अवसर तो मिला है बोलने का वातावरण भी मिल जाए आपके निर्देश से बहुत–बहुत धन्यवाद।

...व्यवधान...

धन्यवाद प्रस्ताव

श्री दिलीप पांडे: इस विधानसभा के सभी साथी इस बात से सहमत होंगे दिल्ली के अंदर जो विधवा पेंशन आती थी, जो बुजुर्गों की पेंशन आती थी एक समय था कि लगातार वो पेंशन मिला करती थी और दिल्ली के बुजुर्ग, दिल्ली की विधवाएं, दिल्ली के सभी लोग जो इस पेंशन के ऊपर आश्रित थे वो दिल्ली की सरकार का हमेशा आभार व्यक्त किया करते थे लेकिन 6 महीने पहले जो बुजुर्गों की पेंशन आती है, वृद्धावस्था पेंशन जो आती है उसमें एक आईजी पेंशन होती है जिसका एक अंश 300 रुपये का महज 300 रुपये का 2500 रुपये में से 300 रुपये का अंश केन्द्र की सरकार से मिलता है और बाकी 2200 रुपये दिल्ली की सरकार उसका हिस्सा देती है। मतलब कलुषित मन की बात करें या गलत किस्म की सियासत की बात करें जो भी वजह रही हो, केन्द्र की सरकार ने 6 महीने पहले लगभग वो 300 रुपये का जो अंशदान है उनका उसे रोक लिया जिसकी वजह से पूरी की पूरी पेंशन दिल्ली के तकरीबन एक लाख बुजुर्गों की पेंशन जो है रुक गई और दिल्ली की सरकार का हस्तक्षेप हुआ और वो पेंशन दोबारा आनी शुरु हुई। इस विषय पर मैं ये धन्यवाद प्रस्ताव सदन के पटल पर रखना चाहता हूं कि यह सदन केन्द्र सरकार द्वारा अपना निर्धारित अंश न देने के कारण आईजी पेंशन योजना के लाखों लाभार्थियों की 6 माह से लंबित पेंशन को अथक प्रयासों से जारी करवाने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के प्रति अपना धन्यवाद ज्ञापित करती है, धन्यवाद।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः विजेन्द्र जी 2 मिनट देता हूं मैं समय। 2 मिनट, अभी मैं समय देता हूं। दिलीप पांडे जी ने जो प्रस्ताव रखा है, धन्यवाद प्रस्ताव पिछले 2 सालों से बुजुर्गों की पेंशन और विडो पेंशन जिसका केन्द्रीय सरकार कुछ पेंशन का हिस्सा देती है। विडो पेंशन 35 हजार हैं कुल दिल्ली में और लगभग इससे डबल ओल्ड ऐज पेंशन हैं 6 महीने से रुकी हुई थीं और रुकी केवल इस कारण थी कि केन्द्रीय सरकार का हिस्सा उसमें नहीं आ रहा था। दिल्ली सरकार डायवर्ट करके फंड उसमें दे रही थी बराबर लेकिन पिछले 6 महीने से वो रुकी पड़ी थी विडो पेंशन भी 35 हजार रुकी पड़ी थी अल्टीमेटली अब जाकर के 3 दिन पहले निर्णय हुआ कि 2500 की बजाय उनको 2200 रुपया उनका रिलीज कर दिया जाए। अब भी 300 रुपया केन्द्रीय सरकार का उनका बाकी है ये दिलीप पांडे जी का प्रस्ताव है विजेन्द्र जी इस पर कुछ कहना चाहते हैं उनको मैं।

श्री विजेंद्र गुप्ताः अध्यक्ष जी, इसी में एक विषय मैं और जोड़ना चाहता हूं अगर दिल्ली की सरकार उस पर निर्णय ले ले तो हम भी इस सरकार का धन्यवाद कर पाएंगे। 2014 के बाद,2014 में जब अरुण जेटली जी फाइनेंस मिनिस्टर थे तब लगभग 50 हजार नई पेंशन शुरु हुई थीं। उसके बाद कुछ छोटा-मोटा हुआ तो मैं कह नहीं सकता लेकिन 2018 के बाद एक भी बुजुर्ग को दिल्ली के नई पेंशन शुरु नहीं की गई है और ये एक बहुत बड़ी बात है कि 5-6 साल से जो बुजुर्ग

दर–दर की ठोकरें खा रहे हैं उनको सरकार किसी भी रुप में बजट में भी कोई प्रावधान नहीं रख रही है कि उनको पेंशन दी जाए। हमारा कहना है कि आप नई पेंशन नहीं जोड़ पा रहे या जोड़ना चाहते हैं लेकिन इस दौरान जो वैंकेसीज हुई हैं, जो पेंशंस जो हैं जो बुजुर्ग गुजर गये हैं या दिल्ली छोड़कर लोग चले गये हैं दूसरी जगह अगर हम वो लगभग 50 हजार से ज्यादा लगभग 1 लाख के करीब जो मेरे पास जानकारी है, पूरी जानकारी मेरे पास नहीं है..

लेकिन एक लाख नई पेंशन उस वेकेंसी से भी शुरू की जा सकती है। सरकार ने उस पर भी उसमें न बजट बढ़ाने की जरूरत है, न बजट जो़ड़ने की जरूरत है, तो हमारा ये कहना है कि बुजुर्गों की पेंशन जो है वो दिल्ली में जल्द से जल्द शुरू की जाये जिससे कि दिल्ली के बुजुर्गों को ये पेंशन मिल सके। और दूसरा, सरकार जो आज अपनी पीठ थपथपा रही है उस पर मेरा ये कहना है साफ साफ कि जब 2200 आप दे रहे हैं तो इस पर राजनीति न करें और आप पूरे 2500 सौ दें। ये तो सरकारों में लेनदेन चलता रहता है लेकिन अगर आप उसको नहीं दे रहे हैं, सरकार में बजट आते जाते रहते हैं तो उसको एक राजनीतिक मुद्दा बनाने की बजाये अगर आप पूरे 2500 रूपये दें और अभी तक आपने क्यों रोके हुए थे ये भी हम जानना चाहते हैं। इतने वर्षों से क्यों रोक रखे थे आपने, पिछले 6 महीने से.

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः एक सेकिंड भई।

...व्यवधान...

श्री विजेंद्र गुप्ताः उनको पेंशन क्यों नहीं दी। तो ये हमारा कहना है। ये कैमरा क्यों बंद कर दिया भई। कैमरा क्यों बंद कर दिया।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः किसने बंद कर दिया।

श्री विजेंद्र गुप्ताः ये कैमरा बंद कर दिया, कैमरा क्यों बंद कर दिया?

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः वो अंदर से कोई गड़बड़ हुआ होगा, हर बात पे कोई।

श्री विजेंद्र गुप्ताः कैमरा क्यों बंद कर दिया भई?

माननीय अध्यक्षः कैमरा उनके कंट्रोल में नहीं है। कोई गड़बड़ हुआ होगा विजेंद्र जी, विजेंद्र जी, कैमरा बंद जानबूझ के नहीं किया जाता, यहां ऐसा कोई डायरेक्शन नहीं है।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः वो कैमरा किसी, हो गया चालू। पीठ थपथपा रहे हैं।

...व्यवधान...

श्री विजेंद्र गुप्ताः मैं अपनी बात को दोहरा देता हूं।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः वो हो गया आपकी बात समझ में आ गयी।

श्री विजेंद्र गुप्ताः रिकॉर्ड पे नहीं आई न अभी। अब आपने परमिशन दी है।

माननीय अध्यक्षः रिकॉर्ड में आ गयी आपकी आवाज रिकॉर्ड में आ गयी।

श्री विजेंद्र गुप्ताः हमारा इतना कहना है कि 2018 से जो पेंशन बंद है वो शुरू होनी चाहिये, नये बुजुर्गों को जो उनका हक है वो उनका छीना जा रहा है। जो आप नयी पेंशन नहीं शुरू कर पा रहे तो वेकेंसीज़ जो हुई हैं एक लाख के करीब, उनको आप रिफिल कर सकते हैं, वो करिये। बाईस सौ रूपये ये सब सरकारों में लेनदेन होता रहता है आप पूरे 2500 रूपये दीजिये। अभी तक आपने ये भी क्यों रोके हुए थे, ये भी एक बड़ा विषय है कि 6-8 महीने से बुजुर्ग जो है बिना पेंशन के जो है वो परेशान थे बुजुर्ग, दवाई नहीं ले पा रहे थे। हमारा आपसे अनुरोध है कि आप पूरे 2500 रिलीज कीजिये।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः वो सच्चाई को मानेंगे नहीं।

श्री विजेंद्र गुप्ताः ये लेनदेन जो हैं ये होता रहता है इसको आप मुद्दा न बनाये। धन्यवाद।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः अभी एक सेकिंड। पहले राखी जी बोल रही हैं उनका आया है। हां राखी जी।

श्रीमती राखी बिरलाः बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी।

माननीय अध्यक्षः संक्षेप में बोलियेगा, ये विषय,

श्रीमती राखी बिरलाः मुझे ऐसा लगता है, हां मैं विषय पर ही हूं। मुझे ऐसा लगता है न विजेंद्र गुप्ता जी ने ठेका ले रखा है सरकार को और सदन को गुमराह करने का। सारी की सारी झूठी बातें सदन पर रखते हैं और इनके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिये प्रिविलिज के तहत, पहला विषय। ये जो बात कर रहे हैं 2018 वाली इसको इन्होंने आधा ही बताया है जबकि पूरी बात ये है कि 4 लाख 90 हजार पर केंद्र सरकार ने बुजुर्गों की पेंशन पर कैपिंग कर रखी है। चार लाख 90 हजार से उपर दिल्ली सरकार बुजुर्गों की नई पेंशन लगा ही नहीं सकती। ये इतने बुजुर्गों के हितैषी हैं, ये बुजुर्गों के बारे में इतना सोच रहे हैं, इन्होंने माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में जो दिल्ली सरकार ने तीर्थ यात्रा योजना चलाई थी उसको बंद करा, जो आज बुजुर्गों के लिये घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं और जैसा कल सौरभ भारद्वाज जी ने कहा और मैं पूरे अपने मंत्रीमंडल और अपने मुख्यमंत्री

जी और आम आदमी पार्टी की तरफ से इन्हें कहना चाहती हूं कि आप चलें केंद्र सरकार के पास, आप चलें केंद्र सरकार के पास और इस एप्लीकेशन को आपके नेतृत्व में हम फॉलो करेंगे कि इसको 4 लाख 90 हजार की कैपिंग को हटाकर 5 लाख, 10 लाख करा जाये, हम आपका साथ देंगे। तो सिर्फ ये अगर सदन का प्रयोग झूठी बयानबाजी के लिये करेंगे, अगर ये सदन का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक भाषणों के लिये करेंगे तो इस पर ये मेरी कड़ी आपति है, पहली बात। और जो ये कह रहे हैं कि सरकारों का लेनदेन चलता है, सरकारों का लेनदेन चलता है लेकिन हमेशा दिल्ली के साथ केंद्र सरकार सौतेला व्यवहार करती है। दिल्ली के लोग, दिल्ली की सरकार सबसे ज्यादा टैक्स जो है केंद्र में देती है लेकिन हर बार हमारे हिस्से के अंदर सिर्फ और सिर्फ चंद पैसे आते हैं। और अब इन्होंने हालत ये कर दी है विधवा बहन बेटियां हो, हमारे बुजुर्ग मां बाप हों, विकलांग लोग हों, इतनी इनकी जो राजनीति में खिसियानी बिल्ली की तरह खंबा नोचने की स्थिति हो गयी है कि 300 रूपये का जो महज इनका हिस्सा है जोकि उंट के मुंह में जीरे जैसा है, उसको भी रोककर ये षडयंत्र के तहत अरविंद केजरीवाल जी की सरकार को और आम आदमी पार्टी की सरकार को जो है बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं।

माननीय अध्यक्षः चलिये।

श्रीमती राखी बिरलाः अध्यक्ष जी, मैं सिर्फ आपके माध्यम से इतना कहना चाहती हूं कि वास्तव में अगर आप दिल्ली के बुजुर्गों के बारे में सोच रहे हैं और उनके हितैषी बन रहे हैं तो इधर उधर की

बात न कर कर आपके माध्यम से ये सदन को जवाब दें कि ये कब केंद्र सरकार को, वित मंत्री को पत्र लिख रहे हैं, एलजी साहब को पत्र लिख रहे हैं कि 4 लाख 90 हजार की कैपिंग को हटा कर इसे कम से कम 10 लाख किया जाये ताकि हरेक बुजुर्ग को उसका हिस्सा मिल सके, उसका हक मिल सके क्योंकि कोई भी सरकार बुजुर्गों पे अहसान नहीं करती, उनका अधिकार है, वो पूरा उम्र टैक्स भरते हैं और जब अंत में उन्हें आर्थिक सुविधा की जरूरत होती है तो वो आर्थिक सुविधा तो देने की बात दूर की है, कोई और सरकार अगर उनके सपनों को पूरा कर रही है, तीर्थ यात्रा करवा रही है तो ये एलजी के माध्यम से अपनी इतनी घिनौनी मानसिकता का परिचय बुजुर्गों के लिये देते हैं कि उनकी तीर्थ यात्रा को ही बंद करवा देते हैं।

माननीय अध्यक्षः बैठिये, बैठिये प्लीज।

श्रीमती राखी बिरलाः तो जरूर ये जवाब मांगियेगा और मैं फिर इनको आगाह करना चाहती हूं कि सदन के अंदर राजनैतिक भाषण और झूठा जो है अपना बयानबाजी बंद करें नहीं तो प्रिविलिज के माध्यम से इनके उपर एक्शन सुनिश्चित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः राजेश जी एक सेकिंड। हां। बोलिये बोलिये।

श्री जितेंद्र महाजनः माननीय अध्यक्ष जी, राखी बिडलान जी ने जो बात कही है मैं भी सदन को चुनौती देता हूं कि सदन में जो 2018 से सदन को नहीं, उनके बयान को..

...व्यवधान...

श्री जितेंद्र महाजन: सदन में जो राखी बिडलान जी ने कहा है उस बात पर मैं ये कहना चाहता हूं कि जो कैपिंग की बात कर रहे हैं ये 2018 से अब तक जो एलओपी हमारे आदरणीय विजेंद्र जी ने कहा है एक लाख लगभग वैकेंसी खाली हैं जो बुजुर्गों के देहांत हो गया, उसको फिलअप नहीं किया गया है। उसको किस आधार पर रोका जा रहा है। दूसरी बात..

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्ष: राखी जी आप मुझ से बात करिये।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्ष: राखी जी।

...व्यवधान...

(समय की घंटी)

...व्यवधान...

श्री जितेंद्र महाजन: एक लाईन और। एक बार जो इन्होंने कहा कि योजनाओं का पैसा..

माननीय अध्यक्ष: राखी जी प्लीज।

श्री जितेंद्र महाजनः योजनाओं का जो पैसा जो लेनदेन होता रहता है आप बताईये आईटीओ का अंडरपास बना 20 परसेंट रेवेन्यू पैसा दिल्ली सरकार को देना था, क्या अब तक दिया क्या?

माननीय अध्यक्षः चलिये मैं इस विषय पर अभी मैं अभी या तो हो सकता है जवाब दें, मैं बात करता हूं।

श्री जितेंद्र महाजनः नहीं दिया। उसका पैसा भी नहीं दिया।

माननीय अध्यक्षः हां राजेश जी बताईये।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः एक सेकिंड भाई, कुलदीप कुमार जी प्लीज, राजेश जी।

...व्यवधान...

श्री राजेश गुप्ताः अध्यक्ष जी बहुत ही गंभीर विषय पर ये बात हो रही थी लेकिन इसमें भी हर बार की तरह राजनीति। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं क्योंकि आप इन बातों को वैसे अच्छी तरह जानते हैं कि दिल्ली नगर निगम भी बुजुर्गों को पेंशन दिया करती थी। इन्होंने वो पेंशन बिल्कुल देनी बंद कर दी, इनका कोई मैनडेट नहीं था पेंशन देने का फिर भी ये पेंशन लगाते थे और इतनी बेइज्जती करते थे बुजुर्गों की ये एक ऐसी कापी सी छोटी सी देते थे, अपने पास बुजुर्ग को बुलाते थे और उसको पेंशन देते थे।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः भई या तो बीच में बोलो नहीं। अब वो विषय को ठीक रख रहे हैं आप रखने नहीं दे रहे उनको। चलिये।

श्री राजेश गुप्ताः इस तरीके से कि बेइज्जती के साथ जो पेंशन दी जाती थी उन बुजुर्गों की फोटो खिंचाई जाती थी, उनकी वीडियो बनाई जाती थी कि हम आपको मैं शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता जैसे भीख दी जाती है ऐसे पेंशन देते थे। इनको तकलीफ नहीं होती थी उस पे राजनीति करते थे, मैनडेट नहीं था इनका, मैनडेट बिल्कुल नहीं था निगम का ये काम करने का, ये काम करते थे। जब इन्होंने पेंशन देनी बंद कर दी बिल्कुल तो दिल्ली सरकार ने वो सारी पेंशन ले ली तो राखी बहन वो जो आप 4 लाख 90 हजार बता रहे हो उनमें से इनकी निगम की पेंशन भी थी जो इन्होंने लगाई थी जो हम देते हैं। आप नहीं दे रहे हो उसमें से एक पैसा भी, हमने दी वो पेंशन। उसके बाद में दिल्ली नगर निगम की तनख्वाह भी नहीं दे पाये वो भी आज एक तारीख को हमारे सारे कर्मचारी भाईयों को वो तनख्वाह हम दे पाते हैं आप कुछ नहीं कर पाते और आपने भी एक बात कही, मैं बहुत छोटे में रखना चाहता हूं ज्यादा लंबे की जरूरत नहीं है, आपने कहा कि तीन सौ रूपये भी हम दे दें, अरे हम तो बहुत कुछ दे ही रहे हैं मेरे भाई, हम तो बाहर घुमाते हैं जो आप तीन लाख में नहीं करवा पाओगे हम घुमा रहे हैं। हम लोग तीर्थ यात्राएं करवा रहे हैं। हम आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं आप इस बात को आन रिकॉर्ड रख दो अभी

जाके बाहर एक बयान दे दो कि हम तीन सौ रूपये नहीं दे सकते मैं अपनी सरकार की तरफ से, सदन की तरफ से वादा करता हूं तीन सौ हम दे देंगे। आप बोल दो बस एक बार, हमारे पल्ले नहीं हैं, हमारे बस का कुछ नहीं है ये काम भी हम कर देंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और विजेंद्र जी कल को कोई लाल बत्ती रास्ते में पड़ जाये ये मत कहना स्पीकर साहब ने बंद करा दी। लाल बत्ती भी आती हैं।

माननीय अध्यक्षः चलिये बैठिये राजेश जी बैठिये अब।

श्री राजेश गुप्ताः बेकार की बातें मत करो।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः बैठिये बैठिये। देखिये माननीय विजेंद्र जी, विजेंद्र गुप्ता जी, विजेंद्र जी आप बहुत सीनियर लीडर हैं, आप सब चीजों को समझते हैं, आपने कहा कि 2500 रूपये दे सकते थे, जब तक फाईनेंस सेक्रेटरी इजाजत देते रहे फंड डायवर्ट करने की, बजट में 2200 रूपये के हिसाब से फंड एलोकेशन होता है, बजट ये सदन पास करती है जिसके आप भी हिस्सेदार हैं number of pensions into 2200 रुपया ये बजट पास होता है एवरी इयर, उस बजट को डायवर्ट करना, ये फाईनेंस के.

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः नहीं सुन लीजिये बात को ऐसे नहीं, मैं टेक्निकल बात बता रहा हूं। वो तीन सौ रूपया फंड डायवर्ट किया जाता है। जब

तक डायवर्ट होता रहा देते रहे, अब डायवर्ट करने से मना कर दिया तो डिसीजन ये लिया..

...व्यवधान...

श्री विजेंद्र गुप्ता: वो पैसा तो अभी आया नहीं आपके पास।

माननीय अध्यक्ष: अभी नहीं आया अभी नहीं, अभी नहीं आया। आयेगा तो, नहीं ऐसे आपको उचित नहीं लगता, चलिये।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्ष: ये धन्यवाद प्रस्ताव सदन के सामने है,

जो इसके पक्ष में हैं हां कहें

जो इसके विरोध में हैं न कहें

(माननीय सदस्यों के हां कहने पर)

धन्यवाद प्रस्ताव पारित हुआ ।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्ष: ध्यानाकर्षण नियम 54 श्री संजीव झा जी छठ पूजा पर पहले की तरह यमुना नदी के घाटों पर आयोजित करने के संबंध में माननीय मंत्री का ध्यानाकर्षित करेंगे।

ध्यानाकर्षण (नियम 54)

श्री संजीव झा: बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय कि आपने मुझे सदन का और माननीय मंत्री जी का ध्यानाकर्षण करने का अवसर दिया। चूंकि ये मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है उसपे मैं आउंगा। क्योंकि कैमरे को बंद करने को लेकर अभी सदन में हल्ला हो गया।

माननीय अध्यक्ष: छोड़ो उस चीज को प्लीज।

श्री संजीव झा: पर चूंकि ये संसद ने एक परम्परा अभी एस्टेब्लिश किया है कि विपक्ष के लोगों को नहीं दिखाया जायेगा, संसद एस्टेब्लिश किया है ये हमारा कल्चर नहीं है।

माननीय अध्यक्ष: अब राखी बिरला जी के उसमें भी कैमरा बंद हुआ है।

श्री संजीव झा: दूसरी बात, अध्यक्ष महोदय, कि छठ पूजा पूर्वांचल की आस्था का सबसे बड़ा महापर्व है और दिल्ली में जो पूर्वांचलवासी हैं वो छठ पर्व बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। 2020 से पहले दिल्ली में जितने यमुना के घाट हैं सभी यमुना के घाटों पर छठ पूजा मनाया जाता था, खूब धूमधाम से मनाया जाता था। हालांकि इसमें मैं अपनी सरकार को, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार को मैं धन्यवाद भी करता हूं कि हमारे आने से पहले केवल 68 जगहों पर सरकार छठ पूजा का आयोजन करती थी, अब वो बढ़कर एक हजार जगहों पर छठ पूजा का आयोजन होता है। लेकिन 2020-21 में कोरोना के कारण एक

नोटिफिकेशन डीडीएमए ने निकाला और कहा कि महामारी होने के कारण यमुना के किनारे छठ पूजा का आयोजन नहीं होगा। पूर्वांचलवासी चूंकि छठ पूजा साफ सफाई का पूजा है और ला अबाईडिंग सिटिजन हैं हमने इस बात को स्वीकारा, चूंकि भीड़ बहुत होती है और लाखों लोग यमुना के घाट पे आते हैं तो सबने ये माना कि कोरोना की महामारी में ये छठ पूजा का आयोजन यमुना के घाट पे न हो जब तक कोरोना है। लेकिन 2023 में यमुना के घाटों पर छठ पूजा का आयोजन नहीं हो पाया। अब यमुना के जितने भी घाट हैं वहां लाखों की संख्या में लोग आते हैं, छठ पूजा का आयोजन करते हैं। अब इससे दो नुकसान हुए एक, कि बहुत सारे लोगों को अपने-अपने घर जाना पड़ा और हर बार छठ में जो रेलवे में और न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन में जो भीड़-भाड़ आप देखते हैं वो उसमें और बढ़ गई और उनमें कई बार हादसे भी होते हैं। देखिये हम ये मानते हैं कि जब कोई भी चाहे पूर्वांचल के लोग हों या कहीं से जो दिल्ली में आए हैं, ऐसा नहीं है कि बोरिया बिस्तर लिया और यहां आया, वो अपने साथ अपनी संस्कृति, अपनी रीति-रिवाज, अपनी भाषा, अपने संस्कार सब साथ लेकर आया। हमारी सरकार ने ये इन्श्योर किया की उनकी संस्कृति, उनकी भाषा, उनकी रीति-रिवाज, उनकी परम्परा, उनका पर्व सब संरक्षित रहे। लेकिन डीडीएमए के उस नोटिफिकेशन के कारण 2023 में पूजा नहीं हो पाया। तो मैं सदन के माध्यम से माननीय रेवेन्यू मिनिस्टर को भी और माननीय एलजी साहब को भी, एलजी साहब को इसलिए चूंकि डीडीएमए का चेयरमेन एलजी साहब हैं और ये नोटिफिकेशन डीडीएमए के द्वारा

निकाला गया है। तो मैं एलजी साहब का भी ध्यानाकर्षण इस सदन के माध्यम से कराना चाहता हूं कि यमुना घाट पर जैसे पहले छठ पूजा होता रहा था, उसी तरह से इस बार भी पूजा हो। कई बार ये एक मिथक फैलाया जाता है कि नहीं छठ पूजा होगा तो प्रदूषण होगा। मैं सदन के माध्यम से सदन को भी और सभी concerned चाहे एलजी साहब हों, बाकी लोगों को भी मैं बताना चाहता हूं कि छठ पूजा में कोई विसर्जन नहीं होता, ये साफ-सफाई का पूजा है। लोग घर की साफ-सफाई करते हैं, नदियों की साफ-सफाई करते हैं। तो इसमें किसी तरह प्रदूषण नहीं फैलता और अगर इसी लोजिक को अगर बाई भी करें तो यही यमुना दिल्ली से पहले जहां-जहां है उसमें पूजा होता है, दिल्ली के बाद में जहां-जहां है वहां पूजा होता है। गंगा मईया के किनारे जितनी भी जगह हैं हर जगह पूजा होता है। तो अलग-अलग जगह के लिए अलग-अलग कानून नहीं होगा। तो मैं सदन के माध्यम से माननीय एलजी साहब को ये निवेदन करना चाहता हूं कि इस बार डीडीएमए का जो कोरेना के महामारी के समय में नोटिफिकेशन था, उस नोटिफिकेशन को कैंसिल किया जाए और पहले की तरह पूजा हो चूंकि दिल्ली में ही इसी यमुना घाट पर 2015 से हमारी सरकार है और खूब धूमधाम से हम पूजा कर रहे थे। तो उसमें नया कुछ तो नहीं आया है, तो आखिर फिर वो पूर्वांचल वासी यमुना किनारे जाकर धूम-धाम से पूजा करते थे, उनको किस कारण से वंचित किया जा रहा है। तो मैं आपके माध्यम से सदन का भी, माननीय मंत्री जी का भी और माननीय एलजी साहब का भी ये ध्यानाकर्षण चाहता हूं और निवेदन कर रहा हूं कि

अब इस बार का छठ फिर से यमुना के किनारे, चूंकि नदी के किनारे ही ये पर्व मनाया जाता है, तो यमुना मईया के किनारे छठी मईया की पूजा आराधना पहले की भांति हो, बस मैं यही सदन का और माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित कराना चाहता था, बहुत–बहुत धन्यवाद।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः भई मैं इस पर कोई अलाउ नहीं कर रहा हूं, प्लीज, भई बैठिए।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः नहीं रोहित जी, मैं इसमें किसी को अलाउ नहीं कर रहा हूं। ये चर्चा का विषय नहीं है, बैठिये प्लीज। माननीय मंत्री कैलाश गहलौत जी उत्तर देंगे।

...व्यवधान...

श्री दिलीप पाण्डेय (मुख्य सचेतक, सत्ता पक्ष): अध्यक्ष महोदय एक बहुत ही pressing matter आया है जिसपर मैं आपकी अनुमति चाहूंगा। ये ऐसा मुद्दा है जिसपर अगर आप अलाउ करें तो मैं दो मिनट अपनी बात रखना चाहूंगा, क्योंकि ये मुद्दा सीधे–सीधे संविधान.

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः मैं किसी को अलाउ नहीं कर रहा ना..

...व्यवधान...

श्री दिलीप पाण्डेयः संविधान की हत्या के बराबर है, लोकतंत्र की हत्या के बराबर है। एक ऐसा विषय जिसपर मैं चाहूंगा इस सदन का भी ध्यान जाए, आपका भी ध्यान जाए और अगर आप दो मिनट की मुझे अनुमति दें तो मैं अपनी बात रखना चाहूंगा।

माननीय अध्यक्षः बताइये।

श्री दिलीप पाण्डेयः अध्यक्ष महोदय बहुत अजीब सी घटना हो रही है, इस August House ने मुझे यहां से नोमिनेट किया है दिल्ली की एमसीडी के अंदर मैंबर के तौर पर। एमसीडी के अंदर स्टैंडिंग कमेटी के इलैक्शनस पेंडिंग है, कल एमसीडी का हाउस हुआ, उस हाउस को ओनरेबल मेयर ने preside किया और preside करने के बाद हाउस को formally, officially स्थगित करके 5 अक्तूबर की डेट मुकर्रर की गई, कि भई अब 5 अक्तूबर को चुनाव होंगे। लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी और उनके द्वारा नियुक्त किए गए एलजी साहब को संविधान का सम्मान नहीं है और इन लोगों ने मिलकर कल से लेकर के आज तक में लोकतंत्र का संविधान का और एमसीडी के कानून का सबका मजाक बना के रख दिया है। कल मैं खुद यहां हाउस खत्म होने के बाद एमसीडी गया, सिविक सैंटर गया, वहां मजाक चल रहा है। बातचीत ऐसी हो रही है कि अभी रात में 8 बजे चुनाव हो जाएगा, नहीं–नहीं अब 10 बजे चुनाव हो जाएगा और ये कहा जा रहा है कि एलजी साहब ने एक आदेश निकाल दिया है कि पहले मेयर को कहा

जाएगा, अगर वो preside नहीं करेंगे तो डिप्टी मेयर को कहा जाएगा और वो भी preside नहीं करेंगे अगर हाउस को तो किसी अधिकारी को बैठाकर हाउस को preside करवाया जाएगा और जबरन चुनाव कराए जाएंगे, ऐसी चर्चा की शुरूआत हुई। अभी–अभी की, थोड़ी देर पहले की बात है सुनने में आया है कि अभी एक बजे जबरदस्ती स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव करवाने की कोशिश की जा रही है। अब आप समझिए अध्यक्ष महोदय। अब आप इस बात को समझिए किये सबकुछ क्या हो रहा है। कल्पना करके देखिये आप कि इस देश की संसद के अंदर स्पीकर साहब को हटा दिया जाए और किसी आईएएस अधिकारी को कहा जाए या आईपीएस अधिकारी को कहा जाए, किसी सचिव को कहा जाए, किसी बाबू को कहा जाए किअब आप बैठिए और आप पार्लियामेंट चलाइये। हम इस ऐतिहासिक असेंबली के अंदर बैठे हुए हैं, आप कुर्सी पर विराजमान हैं और अचानक कोई आए लाट साहब बनकर और कहे कि कोई सचिव, कोई क्लर्क, कोई बाबू आप की कुर्सी पर बैठेगा और लोकतंत्र के इस मंदिर को चलाएगा, ये लोकतंत्र की हत्या है अध्यक्ष महोदय, संविधान की हत्या है और मेरे अधिकारों की हत्या है। डीएमसी एक्ट साफ–साफ कहता है, 1957 में डीएमसी एक्ट लिखा गया, 1958 में एमसीडी बनी और डीएमसी एक्ट के 76 सैक्शन के मुताबिक कोई भी नोन इलैक्टीड पर्सन preside नहीं कर सकता हाउस को, उसकी कुर्सी पर नहीं बैठ सकता, लेकिन ऐसा करवाने की कोशिश करके संविधान की, एक्ट की, एमसीडी की, कानून की मर्यादा की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है अध्यक्ष जी। और मैं उस एमसीडी का मैंबर

हूं, इस हाउस ने मुझे नोमिनेट किया है। मेरे अपने अधिकारों का हनन हो रहा है। इस देश में संविधान का सम्मान, लोकतंत्र का सम्मान करना भारतीय जनता पार्टी के व्यवहार की फैहरिश्त में नहीं है, उनके पोलिटिकल बिहेवियर की कॉपी में नहीं है। आज जो इस देश के अंदर किया जा रहा है, देश की राष्ट्रीय राजधानी के अंदर किया जा रहा है अध्यक्ष महोदय ये कल्पनातीत है, दुर्भाग्यपूर्ण है, दुखद है। इस हाउस में और भी मैंबर्स हैं, बंदना जी बैठी हुई है, प्रवीण कुमार जी बैठे हुए है, ये लोग भी उस एमसीडी के मैंबर हैं। इस हाउस ने नोमिनेट किया है, इनके अधिकारों का भी हनन हो रहा है और जबरन जो है एमसीडी के अंदर हाउस को एक क्लर्क के जरिये preside करा के और इलैक्शन को influence करने की कोशिश की जा रही है, जो सीधे–सीधे संविधान और लोकतंत्र की और एमसीडी के कानून की हत्या के बराबर है। मैं चाहूंगा इस हाउस में जो साथी एमसीडी के मैंबर हैं वो अपनी बात रखें, अपनी राय रखें। अध्यक्ष महोदय इस गम्भीर विषय पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया मैं आपका धन्यवाद व्यक्त करता हूं और मैं चाहता हूं कि इस विषय पर आप भी दो शब्द जरूर कहें क्योंकि ये, आप देखिये अगर पैनल ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे तो कल को ये सम्भव है कि इस हाउस में भी किसी क्लर्क को कहा जाए कि आपकी चेयर पर बैठे और इस हाउस को चलाएं। सम्भव है कि कल को कोई इस देश की पार्लियामेंट में किसी अधिकारी को, किसी क्लर्क को, किसी बाबू को बैठाया जाए और कहा जाए स्पीकर नहीं चलाएंगे वो क्लर्क चलाएगा इस देश की पार्लियामेंट, वो बाबू चलाएगा इस देश

की पार्लियामेंट। इस तरह के खतरों को हम पाल रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है इस देश के लिए, इस देश के लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, इस देश के संविधान के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, धन्यवाद।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः भई मैंने इजाजत नहीं दी है अभी।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः माननीय सदस्यों से प्रार्थना है आप बैठें, माननीय सदस्यों..

...व्यवधान...

श्री दिलीप पाण्डेयः माननीय अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय मेरा आग्रह है कि इस विषय पर दो शब्द आप भी जरूर कहें, धन्यवाद।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः माननीय सदस्यों से प्रार्थना है नीचे बैठें, सबसे पहले बंदना कुमारी जी खड़ी हुई थी, बंदना कुमारी जी अब..

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः नहीं बंदना जी खड़ी हुई हैं पहले, सबसे पहले बंदना जी खड़ी हुई थी, मैं देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं, मैंने देखा है, बंदना जी।

श्रीमती बंदना कुमारीः अध्यक्ष जी आपका धन्यवाद, इतने गम्भीर मुद्दे पर आपने हमें बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष जी आज तो मतलब हद ही हो गई। जो आज एमसीडी सदन के अंदर हो रहा है, जो किसी को नहीं पता, किसी भी, मैं भी वहां की विधायक के रूप में नोमिनेटिड इसी सदन ने हमें नोमिनेट किया है और मैं नोमिनेटिड वहां की एमएलए हूं और सदन की मैंबर हूं। सर जिस तरीके से आज एक डिसिजन सुना दिया गया जो एक बजे कोई अधिकारी बैठेंगे वहां पर और ये सदन को चुन लिया जाएगा, वहां मैंबर चुन लिया जाएगा और उसका चुनाव होगा। अध्यक्ष जी आज जिस तरीके से सभी अधिकारियों को अपने सिस्टम से नचाया जा रहा है, वो तो चल रहा है। एक-एक काम को रोड़ा डालना, एक-एक काम को प्रताड़ित करना, एक-एक काम को सिस्टम अपने। आज ही सुबह हमारे क्षेत्र में एक इतनी बड़ी घटना घटी, इतनी बड़ी घटना घटी एक मकान को बिना नोटिस, बिना सिस्टम के तोड़ दिया गया, तोड़ दिया गया और कोई सूचना नहीं, सबसे पता है, सारे सिस्टम से चल रहा है।

माननीय अध्यक्षः बंदना जी आप विषय से अलग जा रही हैं।

श्रीमती बंदना कुमारीः मैं सर इसलिए कह रही हूं।

माननीय अध्यक्षः जो विषय रखा है।

श्रीमती बंदना कुमारीः जो आज जिस तरह से सदन की धज्जियाँ उड़ाई गई, ऑफिसर के माध्यम से इस सिस्टम को चलाने की कोशिश की जा रही है। हम चुने हुए प्रतिनिधि कुछ भी नहीं है। हम चुने हुए

साथी जो चुनकर आते हैं, जो संविधान के माध्यम से चुने हुए साथी हैं, लोगों की बात को रखते हैं, लोगों की हर बात को सुनते हैं और लोगों के काम को करवाते है। आज हम सबके अधिकार को जिस तरीके से छीना जा रहा है, इसके लिए आज ये बहुत ही गम्भीर मुद्दा है, जो वहां पर बैठ के एक अधिकारी आदेश करेगा, जो वहां, भई चुना हुआ हमारा प्रतिनिधि वहां पर सारे कमेटी के मैंबर चुन लिए जाएंगे, तो वो कैसे सम्भव है। या तो मेयर साहिबा बने, नहीं तो कोई हमारे निगम पार्षद बैठे, कोई चुना हुआ साथी बैठे और ऑलरेडी वो 5 अक्तूबर को डिसाइडिड था, ऑलरेडी 5 अक्तूबर का दिन डिसाइडिड था उसको आनन-फानन में क्या ऑफत पड़ी, कौन सी ऐसी ऑफत पड़ी जो अभी तुरंत एक बजे का टाईम नोटिस कर दिया गया, एक बजे का टाइम दे दिया गया। तो अध्यक्ष जी इसको किसी भी तरह से जल्द से जल्द, कोई अधिकारी नहीं, चुना हुआ प्रतिनिधि उसका सदन का प्रतिनिधित्व करे, एमसीडी सदन का चुना हुआ प्रतिनिधि सदन को देखे और सदन को मैनेज करे।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः एक सैकंड, प्रवीण जी, अभय जी पहले खड़े हुए हैं आपसे।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः भई ओमप्रकाश जी, मैं अभय वर्मा जी बोल रहा हूं। अभय वर्मा जी बोल रहा हूं, दो मिनट बैठिए अभी,

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः भई आप चर्चा नहीं होने देना चाह रहे हैं।

...व्यवधान...

(कुछ माननीय सदस्य वैल में आकर नारेबाजी करने लगें।)

माननीय अध्यक्षः माननीय सदस्यों से प्रार्थना है, माननीय सदस्यों से प्रार्थना है कृपया अपनी-अपनी कुर्सी पर बैठें, माननीय सदस्य अपनी-अपनी कुर्सियों पर बैठें।

...व्यवधान...

(सत्तापक्ष के सदस्यों द्वारा नारेबाजी जारी रखी गई।)

माननीय अध्यक्षः सदन की कार्रवाई 15 मिनट के लिए स्थगित की जाती है।

सदन 12.43 बजे पुनः समवेत हुआ।

माननीय अध्यक्ष (श्री रामनिवास गोयल) पीठासीन हुए।

माननीय अध्यक्षः संजीव झा जी।

...व्यवधान...

श्री संजीव झाः मैं बोल देता हूं सर।

माननीय अध्यक्षः अभी-अभी बुलवाते हैं।

...व्यवधान...

श्री संजीव झाः सर जैसा कि बाकी साथियों ने..

माननीय अध्यक्षः तीन सदस्य इस पर बोलेंगे और, उसके बाद अगर इसी पर लम्बा खींचा तो सारे विषय रह जायेंगे जो बहुत महत्वपूर्ण विषय हैं।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः तो बोल रहे हैं न वो, आपके साथी बोल तो रहे हैं।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः चलिए।

...व्यवधान...

श्री संजीव झाः जैसा कि..

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः बोलिये बोलिये।

श्री संजीव झाः जैसा कि बाकी साथी कह रहे थे और मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि इस देश के जनतंत्र की बुनियाद भी

और लोकतंत्र की बुनियाद भी बहुत मजबूत है और हम सब जितने भी चुने लोग हैं चाहे किसी भी सदन के सदस्य क्यों ना हों, चाहे वो एमसीडी में हो विधानसभा में हो लोकसभा में हो हम सबकी ये जिम्मेदारी बनती है कि सदन की मर्यादा, लोकतंत्र की रक्षा और संविधान की रक्षा करें चूंकि उसी लोकतंत्र, उसी संविधान की बदौलत हम सब लोग चुनकर यहां आये हैं। जो कुछ भी एमसीडी में कल से हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी इस देश की लोकतांत्रिक मर्यादा को, इस देश की संवैधानिक व्यवस्था को तार-तार कर रही है। हम तो डे-वन से मानते हैं कि इनको लोकतंत्र में और संविधान में विश्वास नहीं है लेकिन इस तरह से पावर हो तो उसका नंगा नाच करना मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं है। कल, मुझे लगता है कि एमसीडी में जो चुने हुये सदस्य गये हैं, चुने हुये सदस्य अपने मेयर को चुनते हैं और एमसीडी एक्ट में ये प्रोविज़न है कि वो मेयर जब-जब वो चाहेंगी तब-तब हाउस बुलाना होगा, वो एमसीडी की मेयर बुलायेंगी। एमसीडी की जो मेयर हैं उन्होंने हाउस का दिन रखा, आनन-फानन में पहले तो कहा गया कि 1.00 बजे रात में हाउस चलेगा, क्या मज़ाक हो रहा है और एल.जी. साहब दिल्ली में नहीं हैं, वो छुट्टी मनाने के लिये विदेश में हैं और रात में ही विदेश से ये आदेश आ जाता है कि कोई बाबू चेयर पर बैठेगा और वो हाउस को चलायेगा। ये बात केवल कोई पक्ष-विपक्ष की नहीं है, चाहे हम हो या हमारे विपक्ष के साथी हों, सबको इसी दिल्ली की जनता ने चुनकर के भेजा है और जब आप चुनकर के आये हैं तो आपकी भी उतनी ही जिम्मेदारी बनती है कि

चेयर की मर्यादा बनी रहे। अगर आज जो कुछ भी एमसीडी में हुआ कल को अध्यक्ष महोदय ये कहेंगे कि भई विधानसभा के चेयर पर एक कोई अधिकारी बैठ जायेगा, परसों कह देंगे कि लोकसभा के चेयर पर कोई अधिकारी बैठ जायेगा, तो फिर इस देश में बाबूशाही चलेगी, लोकतंत्र खत्म हो जायेगा। तो आज जो कुकृत्य फिर से इन्होंने किया है, देश के सामने इनका वो तानाशाही वाला जो चेहरा था, वो तानाशाही का चेहरा पूरे देश ने आज देखा है। हम सब लोगों की इस सदन की मर्यादा को, संवैधानिक व्यवस्था को और लोकतांत्रिक व्यवस्था को अक्षुण्ण रखने की और संरक्षित रखने की जिम्मेदारी है और इसीलिये हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं, हम कड़ी निंदा करते हैं और इस देश के संविधान को, लोकतांत्रिक मर्यादा को कोई अगर तार-तार करने की कोशिश किया जायेगा तो ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जायेगा। मैं ये मानता हूं कि ऐसे नापाक चेहरे से, ऐसे नापाक लोगों से देश को बचाने की जरूरत है। ये सब लोग इस देश को, जनतांत्रिक व्यवस्था को और देश को कमज़ोर करने की साजिश भारतीय जनता पार्टी और पूरे आलाकमान करने की साजिश कर रही है, हम उसका विरोध करते हैं।

माननीय अध्यक्षः श्री प्रवीण कुमार जी।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः मैं करवा रहा हूं, करवा रहा हूं। इसके बाद..

श्री प्रवीण कुमारः माननीय अध्यक्ष महोदय जब-जब भारतीय जनता पार्टी इलैक्शन हार जाती है उसके बाद भारतीय जनता पार्टी

षड़यंत्र रचने की कोशिश करती है और वही जो है एमसीडी में कर रही है। जब से आम आदमी पार्टी का मेयर जो है एमसीडी में चुना गया और भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरीके से दिल्ली की जनता ने नकार दिया एमसीडी में, उसके बाद तब से ये एमसीडी के पीछे लगातार लगे हुये हैं किसी तरीके से एमसीडी इनके कब्जे में आ जाये। आज स्टैंडिंग कमेटी का जो इलैक्शन है गलत तरीके से भारतीय जनता पार्टी एल.जी. के माध्यम से करवाना चाहती है। कल पूरी तरीके से मेयर शैली ओबरॉय ने लिखकर दे दिया कि आज इलैक्शन नहीं होगा और 5 अक्तूबर को इलैक्शन होगा लेकिन उसके बावजूद एल.जी. अमेरिका से बैठकर वो चिट्ठी लिख रहे हैं कि किसी एडिशनल कमिश्नर को बिठा दिया जाये और वो इलैक्शन करायेगा। ये इस देश में जो है किस तरीके का लोकतंत्र है? ये इस तरीके का हो गया कि आज वो कि कोई अधिकारी जो है एमसीडी में बैठा है मेयर की कुर्सी पर प्रेजाइडिंग ऑफिसर की कुर्सी पर, कल को जो है इस विधानसभा में एक आईएएस ऑफिसर बैठ जायेगा स्पीकर की कुर्सी पर और वो कहेगा कि जी अब जो है इसी तरीके से काम चलेगा। लोकसभा में भी ऐसे आईएएस ऑफिसर को बिठा देंगे, ब्यूरोक्रेट को बिठा देंगे स्पीकर की कुर्सी पर, ये किस तरीके का लोकतंत्र जो है, किस तरीके का संविधान जो है भारतीय जनता पार्टी बनाना चाहती है? क्या इसी दिन के लिये भारतीय जनता पार्टी को केन्द्र में mandate मिला था कि किसी तरीके से वो संविधान का दुरूपयोग करके, एल.जी. की शक्तियों का दुरूपयोग करके जो संवैधानिक संस्थायें हैं, जो लोकतंत्र के स्तंभ हैं

उनको पूरी तरीके से derail किया जाये? भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से एल.जी. ने जो ये काम किया है बहुत ज्यादा कुकृत्य है, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। मैं खुद जो है एमसीडी हाउस का मैम्बर हूं, आपके माध्यम से आपने जो है जो 13 लोगों को भेजा हुआ है उसमें मैं भी शामिल हूं अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय और इससे पहले भी आपने भेजा था, आज तक एमसीडी में ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई प्रेजाइडिंग ऑफिसर या चुनाव करने वाली जगह पर जो है जो कोई ब्यूरोक्रेट आकर बैठ जाये, वहां हमेशा जो है चुना हुआ प्रतिनिधि ही बैठ सकता है। लेकिन एल.जी. ने ये चिट्ठी भेजकर पूरी तरीके से लोकतंत्र की, संविधान की हत्या करने की कोशिश करी है अध्यक्ष महोदय। एक दो लफ्ज़ जो हैं एकदम से मेरी बातों में आये:

''कि मालूम ये होता है कि दौरे तबाही है,

शीशे की अदालत है पत्थर की गवाही है,

दुनिया में कहीं ऐसी तफसील नहीं मिलती साहब

कातिल ही मुहाफिज़ है और कातिल ही सिपाही है।''

ये आप एक तरीके से बैकडोर से सरकार चलाना चाह रहे हैं, जब हार जाते हैं तो उसके बाद बैकडोर से सरकार चलाना चाह रहे हैं। बहुत कुकृत्य, शर्म आनी चाहिये एल.जी. साहब को इस तरीके के काम करते हुये, संवैधानिक पोस्ट पर उसकी मर्यादा रखनी चाहिये, ये इतिहास में दर्ज होती हैं सारी चीज़ें। जब आगे जो है लोग इसको पढ़ेंगे, इसको

देखेंगे तो वो क्या सोचेंगे, ये देश की जनता बहुत समझदार है। ये सोचते हैं कि देश की जनता मूर्ख है, इसी तरीके से चल जायेगा, हम बैकडोर से एंट्री कर लेंगे, लेकिन इस तरीके से चलेगा नहीं अध्यक्ष महोदय। भारतीय जनता पार्टी वालों को कहना चाहता हूं कि एमसीडी की स्टैंडिंग कमेटी आप कितने भी कोशिश कर लो, आपके हाथ में कभी नहीं आने वाली। आपकी नीयत गलत है, ये इनके मुंह में ना खून लग गया है, इनके मुंह मे जो है एमसीडी के जो 15 साल इन्होंने राज किया है ना, इनके मुंह में खून लग गया है।

माननीय अध्यक्षः प्रवीण जी कन्क्लूड करिये, प्लीज़ कन्क्लूड करिये।

श्री प्रवीण कुमारः ये किसी भी तरीके से एमसीडी को जाने, क्योंकि वो कमाई पूत था इनका।

माननीय अध्यक्षः कन्क्लूड करिये।

श्री प्रवीण कुमारः ये किसी भी तरीके से उसको जाने नहीं देना चाहते अध्यक्ष महोदय, ये पूरी तरीके से येन-केन-प्रकारेण पूरी ताकत वहां पर लगाना चाहते हैं, बहुत शर्म की बात है, मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः मदन जी, अभी मैं करता हूं प्लीज़, मैं अभी करता हूं, बैठिये दो मिनट, अभय वर्मा।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः एक मिनट मदन जी प्लीज़।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः इसी विषय को शाम तक चला लें, अब क्या करूं बताईये?

...व्यवधान...

श्री अभय वर्माः धन्यवाद अध्यक्ष जी, अभी यहां के ऑनरेबल मैम्बर दिलीप पांडे जी ने एक वक्तव्य रखा जिसका मैं जबरदस्त विरोध करता हूं। सरासर उन्होंने झूठ बोला है, फैक्ट को तोड़-मरोड़ कर कहा है। कोई लोकतंत्र की हत्या नहीं हुई है, अगर लोकतंत्र की हत्या हुई है तो मेयर ने किया है अध्यक्ष जी।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः भई देखिये ये जरनैल जी।

...व्यवधान...

श्री अभय वर्माः अध्यक्ष जी, 15 तारीख को..

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः भई उन्होंने समय मांगा है, बोल रहे हैं।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः ये तो कोई बात नहीं हुई।

श्री अभय वर्माः सच सुनने में घबरा जाते हो आप लोग, सच सुनने में घबरा जाते हो।

माननीय अध्यक्षः ये मुझे डायरेक्शन दोगे क्या?

श्री अभय वर्माः 15 दिन पहले 26 सितम्बर को चुनाव तय हुआ था, निगम के लोगों ने नामांकन किया, 26 तारीख को चुनाव होना था और मेयर साहिबा उसको एडजोर्न करके भाग रही हैं। ये है लोकतंत्र की हत्या।

...व्यवधान...

श्री अभय वर्माः चुनाव से क्यों भाग गईं, चुनाव क्यों नहीं करवाया? चुनाव जब तय था, नियमानुसार चुनाव हो रहे थे तो क्यों मेयर साहिबा एडजोन कर दिया हाउस को, जवाब मेयर साहिबा को देना है ना और सर पौने दो साल में एमसीडी का क्या हाल हुआ है?

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः चलिये।

श्री अभय वर्माः पूरी दिल्ली डूब गई बारिश के पानी से,

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः ठीक है, ठीक है।

...व्यवधान...

श्री अभय वर्माः नालियों की सफाई नहीं हुई, गाद नहीं निकाले गये, पौने दो वर्षों से कमेटी नहीं बनी, पूरा एमसीडी ठप्प पड़ा है और 20 लोग दिल्ली के मर गये पानी में डूबने के कारण, करंट लगने के कारण मर गये।

माननीय अध्यक्षः हो गया अभय जी।

...व्यवधान...

श्री अभय वर्माः और महापौर का कार्यकाल एक साल का था, पौने दो साल से महापौर बनकर बैठी हुई हैं।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः कन्क्लूड करेंगे।

श्री अभय वर्माः तो कहीं ना कहीं सारे लोकतंत्र को तार-तार करने का काम एमसीडी के आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने किया है। चुनाव फेस नहीं करना चाहते, चुनाव से भाग जाते हैं।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः ऋतुराज जी।

श्री अभय वर्मा: और गलत-गलत आरोप लगाते हैं।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्ष: श्रीमान ऋतुराज जी।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्ष: कुलदीप जी ये तरीका ठीक नहीं है।

...व्यवधान...

श्री ऋतुराज गोविंद: मैं बोल रहा हूं।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्ष: मैं डिसअलाओ कर रहा हूं।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्ष: मैं डिसअलाओ कर रहा हूं, बैठिये।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्ष: मैं हाउस एडजोर्न कर दूं फिर, मैं हाउस एडजोर्न कर दूं?

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्ष: रोहित जी बैठिये।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः कुछ चेयर की मर्यादा रखिये थोड़ी, बैठिये अभय जी, ऋतुराज जी।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः अभी-अभी, बैठिये-बैठिये प्लीज।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः वो मालूम है सबको क्यों बुलाओ।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः चलिये, ऋतुराज जी चलिये।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः ऋतुराज जी आप शुरू करिये, प्लीज़।

...व्यवधान...

श्री ऋतुराज गोविंदः अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय।

...व्यवधान...

श्री ऋतुराज गोविंदः अरे बैठो वर्मा जी, आप बैठो।

माननीय अध्यक्षः अभय जी आप बैठिये प्लीज़।

श्री ऋतुराज गोविंदः वर्माजी बैठो।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः चलिये।

श्री ऋतुराज गोविंदः कभी-कभी इनको बोलने का मौका मिलता है। अध्यक्ष जी, ये देश बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से चलता है, यहां किसी के बाप का राज नहीं है। एमसीडी डीएमसी एक्ट से चलता है। हम लोगों ने देश भर में इनके करतूतों को देखा है, चंडीगढ़ के करतूत को तो सुप्रीम कोर्ट ने भी देखा और देश ने देखा है कि किस तरीके से ऑन कैमरा ये लोग वोट चोरी करते हुये पकड़े गये। इनकी नीयत खराब है, डे-वन से खराब है क्योंकि एमसीडी को ये सबसे बड़ा लूट का अड्डा हमेशा बनाकर रखे हैं, उसी से इनका भाजपा मुख्यालय चलता रहा है। तो वो जो कामधेनू गाय है, उससे जो इनकी मोहमाया है वो कभी हट नहीं पाई है आज तक। आप सोचो कि दिल्ली की मेयर चुनाव करायेगी, स्टेंडिंग कमेटी की एक सीट के लिये चुनाव होना है उसके लिये इतना परेशान हैं, इतना परेशान हैं। लैफ्टिनेंट गर्वनर अमेरिका में है, दिल्ली के लैफ्टिनेंट गर्वनर, वी.के. सक्सैना, क्या इन्ट्रस्ट है उनका एमसीडी के अंदर में कि रात को 8.00 बजे आर्डर करते हैं कि 10.00 बजे चुनाव कराओ फिर सुबह 11.00 बजे आर्डर करते हैं कि 1.00 बजे चुनाव कराओ। अरे जब हाउस एडजोर्न हो चुका है, जब ये तय हो चुका है कि चुनाव 5 तारीख को होगा तो ऐसी क्या ऑफत है कि पांच-सात दिन आप वेट नहीं कर

सकते हैं और ऐसी क्या मजबूरी है? बेसिकली क्या है इनका ऑपरेशन लोटस केवल स्टेट गर्वमेंट को तोड़कर के बनाने के लिये नहीं चलता है, इनका ऑपरेशन लोटस पार्षदों को ईडी, सीबीआई में फंसाकर, डराकर के, पैसे का लालच देकर के, तोड़कर क्रॉस वोटिंग कराने में भी इनका इन्ट्रस्ट होता है जिसके चलते क्योंकि एमसीडी के अंदर जो है सो दल–बदल कानून लागू नहीं होता है, इसके लिये ये लालायित हैं परेशान हैं कि किसी तरीके से लोकतंत्र की हत्या करके, नियमों का, ऑफिसरों का इस्तेमाल करके कल जो है सो civic centre के अंदर में दिल्ली पुलिस भेज दिया, वहां पर में पूरा पैरामिलिट्री फोर्स भेज दिया, पार्षदों को, सोचिये सदन में नहीं जाने दे रहे हैं। अरे ये जनतंत्र में जनता इम्पोर्टेन्ट है, लोकतंत्र लोगों से बनती है, डैमोक्रेसी का मतलब of the people, for the people, by the people होता है। बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान से ये देश चलता है, डीएमसी एक्ट से एमसीडी चलता है आपको क्या प्रॉब्लम है भई? आप पार्षदों को अंदर घुसने नहीं देंगे, चुनाव कराने नहीं देंगे। जो मेयर है, आपकी कुर्सी पर, ठीक कहा इन्होंने, आपकी कुर्सी पर कल को जाकर कोई अफसर बैठ जायेगा और वो हाउस चला सकता है क्या? ये ऐसा हो ही नहीं सकता है। आज अमेरिका में बैठ करके Lt. Governor आदेश कर रहे है कि मेयर नहीं करायेगा तो डिप्टी मेयर करायेगा, डिप्टी मेयर नहीं करायेगा तो किसी चिंटू को बैठा करके चुनाव करा दो। किसी भी तरीके से करा दो। तो सुप्रीम कोर्ट का observation और ये इतने बेशर्म लोग हैं, सोचो कि जिस आदमी की चोरी सुप्रीम कोर्ट ने पकड़ी, जिस आदमी को ले

करके सारी दुनिया ने देखा, उसी आदमी को सजा देने के बजाय, जेल भेजने के बजाय, उसी आदमी को, उसी चण्डीगढ़ के हाउस में Elder man बना करके बैठाने का काम किया है, ये इनका बेशर्मी का चेहरा है। ये चेहरा है इनका और वो बेशर्म आदमी, वो चोर आदमी, वो डकैत आदमी, वो करप्ट आदमी जिसको जेल में होना चाहिए, वो आज उसी हाउस में बैठ करके पूरे सिस्टम को चिढ़ा रहा होता है, संविधान की धज्जियां उड़ा रहा होता है। ये लोग हमको मर्यादा की बात करते हैं, ये लोग मर्यादा सिखाते हैं। ये लोग संविधान विरोधी हैं। इनका बस चले तो वो आज संविधान को बदल करके अपना संविधान लागू कर दें। लेकिन उसी के चक्कर में इनका 400 से 240 हुआ है। लेकिन आज तक घमंड टूटा नहीं है और ये एलजी वी.के. सक्सेना नरेन्द्र मोदी के चिंटू है।

माननीय अध्यक्षः चलिये कन्क्लूड करिये प्लीज।

श्री ऋतुराज गोविंदः मतलब नरेन्द्र मोदी के representative है और वो जो है सो अमेरिका में बैठ करके जो है सो आदेश देने का काम कर रहे हैं। ये सरासर लोकतंत्र के खिलाफ है। ये तानाशाही नहीं चलेगी। लोकतंत्र की हत्या नहीं चलेगी। ये देश संविधान से चलेगा। एमसीडी डीएमसी एक्ट से चलेगा। किसी के बाप का राज नहीं है कि जो मन में आयेगा वो करेगा। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः अजय दत्त जी केवल एक मिनट। एक मिनट का समय दे रहा हूं मैं। इसके बाद में आपको।

श्री अजय दत्तः Sir, Thank you, you have given me an opportunity to talk about a very serious matter. India is known as the biggest democratic country in the world and the entire world is looking upto India to strengthenize democracy, looking upto us that the democracy actually should create a new set of process and strengthenize many other countries which are part of, which are very, which are in the process of becoming a democratic country but today, we all are very ashamed, we are very sad that in Delhi, in the capital of India, the BJP is trying to hijack democracy, BJP is trying to break democracy, BJP is trying to hijack the entire system of democracy and also the constitution which is not acceptable and we all, as a member of this August Assembly and also I am a member of MCD, we strongly oppose this kind of activities done by Hon'ble LG Saheb that he should not interfere in any election process, he should not interfere in any electoral issues. He should only be concerned about his role and responsibility and yesterday we have seen another kind of issues that he is interfering again and again and trying to give direction that he should conduct election. The election is not about just a BJP programme, it is not about breaking party, it is not about hijacking people, it is all about the people of India…

माननीय अध्यक्षः अजय दत्त जी प्लीज, प्लीज कन्क्लूड।

श्री अजय दत्तः it is all about the people of India and we strongly oppose and we would like this House to give some order or to proceed or give some verdict that the democracy can not be destroyed by any LG or by any bureaucrat or anybody because it is all about the people who have given their life for the democracy and the democratic process of India, thank you very much sir.

माननीय अध्यक्षः श्री मदन लाल जी।

श्री मदन लालः धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस burning topic पर बोलने का मौका दिया। आज एक बहुत ही भयानक स्थिति में हैं हम जब ये देखते हैं कि एलजी ने चुने हुए लोगों की सत्ता को हथियाने की बैक डोर से कोशिश की है, वो चाहे पार्लियामेंट हो वहां स्पीकर चलाते हैं, विधान सभा हो, स्पीकर चलाते हैं, एमसीडी को मेयर चलाती हैं। नियम है कि मेयर चलायेगी। मेयर का appointment से पहले protem mayor होगी। बीजेपी ने पहला खेल वहां खेला। उन्होंने जानबूझकर जब मेयर का इलैक्शन होना चाहिए था उससे पहले protem mayor कराते हैं इलैक्शन। तो उन्होंने जो परिपाटी है उसको एक तार पर रखकर जो सीनियर मोस्ट मैम्बर को चुनकर protem mayor बनाना था, उनको ना बनाकर अपनी पार्टी के एक जूनियर काउंसलर को बनाया। ये लोकतंत्र की पहली हत्या थी। इलैक्शन हो रहा था। इलैक्शन कराना मेयर का prerogative है। ये अधिकार इस विधान सभा में केवल और केवल आपका है और आपकी absence में डिप्टी स्पीकर का है। फिर एक परिपाटी के अनुसार एक कानून के मुताबिक, आपके ऑफिस

द्वारा एक लिस्ट बनाई जाती है कि अगर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर एविलेबल नहीं होंगे तो इस क्रम में स्पीकर का पदभार सम्भालेंगे। वो एक लिस्ट बनती है। तब सर कोई भी मैम्बर कैसे उस कुर्सी पर बैठ जायेगा जो अधिकृत ही नहीं है और अधिकृत करने का अधिकार केवल और केवल उस सदन के नेता को है और वो सदन का नेता इस समय इस कुर्सी पर आप हैं, पार्लियामेंट में पार्लियामेंट के स्पीकर है और यहां एमसीडी में मेयर हैं। अगर एलजी साहब ये कहें कि या तो मेयर नहीं तो डिप्टी मेयर और अगर कोई ना हो तो किसी भी अफसर को बैठा दो। इसका मतलब तो ये है कि आप शायद ये भूल गये कि ये देश बाबा साहेब अम्बेडकर के कानून से नहीं बल्कि आपने कोई नई और किताब लिखनी शुरू दी है। ये तो कानून में भी मान्यता नहीं है। ये तो किसी भी तरह कोई भी ठीक-ठाक से समझदार आदमी जो भी कानून को समझता होगा वो तुरन्त ही कहेगा कि ये बिल्कुल ही गलत है और ये कभी भी मंजूर नहीं है ना हमको, ना आपको, ना कानून को। सर ऐसे समय में जब लगभग दो साल हो गए एमसीडी को बने और अब तक हम स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव नहीं करा पा रहे हैं। उसका सबसे बड़ा कारण हमने देखा कि बीजेपी की तरफ से एलजी ने एक्ट करते हुए जानबूझकर पहले Elder man की ऐसे गिनती लगाई थी सब इलाकों में कि वहां हर बार गिनती को पूरा करके उनका चेयरमैन बनाया जाये। ये सोची समझी राजनीति थी। सोचा समझा, ये एलजी का काम नहीं है।

माननीय अध्यक्षः चलिए कन्क्लूड करिये अब।

श्री मदन लालः एलजी को पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लेना चाहिए।

माननीय अध्यक्षः मदन जी कन्क्लूड करिये प्लीज।

श्री मदन लालः और सर अगर पॉलिटिक्स में हिस्सा किसी को लेना हो तो इलैक्शन लड़े। फिर स्पीकर बने, मेयर बने, प्रधान मंत्री बने। चोर दरवाजे से सत्ता हथियायी नहीं जा सकती। मैं इस सदन के माध्यम से उन सभी से, जो इस दुष्कृत्य के पीछे हैं, निवेदन करना चाहता हूं कि आप कानूनन गलत काम कर रहे हैं। मेयर ने अगर दो साल इलैक्शन नहीं हुआ है। क्या हो गया अगर एक हफ्ते बाद की डेट दे दी है? उससे कौन सा पहाड़ टूट रहा है और एलजी साहब तो यहां है ही नहीं। वो तो अमेरिका में बैठे हैं फिर ऐसे कौन से अफसर है जिनके पेट में दर्द है, वो क्यों परेशान हैं? सर अगर वो ये कहें कि मेयर नहीं है, डिप्टी मेयर नहीं है तो हाउस बुलाया जायेगा। हाउस दोनों में से कोई एक बुलायेगा और अगर किसी को डेट पर ऐतराज है तो फ्लोर पर जाओ टेस्ट करो। आपकी गिनती वहां पूरी नहीं है। आप वहां भी हारेंगे। इसीलिए आप बार-बार जानबूझकर लोगों में कन्फ्यूजन पैदा कर रहे हैं क्योंकि आपके मन में बेईमानी है। सर इलैक्शन पांच को ही होना चाहिए जैसा मेयर साहिबा ने आर्डर किया है और वो ही तर्क संगत भी है, न्याय संगत भी है। इसलिए मैं इस सदन के माध्यम से उन सभी से निवेदन करता हूं कि कृपया अपनी फजिहत करवाना बंद कर दीजिए। अनर्गल बाते आप करना, इस सदन में भी बंद कर दीजिए

कि आप उनको सपोर्ट करते हैं और आप अच्छी तरह जानते हैं कि वो गलत कर रहे हैं।

माननीय अध्यक्षः मदन जी अब..

श्री मदन लालः थैंक्यू सर।

माननीय अध्यक्षः विजेन्द्र जी। विजेन्द्र जी जरा शॉर्ट में रखिये प्लीज।

श्री विजेंद्र गुप्ता (माननीय नेता, प्रतिपक्ष): धन्यवाद अध्यक्ष जी, महापौर के विषय में यहां बात हो रही है। अध्यक्ष जी, मैं संक्षिप्त में, दिल्ली नगर निगम का गठन 6 दिसम्बर, 2022 को हुआ था और 6 दिसम्बर, 2022 के बाद लगभग दो साल होने वाले है, पौने दो साल हो चुके हैं, स्टैंडिंग कमेटी constitute नहीं हुई है। दिल्ली नगर निगम की स्टैंडिंग कमेटी constitute ना होना ये एक बहुत बड़ी चुनौती है पूरी दिल्ली के लिए और आज जिसके कारण दिल्ली अस्त-व्यस्त है। नगर निगम अपनी जिम्मेदारी नहीं निर्वाह कर पा रही उसका बड़ा कारण ये है कि स्टैंडिंग कमेटी का गठन ना होना। अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि लगातार ये कोशिश की गई है रूलिंग पार्टी के द्वारा वहां पर कि स्टैंडिंग कमेटी constitute ना हो, वार्ड कमेटीज constitute ना हो। दिल्ली नगर निगम के डीएमसी एक्ट के अनुसार रूल 44 में डीएमसी की जो पावर है, कार्पोरेशन की जो पावर है वो तीन जगह vest करती है। एक कमिश्नर, दूसरा वार्ड्स

कमेटी और तीसरा स्टैंडिंग कमेटी। अब सवाल ये है कि कार्पोरेशन की पावर जहां vest करती है, जहां पर इलैक्टिड लोग हैं, जहां वो जो फैसला लेंगे वो मान्य होगा और वो उसका आधार executive होगा यानि कि वो execute होगा। दिल्ली नगर निगम के अंदर स्टैंडिंग कमेटी में पांच करोड रूपये से अधिक के जो काम है, पांच करोड रूपये से अधिक के काम उसका कॉन्ट्रेक्ट साईन करने का अधिकार स्टैंडिंग कमेटी का, कॉन्ट्रेक्ट करने का अधिकार स्टैंडिंग कमेटी का है, टेंडर कॉल करने का और उसको मैच्योर करने का और अवार्ड करने का वो काम स्टैंडिंग कमेटी का है। आप समझिये पिछले पौने दो साल से दिल्ली में पांच करोड रूपये से अधिक का कोई काम ही नहीं हो रहा नगर निगम का। अब जैसे अभी जो concessioner appoint होना है कूडा उठाने वाला उसका टर्म पूरा हो गया, तीन साल, चार साल, पांच साल जितने साल के लिए भी उसको ठेका दिया गया था। अब नये टेंडर होंगे। नये टेंडर होंगे तो उसके बाद वो नई appointment होगी। लेकिन वो नहीं हो रही है। इसी तरह मशीनरी परचेज करनी है, उसी तरह से आपके ढलाव ये मैनटेन करने हैं, सेनेटरी landfills maintain करनी है, सड़के बनानी हैं और बिल्डिगें बनानी हैं। तो तमाम चीजें सारी रूक गई। इसी स्टैंडिंग कमेटी में ले आउट और ये जो अधिकार है सिर्फ स्टैंडिंग कमेटी का है। टेंडर कॉल, टेंडर को मैच्योर करना और उसको अवार्ड करना..

माननीय अध्यक्षः विजेन्द्र जी ये सब सदस्यों को मालूम है।

श्री विजेंद्र गुप्ताः एक मिनट, तीन मिनट में मैं खत्म कर दूंगा, दो मिनट में,

माननीय अध्यक्षः तीन मिनट तो..

श्री विजेंद्र गुप्ताः दो मिनट में मैं खत्म कर दूंगा बात पूरी। इसी तरह ले आउट भी सिर्फ स्टैंडिंग कमेटी की पावर है उसके अलावा ना कमिश्नर को पावर है, ना भारत के राष्ट्रपति के पास भी वो पावर नहीं है जो पावर स्टैंडिंग कमेटी की है ले आउट को amend करने की या ले आउट को पारित करने की, रि ले-आउट बनाने की। पिछले पौने दो साल से दिल्ली में जो दिल्ली नगर निगम का अधिकार क्षेत्र है 97 परसेंट दिल्ली नगर निगम के पास है। दिल्ली नगर निगम उसको होल्ड करता है। वहां पर कोई ले आउट पारित नहीं हुआ है। मुझे समझ नहीं आता कि पहले आपने वार्ड कमेटी constitute नहीं होने दी। बिना मतलब के उसको रोके रखा। ये ही सब चीजें जब वार्ड कमेटी के चुनाव थे तब भी ये ही हुआ था जब महापौर उनको उसकी डेट वापिस लेकर चली गई थी और वो वार्ड कमेटी उनके इच्छा के विरूद्ध constitute हुई हैं। इसी तरह Standing Committee के जब 17 मैम्बर elect हो चुके हैं तो एक मैम्बर को क्यों नहीं elect होने दिया जा रहा जिससे कि एक मैम्बर elect नहीं होगा तो Body constitute नहीं हो पाएगी और Body constitute नहीं होगी तो वो काम नहीं कर पाएगी। मैं आम आदमी पार्टी की इस भावना की कड़े शब्दों में निंदा करता हूं कि वो कल मोबाइल अंदर ले के जा रहे हैं जबकि मोबाइल वोटिंग के समय मोबाइल लेकर जाना अलाउड नहीं है लेकिन आपकी एक ही जिद थी कि मैम्बरों को मोबाइल ले जाने दिया जाए। ये पूरी तरह गलत था। मोबाइल अंदर नहीं जाना चाहिए जहां वोटिंग हो रही है।

दूसरा बार बार हाउस को ऐडजोर्न करना, वोटिंग को टालना ये पूरी तरह से गलत है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति, आप मेयर का चुनाव नहीं होने दे रहे। एक साल का टर्म था चूंकि वहां पे दलित पार्षद को मेयर बनना था, आपने पूरा दलित का जो टैन्योर है वो आपने, आम आदमी पार्टी ने..

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः मैं इसको, मुझे और भी.

...व्यवधान...

श्री विजेंद्र गुप्ताः वो अधिकार छीन लिया तो इसलिए.

...व्यवधान...

श्री विजेंद्र गुप्ताः मेरा ये साफ कहना है कि इस पूरे उसमें जो गड़बड़ झाला आप कर रहे हैं..

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः विजेंद्र जी कनकलूड करिए।

...व्यवधान...

श्री विजेंद्र गुप्ताः इस गड़बड़ झाले को आप रोकिए।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः विजेंद्र जी कनकलूड करिए प्लीज।

...व्यवधान...

श्री विजेंद्र गुप्ताः और मैम्बर का चुनाव करवाइए और स्टैंडिंग कमेटी को constitute होकर उसका काम होने दीजिए। धन्यवाद।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः धन्यवाद। मैं अब किसी को एलाउ नहीं प्लीज। मैं किसी को मेरे पास बिजनैस बहुत ज्यादा है।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः प्लीज, मैं रिकवेस्ट कर रहा हूं।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः माननीय सदस्य गण, माननीय उपराज्यपाल द्वारा दिल्ली नगर निगम की स्थाई समिति की चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने की कार्रवाई बहुत ही गंभीर मामला है। मैंने दिल्ली नगर निगम एक्ट का अभी अध्ययन किया है। इसमें जिस एक्ट का उन्होंने हवाला दिया है 487 रूलिंग का एलजी ने वो इससे संबंधित नहीं है, ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर सीधा हमला है। स्थाई समिति की चुनाव प्रक्रिया की अध्यक्षता मेयर या उनकी अनुपस्थिति में डिप्टी मेयर या किसी सीनियर मोस्ट कारपोरेशन के सदस्य द्वारा की जाती है इस संवैधानिक कर्तव्य को निभाने के लिए किसी अधिकारी को नियुक्त करना निर्वाचित

सदन का मजाक उड़ाना है जिसे दिल्ली के लोगों ने चुना है। मैं माननीय उपराज्यपाल की इस जल्दबाजी को समझ नहीं पा रहा हूं। ऐसा लगता है कि उन्होंने चंडीगढ़ के मेयर चुनाव से कोई सबक नहीं सीखा है।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः जहां सुप्रीम कोर्ट को भी हस्तक्षेप करना पड़ा और कानून की रक्षा करनी पड़ी। धन्यवाद।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः रेजोल्यूशन, श्री कुलदीप कुमार जी, आनरेबल मेंबर to move a resolution regarding mix land use.

श्री विजेन्द्र गुप्ता (माननीय नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष जी, हम इस विषय पर कुछ कहना चाहते हैं। दोबारा दोहरा रहे हैं कि ग्राउंड वाटर....

...व्यवधान...

श्री कुलदीप कुमारः अध्यक्ष महोदय, मैं संकल्प प्रस्तुत करने के लिये सदन की परमिशन चाहता हूं।

माननीय अध्यक्षः हां बोलिये।

श्री विजेंद्र गुप्ताः इस मामले को हम उठाते रहेंगे।

...व्यवधान...

श्री कुलदीप कुमारः अध्यक्ष जी, गुप्ता जी, बहुत गंभीर मसला है डेयरियों का, आप कृपया बैठ जायें। अध्यक्ष जी, दिल्ली के अंदर 1975-76 में दिल्ली के अंदर गाय भैंस के रखरखाव के लिये दिल्ली के अंदर डेयरियों को आवंटित किया गया था जिसमें...

माननीय अध्यक्षः पहले परमिशन तो मांगिये आप।

श्री कुलदीप कुमारः अध्यक्ष जी मैंने तो मांगी है।

माननीय अध्यक्षः एक बार दोबारा करिये।

श्री कुलदीप कुमारः अध्यक्ष महोदय, मैं संकल्प प्रस्तुत करने के लिये सदन की परमिशन चाहता हूं ।

माननीय अध्यक्षः यह प्रस्ताव सदन के सामने है-

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें

जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें

(सदस्यों के हाँ कहने पर)

हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता

प्रस्ताव पारित हुआ।

सदन द्वारा माननीय सदस्य को संकल्प प्रस्तुत करने की परमिशन दी गयी।

श्री कुलदीप कुमारः धन्यवाद अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी दिल्ली के अंदर दिल्ली के लोगों को दूध की आपूर्ति हो और उसके साथ साथ हमारे दिल्ली के अंदर जो गाय, भैंस, पशुपालक करने वाले लोग हैं उनके लिये 1975-76 में अध्यक्ष जी दिल्ली के अंदर डेयरियों को अलॉट किया गया था जिसमें डयूसिब का विभाग, एमसीडी का विभाग, जिन्होंने डेयरियों को अलाटमेंट करने का काम 1975-76 में करने का काम किया था। अध्यक्ष जी, जिस समय पर ये डेयरियां आवंटित की गयी, अलाट की गयी वो दिल्ली के बाहरी क्षेत्रों की तरफ जैसे गाजीपुर डेयरी फार्म है तो वो दिल्ली यूपी के बार्डर पे दिल्ली के बाहर की तरफ है, जैसे Gharoli डेयरी फार्म है तो वो दिल्ली यूपी नोएडा के बार्डर पे है, मदनपुर खादर है, ऐसे ही तमाम दिल्ली के अंदर 11, भलस्वा डेयरी फार्म है, लगभग मेरे पे एक लिस्ट थी हां, लगभग 11 डेयरी फार्म हैं अध्यक्ष जी जो दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में आवंटित किये गये थे। लेकिन उस समय पर वहां के हालात कुछ और थे और आज के हालात अध्यक्ष जी कुछ और हो चुके हैं। आज वहां डेयरी संचालित करने वाले लोगों के लिये पशुपालन वहां करना एक चुनौतीपूर्ण काम हो गया है। इसी के लिये अध्यक्ष जी आज एक संकल्प मैं यहां पर आपकी परमिशन से पढ़ रहा हूं।

''राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा दिनांक 27 सितम्बर, 2024 को आयोजित अपनी बैठक में संकल्प करती है। इस सदन में

संज्ञान में आया है कि तत्कालीन दिल्ली प्रशासन ने वर्ष 1976 में शहर की आबादी से दूर घने जंगलों में पशु पालने के लिये उपयुक्त स्थानों पर डेयरी फार्मों की स्थापना की थी। दिल्ली के निरंतर विकास के परिणामस्वरूप इन डेयरी फार्मों के आसपास कई आवासीय कालोनी का निर्माण हो गया जिस कारण कई डेयरी मालिकों को अपना व्यवसाय बंद करना पड़ा और स्थानीय निवासियों को मौजूदा डेयरी फार्मों के कारण अत्याधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इन कठिन परिस्थितियों के कारण कई डेयरी मालिकों ने पशु पालन का काम छोड़ दिया और उन पर आजीविका का खतरा मंडरा रहा है। इसके दृष्टिगत दिल्ली सरकार ने वर्ष 2018-19 मेें श्री गुलाब सिंह यादव जी की अध्यक्षता में एमसीडी, डयूसिब, डीडीए और डेयरी फार्म के प्रतिनिधियों की एक समिति का गठन किया जिसने अनुमोदन किया कि इन डेयरी क्षेत्रों का भूभाग बदलकर मिश्रित भूभाग प्रयोग मिक्स लैंड यूज में किया जाए। यह आश्चर्यजनक है कि उस समिति की सिफारिश अभी तक लागू नहीं हो पाई है और लगभग ढाई लाख लोगों की अजीविका पर संकट खड़ा हो गया है और वह अनिश्चितता के माहौल में जी रहे हैं।

उपरोक्त गंभीर स्थिति को देखते हुए यह सदन ऋणपूर्वक अनुमोदन करता है कि उक्त समिति की सिफारिशों के दृष्टिगत उक्त डेयरी क्षेत्रों का भूभाग बदलकर मिश्रित भूभाग प्रयोग मिक्स लैंड यूज किया जाए और लगभग पांच दशकों से स्थापित इन डेयरी फार्मों से संबंधित मालिकों को अविलंब मालिक का हक प्रदान किया जाए।''

धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः श्री जयभगवान जी।

श्री जयभगवानः माननीय अध्यक्ष महोदय आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस अति महत्वपूर्ण मुददे पर बोलने का अवसर प्रदान किया। मैं जो अभी कुलदीप भाई ने प्रस्ताव रखा है डेयरी फार्मों के लिये उसका समर्थन करता हूं। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि 1974 में जो दिल्ली की अलग अलग डेयरियां जो अलग अलग क्षेत्रों के अंदर थी उनका नोटिफिकेशन किया गया और 1975 और 76 में इनको अलाटमेंट की गयी जिसके अंदर घड़ौली डेयरी, भलस्वा डेयरी, और गोयला डेयरी, शाहबाद डेयरी, गाजीपुर डेयरी, मसूद पुर डेयरी, मदनपुर खादर डेयरी, ककरौला डेयरी, नंगली डेयरी और भी एक दो डेयरियां हैं जिनका नाम मेरे पास नहीं है तो ये करीब करीब 11 से 12 डेयरियां पूरी दिल्ली के अंदर अलग अलग क्षेत्र में से उठाकर के दिल्ली गेट के आसपास या अलग अलग क्षेत्रों से उठाकर के इनको दिल्ली के बार्डरों पे डाल दिया गया। और वहां पर अध्यक्ष महोदय सबसे बड़ा जो मुद्दा था जब बार्डरों पे इनको डाला गया तो वहां पर इनके लिये व्यवस्था नहीं थी। न ही इनके सैनिटेशन की कोई व्यवस्था थी, न ही इनकी भैंसों का जो गोबर है उसको डालने के लिये कोई व्यवस्था की गयी, न ही जो इनके लिये पानी की व्यवस्था की गयी, न ही वैक्सीन की व्यवस्था की गयी, न ही मेडिसिन की व्यवस्था की गयी। जब डेयरी वाले अपनी डेयरियों को लेकर के इन जगहों पर पहुंचे तो उनकी जो भैंसें हैं वो मरने लगी। बहुत ज्यादा परेशानी हो गयी जिसकी वजह से काफी डेयरी वालों ने अपने प्लाट

छोड़ दिये और वो वापस दूसरी जगह पहुंच गये जिसकी वजह से इन डेयरियों के अंदर धीरे धीरे वो अपने जो प्लाट उनको अलाट हुए थे वो सारे प्लाट दूसरे लोगों को बेचकर के वो चले गये। अध्यक्ष महोदय, इन कालोनियों के अंदर अब क्यूंकि ज्यादातर रेजिडेंशियल एरिया है और सबने अपने जो घर हैं वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से बना रखे हैं, बड़े बड़े बना रखे हैं और सबसे बड़ा मुददा जो है अध्यक्ष महोदय वो ये है इसके अंदर कि एक डेयरी वाले का जो बेटा है ये जरूरी नहीं है कि वो डेयरी चलायेगा क्योंकि मैं भी उसी डेयरी के अंदर रहता हूं। अध्यक्ष महोदय, अगर मेरे पिताजी डेयरी चलाते थे तो ये जरूरी नहीं है कि मैं डेयरी चलाउंगा। तो सभी बच्चे आज पढ़ लिख गये हैं और वो आगे बढ़ गये हैं। तो वो डेयरी करना नहीं चाहते और 97 परसेंट इन डेयरियों के अंदर आज घर बन गये हैं, रेजिडेंशियल एरिया हो गया है और कमर्शियल यूज हो रहा है। तो अध्यक्ष महोदय सबसे पहला मेरा जो मुददा है ये है क्योंकि अभी माननीय कुलदीप कुमार जी ने बताया कि हमारे गुलाब सिंह जी की अध्यक्षता में 2019 में करीब 6.8.2019 को एक पॉलिसी बनाई गयी दिल्ली सरकार की तरफ से जिसमें हमारी जो कमेटी ने 22.8.2019 और 30.8.2019 को दौरा भी किया सभी कालोनियों के अंदर जाकर के डेयरियों के अंदर और इस पर इस कमेटी की 17.9.2019 को और 24.9.2019 को मीटिंग हुई और तय हुआ कि जो इन डेयरी वालों को इनका जो मालिकाना हक है वो दिया जाये और जो मिक्स लैंड यूज है वो किया जाये क्यूंकि अभी क्या है वहां पर कमर्शियल एक्टिविटिज चल रही हैं, कई चीजें हैं तो वो ये चाहते

हैं कि इनको उन डेयरियों का मालिकाना हक दिया जाये सबसे पहले तो और मिक्स लैंड यूज किया जाये, लैंड यूज चेंज किया जाये। तो अध्यक्ष महोदय मैं ये बताना चाहता हूं कि माननीय एलजी साहब ने एक आर्डर है मैंने अभी पढ़ा था इसके अंदर एलजी साहब ने 9.1.2001 को जो मसूद्पुर डेयरी है उसके लिये आर्डर किया और उसको रेगुलराईज कर दिया। वो भी डेयरी थी अब वो रेजिडेंशियल एरिया हो गया है। अभी जैसे कि मैं बात करूं शाहबाद डेयरी की तो 1976 के अंदर वहां पर प्लाट काटे गये और वो डेयरी वाले वहां से चले गये और जब वहां से चले गये तो 10-12 डेयरियां वहां पर रह गयी और उसके बाद में वहां पर करीब करीब 10-12 डेयरियां रहने के बाद में सरकार ने दोबारा से 1986 में शालीमार बाग और केला गोदाम से वहां पर झुग्गियों के प्लाट अलाटमेंट कर दिये। रेजिडेंशियल एरिया बना दिया उस एरिये को क्यूंकि डेयरियों के बीच बीच में जहां जहां जगह बची हुई थी वहां पर डेयरियों के बीच में रेजिडेंशियल प्लाट काट दिये। अध्यक्ष महोदय अब वो जो पूरा एरिया 99 परसेंट रेजिडेंशियल एरिया है और सभी ने तीन तीन, चार चार मंजिल सबने प्लॉट बना रखे हैं और सब लोग घरों में रहते हैं, बच्चे पढ़ लिख गये हैं, सब लोग चाहते हैं कि अब जो उनका जो एरिया है उनको मालिकाना हक दे दिया जाये और ये जो प्लाट है इनको रेगुलाइज कर दिया जाए क्यूंकि अगर व्यवस्था होती पहले से तो यहां पर डेयरी फार्म चलते अब क्यूंकि वहां पर डेयरी यहां है भी नहीं क्यूंकि डेयरियां भी बहुत कम हो गई है और डेयरियां कोई करना भी नहीं चाहता अब और क्यूंकि अभी लास्ट टाइम मैं एक जगह गया था वहां पर..

माननीय अध्यक्षः कनकलूड करिए जयभगवान जी कनकलूड करिए प्लीज।

श्री जयभगवानः सर कनकलूड ही कर रहा हूं। तो चूंकि जो डेयरी फार्म अपनी स्वेच्छा से अगर वो शिफ्ट करना चाहता है घोघा डेयरी में तो वो शिफ्ट कर सकता है और जो लोग रेजीडेंशियल एरिए में रहना चाहते हैं तो उनको मालिकाना हक दिया जाए और मैं जो कुलदीप भाई ने जो ये प्रस्ताव लेकर आए डेयरी वासियों के लिए इसका समर्थन करता हूं। पुरजोर समर्थन करता हूं कि इन सभी एरियों को मालिकाना हक दिया जाए और इनको जो लैंड यूज है वो चेंज किया जाए, मिक्स लैंड यूज दिया जाए। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः श्री नरेश यादव जी। भई ये उपर बैठे हैं कोई भी ताली नहीं बजाएगा। मुझे तालियों की आवाज आ रही है उपर से।

श्री अजेश यादवः अध्यक्ष महोदय इस के बारे में मैं एक सूचना देना चाहता हूं भलस्वा डेयरी में..

माननीय अध्यक्षः अजेश जी बोलिए।

...व्यवधान...

श्री अजेश यादवः आंदोलन इसको लेकर हुआ था तो एमसीडी में हम प्रस्ताव ले के आए और एमसीडी ने इसको पास करके भेज दिया है कि इन लोगों को वहीं रहने दिया जाए और इसका लैंड यूज चेंज कर दिया जाए।

माननीय अध्यक्षः चलिए, हां।

श्री नरेश यादवः धन्यवाद अध्यक्ष जी जो आपने मुझे दिल्ली की डेयरियों के बारे में बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष जी माननीय गोपाल राय जी ने जो 2018-19 में कमेटी बनाई थी श्री गुलाब सिंह जी की अध्यक्षता में उसमें मैं भी एक मैम्बर था और मुझे भी इन सभी डेयरियों में जाने का मौका मिला। हमने जब डेयरियों का विजिट किया तो वहां पर देखा कि जो डेयरियां हैं अब हकीकत में वहां डेयरियां नहीं हैं और रेजिडेंशियल कॉलोनिज बन चुकी है। लगभग 70-80 परसेंट तक वहां built up मकान बन चुके हैं, तब हम इसके तह में गए और हमने पूछा कि ऐसा क्यूं हुआ क्योंकि सरकार ने तो ये डेयरियां दी थी। ये अध्यक्ष जी ये डीडीए ने अलॉट करके ये डेयरियां दी थी। ये जितनी भी 11 की 11 डेयरियों की बात चल रही है ये एन्क्रोचर्स नहीं हैं, इन्होंने अपनी मर्जी से वो जमीन नहीं ली, इनको डीडीए ने लैंड अलॉट की थी और केवल उन्हीं, जो डेयरी जिनको दी है उसी पर इन लोगों ने मकान बनाए और कुछ जो डेयरियां हैं उसमें अभी भी भैंस वगैरह रखते हैं लोग। कई लोगों ने ऐसा भी किया कि ग्राउंड फ्लोर पर भैंस हैं और ऊपर मल्टीस्टोरी बनाकर मकान बना लिया और कुछ किराए-विराए पर दिया। तो अध्यक्ष जी, मैं आपको इसका जो मेन रिजंस थे वो मैं आपको बताना चाहता हूं। जब हमने सभी डेयरियों में, अलग-अलग डेयरियों में विजिट किया। मेरे यहां पर भी मसूदपुर डेयरी है जो डूसिब के अंदर है, मदनपुर खादर, गाजीपुर, कई डेयरियों में मैं भी गया। तो अध्यक्ष जी, यहां पर जो डिपार्टमेंट्स ने, एमसीडी ने,

डूसिब ने जो सुविधाएं देनी थी, जैसे वेस्ट डिस्पोजल नहीं होता था, चारों तरफ गोबर फैला हुआ है और इसके अलावा पानी की कोई सुविधा नहीं थी। मसूदपुर डेयरी में जब मैं 2015 में विधायक बनकर आया एक बूंद पानी भी किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट्स से नहीं आता था। वहां हालात ऐसे थे कि डेयरी चलाना बहुत मुश्किल था। और ये जितने भी डेयरी के ऑनर्स थे इन्होंने मजबूरी में इन डेयरियों को कन्वर्ट कर लिया एक तरह से मकान में, रेजिडेंशियल एरिया में या थोड़ा सा कुछ, किसी ने कोई काम भी अपना स्टार्ट कर दिया उसी डेयरी के स्पेस के अंदर। तो ये ओवरऑल जब हम लोगों ने सबने माननीय मंत्री-गोपाल राय जी के साथ में डिस्कशन किया और सारी रिपोर्ट पेश की, कमेटी ने पूरी रिपोर्ट पेश की तो और ये जो पॉलिसी बनी थी, कमेटी को कांस्टीटयूट किया गया 6/08/2019 में अध्यक्ष जी और कमेटी ने जो अपनी रिपोर्ट दी वो दी थी 14 अक्टूबर, 2019 में और ये सारे रिजंस उसमें मेंशन किए गए और हमने लास्ट फाइनल कंक्लुजन ये निकाला कि इन सभी 11 की 11 डेयरियों को मिक्स्ड-लैंड यूज में कन्वर्ट कर दिया जाए जिससे कि ये लोग अपनी आजीविका भी चला सके और वहां पर अपने परिवार के साथ रह भी सके और अगर एक्स्ट्रा स्पेस है तो उसको किराए पर देकर अपना गुजारा-बसर कर सके, ये एक फाइनल कंक्लुजन था इस पॉलिसी का और आज जो ये प्रपोजल रखा गया है ये उसी पॉलिसी से संबंधित रखा गया है, जो कुलदीप भाई ने रखा है, मैं इसका पूरी तरह से समर्थन करता हूं। इसमें दो डिमांड हैं अध्यक्ष जी, एक तो मिक्स्ड-लैंड यूज इन सभी को दे दिया जाए, दूसरा

इनको ओनरशिप दे दिया जाए। आज भी डीडीए ने इनको लीज पर, लाइसेंस पर रखा हुआ है और वो लाइसेंस और लीज में ये लोग अटके हुए हैं, तरह-तरह के इनके ऊपर टैक्सिस लगाए जाते हैं। खुद डूसिब के पास भी अपनी कैलकुलेशन नहीं है। मैं बहुत बार गया हूं, मेरे पास, कई बार नोटिसिस इशू कर दिए जाते हैं, सीलिंग प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दी जाती है। कभी वहां पर एमसीडी आ जाती है क्योंकि इन्होंने कुछ मकान भी बनाए हैं तो एमसीडी वहां पर जो इलीगल कंस्ट्रक्शन के लिए इनके खिलाफ नोटिसिस इशू कर देते हैं। इसके अलावा अध्यक्ष जी यहां पर एनजीओज आ जाते हैं कि ये तो डेयरियां थी और ये अब तुमने मकान क्यों बना लिए, तो ब्लैकमेलर्स आ जाते हैं इनके पास में। लेकिन मैं आज फिर इस सदन में कह रहा हूं और मेरे ख्याल से जो हमारे अपोजिशन के, बीजेपी के लोग हैं वो भी सहमत होंगे, ये एन्क्रोचर्स नहीं है, इन्होंने कोई सरकारी जमीन पर कब्जा नहीं किया, ये अलॉटिस हैं और अलॉटिस ने जो सुविधाएं नहीं मिलने के कारण इन्होंने अपना लैंड यूज चेंज कर लिया, 80-90 परसेंट लैंड यूज चेंज हो चुका है और आज की जो स्थिति है उसमें केवल एक ही इसका हल निकलता है कि इनको मिक्स्ड लैंड यूज का एक रेंजिडेंशियल या कमर्शिलय में इनको एक ऑफर दिया जाए,..

माननीय अध्यक्षः हो गया।

श्री नरेश यादवः इसमें जो भी रूल-रैगुलेशंस के हिसाब से चार्जिज हैं,..

माननीय अध्यक्षः प्लीज कंक्लुड करिए नरेश जी।

श्री नरेश यादवः वो चार्जिज लिए जाए और जो लीज और लाइसेंस है उसको समाप्त करके इनको ओनरशिप दी जाए, ये मेरी डिमांड है और इस संकल्प को मैं समर्थन करता हूं और माननीय मंत्री जी का भी मैं धन्यवाद करता हूं गोपाल राय जी का, उन्होंने लगातार इस विषय में खूब मीटिंग्स की हैं, सारे डेयरी जो प्रतिनिधि हैं वहां पर आते थे, संतराम जी थे, हमारे यहां से सुशील जी, अमरजीत जी, ये सभी लोग आए हैं और साथ में इसमें जो हमने लीगल के लिए सोमनाथ भारती जी हमेशा हमारे साथ मीटिंग में आएं इनका भी मैं धन्यवाद करता हूं और ये सारी पॉलिसी बनी, कमेटी ने पॉलिसी दी उसके बाद में ये संकल्प आया और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये आगे जाकर पॉलिसी नोटिफाइड भी होगी और इनको ये मालिकाना हक मिलेगा और मिक्स्ड-लैंड यूज में ये इनका लैंड यूज चेंज होगा। बहुत-बहुत शुक्रिया, धन्यवाद अध्यक्ष जी जो आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

श्री सही रामः अध्यक्ष जी, मैं भी चाहूंगा।

माननीय अध्यक्षः सही राम जी देखिए अब यदि इसमें..

...व्यवधान...

श्री मदन लालः ये गांव से जुड़ा मुद्दा है सर।

...व्यवधान...

श्री मदन लालः एक मिनट। गांव से जुड़ा मुद्दा है सर।

माननीय अध्यक्षः नहीं, मदन लाल जी अब इस पर नहीं। केवल मैं, मेरे पास दो नाम और आए हुए हैं।

श्री मदन लालः सर, प्रार्थना ये है कि जितने ये..

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः सही राम जी पहले खड़े हुए हैं, सही राम जी।

श्री मदन लालः प्लीज, एक मिनट।

माननीय अध्यक्षः भई आज, आज विषय जो रह जाएंगे..

...व्यवधान...

श्री सही रामः अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद आपका।

...व्यवधान...

श्री मदन लालः इससे कई लाख लोगों की रोजी रोटी जुड़ी है।

माननीय अध्यक्षः भई मदन जी अब ये एक सेकंड, सही राम जी खड़े हुए हैं न। सही राम जी, एक मिनट में बात पूरी करिए प्लीज।

श्री सही रामः अध्यक्ष महोदय, आप अंदाजा लगाओ कि आज से 48 साल पहले इन डेयरी वालों को वहां बसाया गया था अलग-अलग जगह कि दिल्ली से गाय-भैंस बाहर की जाए, 48 साल पहले इनका

परिवार कितना था जिनको अलॉटेड हुई और आज इनका परिवार कितना बड़ा हो गया होगा 48 साल में, 48 साल में इनका परिवार भी बढ़ा, परिवार के साथ-साथ इनके पशु भी बढ़े होंगे और 48 साल के बाद आपकी जानकारी में आया होगा, अभी जैसा अजेश भाई ने बताया इनके यहां भी एमसीडी और डूसिब के लोग सीलिंग करने गए, वहां भारी हंगामा हुआ, उनको बैरंग वापिस होना पड़ा। इसी तरह से कुछ दिन पहले मदनपुर डेयरी फार्म में भी, मदनपुर खादर की डेयरी फार्म में भी कुछ डेयरियां सील की गई। इस कमेटी का मैं भी मेम्बर हूं, मैंने भी ये प्रस्ताव पहले भी रखा था कि इन लोगों को अध्यक्ष महोदय, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, कमेटी ने भी रिक्वेस्ट की थी, एमसीडी में भी पास हो चुका है कि इनको मालिकाना हक, फ्री होल्ड करके इनको मालिकाना हक दे दिया जाए, इतनी सी बात है उसके लिए कई हजार लोगों के ऊपर तलवार लटकी हुई है। और उसमें दूसरी रिक्वेस्ट मेरी ये है सरकार से भी, निगम में भी कि जब तक इस पर फैसला न हो जाए इनको मालिकाना हक न दिया जाए, तब तक के लिए जो सीलिंग की तलवार इनके ऊपर लटकी हुई है उस सीलिंग को तुरंत रोका जाए।

अध्यक्ष महोदय, एक बड़े मजे की बात है कि ये कार्रवाई कहां से शुरू हुई सबसे बड़ी बात तो ये है। एक एनजीओ ने एनजीटी में केस डाला कि जी सफाई व्यवस्था नहीं हो रही, पशुओं के साथ क्रूरता हो रही है। अध्यक्ष महोदय, सफाई व्यवस्था करना किसकी जिम्मेवारी है ये भी सोचना पड़ेगा आपको। वहां सुविधा देने की जिम्मेवारी किसकी है ये भी सोचना पड़ेगा आपको। अगर वहां ये सब सरकारें, निगम या डूसिब

या डीडीए ये सब फैसिलिटी वहां दे देती तो ये नौबत ना आती नंबर एक। नंबर दो जब परिवार बढ़ा है, पशु बढ़े हैं तो नैचुरल है कि वहां जो काम करने वाले लोग हैं वो भी बढ़े होंगे। अब उनके रहने की व्यवस्था तो करनी पड़ेगी डेयरी वाले को, चाहे वो नीचे डेयरी करके ऊपर अपना मकान बनाए, उससे ऊपर जो काम करने वाले हैं उनके लिए बनाए, ये तो बहुत जरूरी है, सिम्पल सी बात है, ये तो समय की जरूरत है।

माननीय अध्यक्षः सही राम जी कंक्लुड करिए, प्लीज कंक्लुड करिए।

श्री सही रामः अध्यक्ष महोदय, आपसे मेरा निवेदन है कुलदीप भाई जो ये प्रस्ताव लाए हैं इस पर गहनता से विचार करके और जल्द से जल्द एक फैसला लिया जाए कि इनको फ्री-होल्ड करके इनको मालिकाना हक दिया जाए, ये मेरी सदन से रिक्वेस्ट है। बहुत-बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी।

श्री मदन लालः एक मिनट से ज्यादा नहीं बोलूंगा।

माननीय अध्यक्षः मदन लाल जी, अब ये विषय बहुत हो गया, प्लीज।

श्री मदन लालः गांव से जुड़ा मुद्दा है। धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, 1974-75 का वो टाइम है जब इमरजेंसी का टाइम था। दिल्ली के गांवों को शहरीकृत गांव कर दिया गया था। ऐसे समय में जिनके पास

गाय-भैंस थी सबसे सरकार को परेशानी होगी लगी। cow huts खत्म हो गए, चरागाह बंद हो गए, थे ही नहीं। दिल्ली के एक्सपेंशन के साथ-साथ जितनी खेती की जमीनें थी वो सारी मकानों में बदलने लगी। दिल्ली में एशियाड 82 होना था 82 में, सरकार पॉलिसी बना रही थी कि कैसे हम विदेशी लोगों के सामने दिल्ली को प्रेजेंट करेंगे। तो दिल्ली सरकार ने, तत्कालीन दिल्ली सरकार ने जो कांग्रेस की थी और उस समय बी.आर. टमटा कमिश्नर हुआ करते थे एमसीडी के, उन लोगों ने घर-घर जाकर लोगों की गाय-भैंस को जबरदस्ती छीना और चरागाहों में भेज दिया। लोगों ने शोर मचाया तब इन्होंने ये डेयरी फार्म अलॉट करने शुरू किए। इसके पीछे सबसे बड़ा तर्क यही था कि दिल्ली के जहां-जहां डेयरियां हैं लोगों के पास उनके पास सफिशिएंट जगह नहीं है, सिवेक एमेनिटिज, नहीं है सिविक सर्विसेज, लिहाजा इनको कहीं एक और जगह कंसोलिटेड कर दिया जाए। इसीलिए ये 10-11 जो दिल्ली में डेयरी फार्म बने उसके पीछे केवल एक वो ही तर्क था। पर सरकार ने वो बनाई तो सही। पर उसके साथ-साथ उन लोगों को वो मूलभूत सुविधाएं जो वहां दी जानी चाहिए थी क्योंकि केवल जानवर शिफ्ट नहीं होने थे, लोग भी शिफ्ट होने थे, उन लोगों को रहने के लिए साधन देना चाहिए था क्योंकि आनन फानन में बिना किसी सोचे समझे केवल दिल्ली को क्लीन करने की नीयत से, सत्ता उस समय बड़ी ताकतवर थी, इमरजेंसी का टाइम था। उस कारण से.. जितने भी लोग थे गांव के इन सबको विस्थापित किया गया और वहां जगह अलॉट की गई। समय चेंज हो रहा है। दिल्ली में लोगों की तादाद बढ़

रही है। चरागाह खत्म हो चुके हैं। लोगों को जानवरों के लिए साधन नहीं मिलता उनको खिलाने का तो लोग क्या करेंगे। अपने बच्चों को पालने के लिए गाय-भैंस भी रखेंगे और अपने परिवार को भी वहीं रखेंगे। अब लोगों ने वहां मकान बनाने शुरू कर दिए। यहीं प्रॉब्लम हो गई। जितने करप्ट ऑफिसर्स हैं उनको लगता है अब ये लूटने का समय आ गया है, तो कोई न कोई ऑफिसर, कोई न कोई बहाना लेकर वहां पहुंच जाता है, उनको डर दिखाता है, उनको भय दिखाता है, सीलिंग का डर दिखाते है।

माननीय अध्यक्षः मदन लाल जी, कंक्लुड करिए, प्लीज कंक्लुड करिए।

श्री मदन लालः ये ही कारण है कि आज पूरी दिल्ली में हाहाकार मचा हुआ है। सर, वो हमारे लोग हैं। दिल्ली के लोग हैं, दिल्ली की सरकार का हिस्सा है इसलिए हमको उनकी सुननी चाहिए और उनकी मदद करने के लिए हमको पॉलिसी बनानी चाहिए कि वो लोग जहां रहते हैं, आज उन्होंने अपना गांव छोड़ा, अपना घर-बार छोड़ा, अपनी पैतृक जगह छोड़ी, वहां जाकर बसे जंगलों में।

माननीय अध्यक्षः मदन जी, दो मिनट हो गए हैं।

श्री मदन लालः सर, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। उन लोगों की आज की हालत को देखते हुए और उस समय की हालत को देखते हुए सरकार को सहानुभूतिपूर्वक सोचकर उनके लिए न केवल वहीं

स्थापित करने की पूरी की पूरी सुविधा दी जानी चाहिए बल्कि उनको वो परमानेंट रेंजीडेंट के रूप में उनको विस्थापित करना चाहिए वहीं। मैं कुलदीप जी के इस प्रपोजल का स्वागत करता हूं और उनका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने दिल्ली के लोगों के लिए, बहुत एक बर्निंग टॉपिक है, आज हमको उनकी मदद के लिए खड़ा होना चाहिए, मैं उनका समर्थन करता हूं और आपका विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः श्री विजेंद्र गुप्ता जी।

श्री विजेंद्र गुप्ता (माननीय नेता, प्रतिपक्ष): आदरणीय अध्यक्ष जी, दिल्ली की डेयरी कॉलोनी में एमसीडी वहां पर जाकर जिस तरह से कार्रवाई कर रही है, जिस तरह का पैनिक हो रहा है, जिस तरह का आतंक है, मैं इस प्रस्ताव में एक संशोधन इस सदन के समक्ष पेश करना चाहता हूं कि डेयरी फार्मों पर जो कार्रवाई की जा रही है, जो तलवार लटकाई गई है, जो सीलिंग की जा रही है, जो डेमोलिशन किया जा रहा है उस पर तुरंत रोक लगाई जाए। सबसे पहले तो उनको रिलीफ देना है कि जो कार्रवाई हो रही है जिससे हाहाकार मचा हुआ है और कार्रवाई करते वक्त एजेंसिज का..

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः भई उनको बोल लेने दीजिए।

...व्यवधान...

श्री विजेंद्र गुप्ताः एक मिनट, एक मिनट। मैं आपकी बात को ही बढ़ा रहा हूं आगे। जो सही राम जी ने कहा बिल्कुल ठीक कहा। मामला ये अदालत से चला है। एजेंसिज को भी मैं यही कहूंगा कि वो भी कहीं न कहीं बंध गई हैं और हाई कोर्ट के फैसले, एनजीटी के फैसले के कारण ये स्थिति उत्पन्न हो रही है। हमें इस कार्रवाई को तुरंत रोकना चाहिए ये सदन सर्वसम्मति से ये पारित करे और उसके बाद इसमें जो सबसे बड़ी जरूरत है वो ये है कि मालिकाना हक तो दिया ही जाए, इसके साथ-साथ इसका लैंड यूज भी चेंज किया जाए। ब तक लैंडयूज चेंज नहीं होगा, जब तक मालिकाना हक नहीं मिलेगा और उससे पहले ये तोड़फोड़ की कार्रवाई को तुरंत रोक लगाई जाए। इसमें एमसीडी कोर्ट के सामने ये प्ली ले और दिल्ली सरकार से भी हमारी मांग है कि इसमें इंटरवीन करे और इंटरवीन करके एनजीटी में पार्टी बने और असेंबली का पक्ष वहां पर रखा जाए और फिर उसके बाद इसकी तमाम सबसे पहली जरूरत है वहां पर होने वाली कार्रवाई को तुरंत रोका जाए वरना कार्रवाई चलती जायेगी, लोग परेशान होते रहेंगे, लोग तबाह होते रहेंगे और निष्कर्ष कुछ निकल नहीं पायेगा। तो अभी जो आग लगी है उसको तुरंत रोकना चाहिए। उसको बुझाने की जरूरत है और उसमें ये संशोधन करके हम इस प्रस्ताव के पक्ष में हैं।

माननीय अध्यक्षः श्री सोमनाथ जी।

श्री सोमनाथ भारतीः अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस ज्वलंत मुद्दे पर बोलने का मौका दिया आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। इसपे

एकमत जो बनके निकल रहा है हाउस से कि विपक्ष और पक्ष दोनों चाहता है कि इस डेरी के मुद्दे पे जो डेरी के लोग हैं इनके साथ न्याय हो और मैं इस बात को सदन के पटल पर रखना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि जिस प्रकार से केजरीवाल सरकार ने गोपाल राय जी के मार्फत कई मीटिंग्स लीं एक नहीं, कई मीटिंग्स लीं और उन हर मीटिंग में जो फैसले लिये गए, चूंकि ये दूसरा उदाहरण है कि itinerary of the selected versus elected का मैं बड़े विनम्रता के साथ इस बात को रखना चाहता हूँ कि माननीय गोपाल राय जी ने डेरी वालों के साथ होने के लिए जिन-जिन बातों का संकल्प लिया, जिन-जिन बातों का फैसला लिया इन बातों को अधिकारियों ने उस प्रकार से कोर्ट के सामने पेश नहीं किया। मैं कोर्ट में ही था। इस बात का मुझे दुख है कि हमारी सरकार लगातार डेरी वालों के साथ काम कर रही है। उनके साथ न्याय करना चाहती है। 2019 का जो फैसला है उसको जैसे उसमें हर स्टैप्स दिखाये गए, उसके साथ वो काम करना चाहती है। लेकिन अधिकारियों ने अपने मन मर्जी से गोपाल राय जी के आदेश को जैसा उन्होंने कहा वैसा उन्होंने कोर्ट में नहीं रखा और यहां तक कि उन्होंने कभी-कभी तो उल्टा ही रखा। मैं जानना चाहता हूँ विजेन्द्र गुप्ता जी से कि अधिकारियों को ये ताकत कहां से मिलती है कि इलैक्टिड गवर्मेंट के फैसले को उस प्रकार से बिल्कुल कभी-कभी विरोधाभास में, हम कुछ कह रहे हैं वो कुछ कह रहे हैं। मैं कोर्ट में ही था। अध्यक्ष महोदय मुझे लगता है कि उन अधिकारियों ने जिन्होंने सरकार के आदेशों की अवहेलना की उनके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए। मैं चाहता

हूँ कि एलजी साहब तक ये बात पहुंचायें विजेन्द्र गुप्ता जी कि जिन अधिकारियों ने डेरी वालों के विरोध में सरकार की इच्छा के विरूद्ध उन्होंने वहां पे बातें रखीं उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। दूसरा एक तरफ तो पीएम उदय जैसी योजना लाकर के मतलब एकड़ों में जमीने फालतु में दी जा रहीं है उन लोगों को जिनकी ऑलरेडी जमीन है और इस तरफ डेरी वाले जो कई दशकों से बैठे हुए हैं, जो अब डेरी का बिजनेस नहीं कर पा रहे हैं उनको उजाड़ने की तैयारी चल रही है। तो मैं चाहता हूँ कि डेरी वालों को जहां, जैसे वो बसे हुए हैं मकान बन गया, दुकान बन गया जो बन गया उनको मालिकाना हक और चेंज आफॅ लैंडयूज तुरंत किया जाए, उनके साथ ज्यादती ना हो, ये मैं आपके माध्यम से कहना चाह रहा था। तीसरा, बातें जो चल रही है कि जी गाय का दूध मिलना चाहिए, भैंस का दूध मिलना चाहिए, अरे भाई उनको जो सुविधायें मिलनी चाहिए थीं चाहे वो गोबर गैस प्लांट हो, चाहे उनके सीवर की व्यवस्था हो, पानी की व्यवस्था हो वहां अधिकारियों ने उनका साथ नहीं दिया इस कारण से उनकी स्थिति बनी और चौथा भई जिन गायों की, जिन भैंसों की आप वहां पे चिन्ता हाईकोर्ट में करना चाहते हैं वो गायें और वो भैंसे इन डेरी वालों की नहीं हैं मैं ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूँ। डेरी वालों ने अपने गायों की और भैंसों की पूरी चिन्ता की है। वो गार्बेज नहीं खा रहे। जो कूड़ा खा रहे हैं वो उनकी नहीं हैं मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ। इसलिए आवारा पशुओं के साथ डेरी वालों को ना जोड़ा जाए और उनके किये का इनको पनिशमेंट ना दिया जाए। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः कुलदीप कुमार जी ने जो संकल्प सदन में रखा.
.

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः भई अब नहीं देखिए मैं अब किसी को नहीं प्लीज। मैं रिक्वैस्ट कर रहा हूँ..

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः भई ये ठीक नहीं है नरेश यादव जी। ऐसे तो काम नहीं चल सकता। ऐसे तो मैं हैल्पलेश हूँ। मैं सदन नहीं चला सकता। ऐसे सदन नहीं चल सकता। कोई नाम मेरे पास, कोई तो तरीका होगा नाम आयेंगे मेरे पास। ऐसे तो नहीं जो सदस्य.

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः प्लीज, प्लीज। मैं रिक्वैस्ट कर रहा हूँ बैठिए।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः बोलिए, दो मिनट में पूरा करिये प्लीज।

श्री गुलाब सिंहः सर, एक बात बताओ, पहली बात तो मुझे बोलने का इस मामले में तो बिल्कुल राइट है और मुझे ही नहीं बोलने दे रहे हों आप।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः बोलिए, बोलिए।

श्री गुलाब सिंहः अध्यक्ष महोदय बहुत-बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय 2019 में मैं माननीय मंत्री गोपाल राय जी ने एक समिति का गठन किया जिसकी अध्यक्षता करने का मुझे मौका मिला और इस पूरे मामले को बड़ा बारीकी से मैंने समझा। अभी सभी माननीय सदस्यों ने अपने-अपने वक्तव्य रखे। लेकिन इसको समझने की जरूरत है जब करिबन हमारी उम्र जितनी है उस समय ये डेरिया अलॉट की गईं थी 50-50 गज की ये डेरियां हैं जिसके अंदर रूल रेगुलेशन था कि 5 भैंस और तीन-चार बच्चे उनके उस डेरी के अंदर रह सकते हैं। लेकिन जो लोग इन डेरियों में पशुपालन करने के लिए आये थे उनको समझने की जरूरत है वो लोग कौन हैं। कोई बिल्कुल सम्पन्न परिवार से तो आये नहीं वो लोग। वो सब नीडी लोग थे, सबका पशुपालन का लम्बा अनुभव था। ग्रामीण क्षेत्र से आये थे। कोई हरियाणा से आया था, कोई उत्तर प्रदेश के अलग-अलग राज्यों से आये थे और उन्होंने आके दिल्ली के अंदर ये डेरियां खोलीं और जब ये डेरियां खुलीं तो मैं अपने यहां की बात करता हूँ और दिल्ली की सारी डेरियों की बात करूं जिसमें 11 डेरियां जिसमें 3 डूसिब और 8 डेरी जो हैं एमसीडी की है। मेरे यहां पे नंगली डेरी, गोयला डेरी, ककरोला डेरी है और मैं, आप तो हमारे पिता तुल्य हैं और आपने सब कुछ देखा है कभी वहां पे खेत हुआ करते थे। जब इन डेरी के जो पशु हैं वो खेतों में चरने के लिए जाते थे। पशुपालन के लिए वहां पे जमीनें थीं, गाय चराने के लिए भैंसे चराने के लिए जमीनें हुआ करती थीं और सैकड़ों एकड़ में हुआ करती

थीं। तो ईवन ये हालत थी कि एक समय का अगर उनको खाना-दाना ना दिया जाए तब भी काम चलेगा क्योंकि वो चर के आते थे खेतों के अंदर। स्थिति ऐसे पलटी कि धीरे-धीरे, धीरे-धीरे उन डेरियों के आसपास में बहुत सारे अनॉथराइज कॉलोनियां कटीं जिसको फिर बाद में दिल्ली सरकार ने 1739 कॉलोनियों की लिस्ट में डाल दिया और वहां पे डेवलपमेंट के काम हुए सीवरलाइन, पानी की लाइन तमाम काम। लेकिन अब वो डेरी उनके बीच में आ गईं। उन डेरी से निकलने वाले जो नाले हैं वो गोबर से भरे हैं। क्यों भरे हैं क्योंकि अभी तो एमसीडी के अंदर पौने दो साल से आम आदमी पार्टी की सरकार है। गत पिछले 15-20 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। मैं चुनौती देता हूँ किसी एक डेरी में..

...व्यवधान...

श्री गुलाब सिंहः गुप्ता जी पहले जो मैं..

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः विजेन्द्र जी मुझसे बात करिये आप प्लीज।

श्री गुलाब सिंहः गुप्ता जी मैं बारिकी से बड़ी..

...व्यवधान...

श्री गुलाब सिंहः सुनिये बारिकी से अध्ययन करके ये बात बोल रहा हूँ।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः ये बड़ी परेशानी है।

श्री गुलाब सिंहः बारीकी से अध्ययन करके ये बात बोल रहा हूँ कि अगर आपने गोबर गैस प्लांट, अगर आपने गोबर गैस प्लांट ठीक से बना दिये होते तो शायद इस सदन पे आज ये चर्चा नहीं होती नंबर (1)।

...व्यवधान...

श्री गुलाब सिंहः नंबर (2) आठ डेरी एमसीडी की जमीन पे चल रही हैं। एमसीडी को मैं आपको रिटन में दे सकता हूँ एमसीडी को दिल्ली जलबोर्ड ने बार-बार डैफिसिएनसी भेजी कि भैया हमें आप पैसा दे दीजिए। आज डेरी के लोग जो हैं वो पानी कहां से ले रहे हैं। बेचारो ने मजबूरी में सबमर्शिबल कर रखा है। तीसरे दिन एसडीएम पहुंच जाता है वहां पे सील करने के लिए, एमसीडी पहुंच जाती है सील करने के लिए, क्यों? अगर वो आज सबमर्शिबल बंद कर दे तो पशु पानी कहां से पियेंगे मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, सच्चाई है कि नहीं है? तो डैफीसिएंसी निकाली कि एमसीडी वाले भई पैसे दे दो,भाजपा की सरकार थी। एक सिंगल पैसा एमसीडी ने दिल्ली जलबोर्ड को पानी की लाइन डालने के लिए नहीं दिया गया। इसलिए ये नौबत आके खड़ी हुई। धीरे-धीरे करके दूसरा, इनके ऊपर जो बिजली का बिल आ रहा है कमर्शियल आ रहा है। हमने, इस कमेटी ने ये भी रिक्मेंड किया था कि इनको एग्रीकल्चर का रेट दिया जाए। एग्रीकल्चर के बिल इनके

आने चाहिए भईया ये कमर्शियल कहां से दे देंगे? एक भैंस क्या कमा के देती है पशुपालन अगर आप करोगे तो।

...व्यवधान...

श्री गुलाब सिंहः तो ये तमाम सुनिए, सुनिए, सुनिए, सुनिए तो ये..

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः बोल रहे हैं न।

...व्यवधान...

श्री गुलाब सिंहः भाई साहब सुन लीजिए।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः वो सब चीज बोल रहे हैं। चलिए।

...व्यवधान...

श्री गुलाब सिंहः गुप्ता जी चीजों को समझिये। सुनिए, सुनिए अब बात आयी है मिक्स लैंडयूज की, क्यों, मिक्स लैंडयूज का क्या फायदा होगा? अच्छा दूसरी बात क्या कि इन्होंने कच्चे स्ट्रैक्चर बना लिये ऊपर टीन शेड डाल लिया। अब मान लीजिए घर में दो बेटे हैं, दो बेटियां हैं उनकी मदर है, उनके फादर हैं और उनके पिताजी पशुपालन करने के लिए किसी एक डेरी में आ गए। परिवार कहां जायेगा जी, परिवार

को छोड़ के आ जाए। अब वो बेचारा तो 4-5 बच्चों को अपने परिवार को पूरे को लेके वहां पे आ रहा है तो थोड़ा-सा स्ट्रैक्चर बना लिया ऊपर उन्होंने। फिर वो लोग जो उनके साथ मदद करते हैं मजदूर जो हैं जो सुबह भूसा उनको खिलाते हैं, गोबर को उठाते हैं तो वो कहां जायें। तो उन्होंने दूसरी मंजिल बना ली। डेमोलेशन हुआ तो सारी कहानी यहां से निकलकर आती है कि वो लोग थक गए, परेशान हो गए। ईवन कई सारी कॉलोनियों में डेरी वालों को पशुओं के साथ इतनी हीन भावना से देखने लग गए कि हमारे पास आते हैं लोग शिकायत लेके यार इन डेरी वालों को भगाओ यहां से। अरे भाई साहब दूध तो आप वहीं से लेते हो, भगाओ इनको डेरी वालों को। तो हालात ये इसलिए होये कि ना गोबर गैस प्लांट बना, ना पानी की लाइनें डाली गयीं, ना वहां पे एग्रीकल्चर उनके ऊपर रेट लगाये बिजली के। इसलिए ये जो मिक्सलैंड यूज की बात हम कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं कि बिना पोल्यूसन वाला, बिना प्रदूषण वाले छोटे उद्योग वो वहां पे खोल सकें, उनकी जीवन याचिका वहां से चल सके और वहां पे अपना कमर्शियल रेजीडेंस बना सके और उनको मालिकाना हक दिया जाना चाहिए। ठीक वैसे ही जैसे 74(4) की जमीनों की हालत आज दिल्ली के अंदर है आज 74(4)की जमीनों का 99 साल का पट्टा हुआ था कुछ लोगों को भूमिधर का राइट मिल गया, कुछ को नहीं मिला। वो धक्के खाते घूम रहे हैं। ठीक ऐसा इनके साथ हो रहा है। इसलिए मिक्स लैंडयूज इनका आप ये प्रपोजल लेके आयें और सदन ये प्रस्ताव पास करके भेजे। कुलदीप भाई जो संकल्प लेके आते हैं मैं उसका पूरा समर्थन करता हूँ

और इनको मालिकाना हक दिया जाए, लेकिन मिक्स लैंडयूज का ये सदन आज ये प्रस्ताव पास करके भेजे। अभी आपने कहा कि ऊपर तालियां मत बजाइये सर ये उनकी पीड़ा है। ये सारे डेरी वाले बैठे हैं सर आज ऊपर। क्योंकि हम कई वर्षों से इनके साथ में, टच में सारे विधायक साथी।

...व्यवधान...

श्री गुलाब सिंहः मैं इन ढाई लाख लोगों को ये आश्वस्त कर रहा हूँ इस सदन के माध्यम से कि ये मिक्स लैंडयूज, सुनिए गुप्ता जी, लैंडयूज चेंज करने का अधिकार, लैंडयूज चेंज.

...व्यवधान...

श्री गुलाब सिंहः लैंडयूज चेंज करने का अधिकार भी दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय के पास है। मुझे पूरा भरोसा है कि सदन जब ये प्रस्ताव पास करके भेजेगा तो ये पूरी जिम्मेदारी आपकी बनती है कि उस लैंडयूज को चेंज कराने की जिम्मेदारी आपकी है वरना इसके पाप के भोगी आप होंगे और कोई नहीं होगा। बहुत-बहुत शुक्रिया धन्यवाद।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः अब श्री कुलदीप कुमार जी द्वारा प्रस्तुत संकल्प सदन के सामने है।

जो इसके पक्ष में है वो हाँ कहें,

जो इसके विरोध में हैं वे न कहें,

(सदस्यों के हाँ कहने पर)

हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता,

संकल्प स्वीकार हुआ।

श्री विजेंद्र गुप्ताः किस रूल में ये संकल्प पास हुआ है.

...व्यवधान...

श्री विजेंद्र गुप्ताःये तो बताइये?

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः ये रेजोल्यूशन 88 में आता है ना? ये रेजोल्यूशन 88 में विजेन्द्र जी, रेजोल्यूशन 88 में आता है। वो गलती रह गई होगी 88 में आता है।

...व्यवधान...

श्री विजेंद्र गुप्ताः रूल 89 है सर।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः 89 है?

...व्यवधान...

श्री विजेंद्र गुप्ताः 89 है। रूल 89 ।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः चलिए लंच के लिए, लंच के लिए पौने तीन बजे तक हाउस स्थगित किया जाता है।

(सदन की कार्रवाई अपराह्न 2.45 बजे तक के लिए स्थगित की गई।)

सदन अपराहन् 02.54 बजे पुनः समवेत हुआ।

माननीय अध्यक्ष (श्री रामनिवास गोयल) पीठासीन हुए।

माननीय अध्यक्षः अल्पकालिक चर्चा नियम 55 श्री भूपेंद्र जून जी दिल्ली में कानून एवं व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति तथा व्यापारियों को फिरौती और वसूली की खुलेआम धमकी के संबंध में चर्चा प्रारंभ करेंगे। श्रीमान जून साहब।

...व्यवधान...

श्री बी.एस. जूनः धन्यवाद अध्यक्ष जी।

...व्यवधान...

श्री मोहन सिंह बिष्टः अध्यक्ष जी, हाउस के अंदर पुलिस कमिश्नर होना चाहिये, पुलिस का कोई.

माननीय अध्यक्षः नहीं कोई जरूरी नहीं है।

श्री मोहन सिंह बिष्टः ये गलत परंपरा डाल रहे हैं।

माननीय अध्यक्षः एलजी साहब से पूछिये हाउस में कमिश्नर आते नहीं हैं।

...व्यवधान...

श्री मोहन सिंह बिष्टः कोई अधिकारी इसमें नहीं है, कोई तो होना चाहिये।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः चलिये जून साहब शुरू करिये आप।

...व्यवधान...

श्री बी.एस. जूनः धन्यवाद अध्यक्ष जी, धन्यवाद। सर आज..

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः अधिकारी एलजी से, मोहन सिंह बिष्ट जी..

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः चलिये। चलिये बैठिये, ठीक है।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः चलिये शुरू करिये आप।

...व्यवधान...

श्री बी.एस. जून: सर आज सुबह जब अखबार पढ़ा तो दो खबरें नजर आई अखबार में जो हैडलाईन थीं। नंबर (1) कि पीएमओ में एक इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल है..

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्ष: मोहन सिंह बिष्ट जी क्या परेशानी हो रही है। एक सैकिंड रूकिये। एक सैकिंड रूकिये। बैठिये।

...व्यवधान...

श्री मोहन सिंह बिष्ट: कमिश्नर क्यों नहीं बुलाए जा रहे?

माननीय अध्यक्ष: बैठिये। पुलिस कमिश्नर या अधिकारी यहां नहीं आते ये मुझसे ज्यादा आप लोग बेहतर जानते हैं। अब जो भी हो उसको चलायेंगे। उसको चलायेंगे।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्ष: बैठिये।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्ष: डिस्कस करेंगे। पब्लिक की समस्या तो उठायेंगे न।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः नहीं पब्लिक की समस्या किसलिये उठायें,

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः ये एलजी साहब से पूछिये, एलजी साहब से पूछिये क्यों नहीं आते।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः आप छोड जाइये सदन, आपको समय बर्बाद लगता है तो बाहर चले जाईये।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः बैठिये। शुरू करिये। आपको परेशानी हो रही है।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः दिल्ली के लोगों से फिरौती मांगी जा रही है, दिल्ली के लोगों से फिरौती मांगी जा रही है। आपको चर्चा में परेशानी हो रही है.

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः चलिये शुरू करिये।

...व्यवधान...

श्री बी. एस. जून: सर दिल्ली..

...व्यवधान...

श्री बी. एस. जून: सर आज..

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्ष: मोहन सिंह बिष्ट जी, मेरी बात सुन लीजिये, मोहन सिंह जी मेरी बात सुन लीजिये। एक बात सुन लीजिये मेरी पूरी, आप जितना बोल रहे हैं। आप जितना बोल रहे हैं, कायदे कानून से चला रहा हूं मैं, कायदे कानून की बात कर रहे हैं। डेढ साल से कैंटीन की पेमेंट नहीं हो रहा। डेढ साल से कैंटीन की पेमेंट नहीं हो रहा है।..

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्ष: डेढ साल से कैंटीन की पेमेंट नहीं हो रहा है आप बात कर रहे हैं। डेढ साल से कैंटीन की पेमेंट नहीं हो रही। बैठिये, चलिये।

...व्यवधान...

श्री बी.एस. जून: सर टाईम्स ऑफ इंडिया में आज एक न्यूज क्लिप है।

माननीय अध्यक्ष: उलटा चोर कोतवाल को डांटे। बैठिये।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः शुरू करिये, शुरू करिये।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः मोहन सिंह जी बैठिये। चलिये।

...व्यवधान...

श्री बी.एस. जूनः सर टाईम्स ऑफ इंडिया में आज एक न्यूज आईटम..

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः भाई साहब बैठ जाइये।

...व्यवधान...

श्री बी. एस. जूनः अरे सुनो गुप्ता जी, अच्छी बात है।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः मेरे पास कोई..

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः देखिये, बैठिये दो मिनट, दो मिनट, बैठिये।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः सैंकड़ों व्यापारी मुझसे मिलने आ चुके हैं, सैंकड़ों व्यापारी मुझसे मिलने आ चुके हैं गोयल साहब हमसे फिरौती मांगी जा रही है। गैंगस्टर फिरौती मांग रहे हैं।..

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः हां तो भाग लीजिये न उसमें..

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः इसके लिये मेरे पास कोई नहीं आया, इसके लिये। मेरे पास कोई नहीं आया इसके लिये।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः व्यापारी दुखी हैं।

...व्यवधान...

श्री विजेंद्र गुप्ताः ये देखिये ये हालत है दिल्ली की।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः दिल्ली की हालत तो वो बताने जा रहे हैं, सुनने का माद्दा रखिये।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः सैंकड़ों व्यापारियों से, दिल्ली के सैंकड़ों व्यापारियों से..

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः परेशानी हो रही है।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः आप बैठिये, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः विपक्ष के लोग दिल्ली के व्यापारियों से कोई हमदर्दी नहीं रखते, व्यापारी डरे बैठे हैं। गैंगस्टर उनसे मांग कर रहे हैं। गैंगस्टर फिरौती मांग रहे हैं। एलजी साहब के कानों पे जूं नहीं रेंग रही, परेशानी हो रही है आपको। आपकी पोल खुल रही है इसलिये परेशानी हो रही है। बैठिये।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः मार्शल्स प्लीज, मार्शल्स मोहन सिंह बिष्ट जी को बाहर करिये।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः हां तो वाक आउट करिये। वाक आउट करिये।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः बैठिये प्लीज बैठिये।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः चलिये, या तो बाहर चलिये। अजय महावर जी बाहर चलिये। प्लीज या बैठिये शांतिपूर्वक या मुझे मार्शल्स को बोलना पड़ेगा।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः नहीं मार्शल्स करिये बाहर करिये, बाहर करिये या बैठिये या बाहर जाईये प्लीज। मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः नहीं या तो बाहर जाईये या तो बैठिये।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः मैं जिस पे चर्चा करवा रहा हूं, वो मैं..

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः बाहर करिये भई ओम प्रकाश जी को बाहर करिये। अजय महावर को बाहर करिये।

...व्यवधान...

(माननीय अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार मार्शल्स द्वारा श्री मोहन सिंह बिष्ट, श्री अजय कुमार महावर और श्री ओमप्रकाश शर्मा को सदन से बाहर किया गया। विपक्ष के बाकी बचे अन्य सदस्यों द्वारा सदन से वॉक आउट किया गया।)

माननीय अध्यक्षः माननीय सदस्यों को सूचित कर रहा हूं कि कर्नाटका की एस्टीमेट कमेटी के पांच विधायक आज आये हैं उनका मैं सदन की ओर से स्वागत करता हूं धन्यवाद। पिछले दो महीने में व्यापारियों के कई डेलीगेशन मेरे पास आये हैं कि हमसे फिरौती मांगी जा रही है, अखबारों में भी छपा है और ये विषय इतना गंभीर है दो करोड़ से लेके बीस करोड़ तक। एलजी साहब के कानों पे जूं नहीं रेंग रही, जून साहब ने इस विषय पर चर्चा करने का और कल एक चर्चा नियम 55 के अन्तर्गत मांगी है मैं जून साहब से कह रहा हूं अपना विषय रखें।

अल्पकालिक चर्चा (नियम-55)

श्री बी. एस. जूनः धन्यवाद सर। सर आज टाईम्स ऑफ इंडिया में एक न्यूज क्लिप था जिसमें पीएमओ में काम करते हुए इकनॉमिक एडवाइजर काउंसिल की एक डाटा आये जिसमें कहा गया कि दिल्ली की पर कैपिटा इनकम पहले तीन स्टेट्स में है और दिल्ली की इकानॉमी बहुत साउंड है। हम सभी जानते हैं सर दिल्ली का कोई नेचुरल सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। तो ये आम आदमी पार्टी गुड गवर्नेंस। आम आदमी पार्टी की अच्छी पालिसीज़ जिसकी वजह से आज

पर कैपिटा इनकम हमारी, ये जो हमारे साथी बैठे हैं कर्नाटका इनसे भी ज्यादा है। तेलंगाना, दिल्ली, हरियाणा तो सर ये तीन स्टेट्स हैं जो टाप पे हैं। और सर इसकी रीढ़ की हड्डी क्या इतनी साउंड इकानॉमी की रीड की हड्डी है हमारे व्यापारी, हमारे बिजनेसमैन जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है इस स्टेट का। आज सर उसी रीढ़ की हड्डी को तोड़ने का प्रयास हो रहा है। डेली ट्रेडर्स को, बिजनेसमैन को एक्सटोर्शन कॉल आ रही है इंडिया में से भी और अब्रॉड से भी जिनको तरह तरह के थ्रेट दिये जाते हैं और उन थ्रेट्स के अंडर उनको फोर्स किया जाता है कि वो एक्सटोर्शन मनी दें। सर ये सब्जेक्ट ला एंड ऑर्डर का है। दिल्ली में ला एंड ऑर्डर की सिचुएशन एक तरह से बदतर हो चुकी है जो एक रिजर्व्ड सब्जेक्ट है और डायरेक्टली अंडर होम मिनिस्टरी और लेफ्टिनेंट गवर्नर के अंडर है। दिल्ली पुलिस पे आम आदमी पार्टी का, सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है, जो डायरेक्टली लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के अंडर है। दिल्ली पुलिस कोई भी इस बारे में कार्रवाई करने में बिल्कुल असफल रही है उनकी वजह से कोई भी केस सॉल्व नहीं हो रहा है और डेली ऐसी टाईप की इंसिडेंट बढ़ती जा रही हैं। पिछले चार पांच महीने में ऐसी इंसिडेंट्स में 60 परसेंट की बढ़ोतरी हुई है। तो जितने भी व्यापारी लोग हैं, जितने भी ट्रेडर्स हैं वो एक दहशत में जी रहे हैं, एक भय के माहौल में जी रहे हैं और दिल्ली पुलिस उनकी कोई मदद नहीं कर रही। सर जो माहौल आज है उसमें दिल्ली में कौन बिजनेस करेगा, कौन ट्रेडर्स जो है यहां काम करना पसंद करेगा जिससे डायरेक्टली हमारी जो इकॉनमी जो आज इतनी साउंड है वो भी अफेक्ट

हो रही है। एलजी साहब क्या करेंगे, दिल्ली सरकार के जो काम हैं उनको रोकने की कोशिश करते हैं, कभी मोहल्ला क्लिनिक को बंद करवायेंगे, कभी दवाइयां बंद करवायेंगे, कभी स्कूल में जायेंगे, कभी सड़कों पे जा के दिल्ली सरकार के खिलाफ बयान देंगे लेकिन जो मेन इशु है, जो आज ट्रेडर्स को थ्रेट दिया जा रहा है, जो ट्रेडर्स दहशत में जी रहे हैं उनकी कार्रवाई दिल्ली पुलिस से कुछ नहीं करायी जायेगी। इतना मिसट्रस्ट हो गया है दिल्ली पुलिस और व्यापारियों के बीच, बड़े दुर्भाग्य की बात है सर कि व्यापारी डायरेक्टली गैंगस्टर से जो है डील कर रहे हैं। अपनी सेफ्टी के लिये, सिक्योरिटी के लिये, अपने बच्चों के लिये डायरेक्टली वो उनसे डील कर रहे हैं। उन्हें दिल्ली पुलिस पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। आज हालात ये हो गये हैं दिल्ली में किसी भी कार्नर में चाहे दिल्ली साउथ हो, साउथ वेस्ट हो, नई दिल्ली हो, ट्रांस यमुना हो, सब जगह गोलियां चल रही हैं उनके आफिसिज़ पे, उनके जो बिजनेस प्रिमेसिज़ हैं उनको एक तरह से सीज कर लिया गया है इन गैंगस्टर्स के द्वारा और दिल्ली पुलिस के कान पे जूं तक नहीं रेंगती। हमें तो ऐसी भी खबरें मिलती हैं सर कि दिल्ली पुलिस और इन गैंगस्टर्स के बीच भी एक नेक्सस है जिसको ये अरेस्ट करना चाहें, कर लेते हैं और नहीं तो ये एक्सटोर्शन का जो रैकेट है ये डे बाय डे दिल्ली में बढ़ता जा रहा है। ये सिचुएशन बहुत खराब हो जायेगी सर क्योंकि आज ट्रेडर्स, बिजनेसमैन अंडर थ्रेट हैं, कल को एक कॉमन मैन भी इनके बीच में आयेगा। अगर ओपनली गोलियां चलेंगी तो किसी को भी गोली का शिकार होना पड़ सकता है। तो एलजी साहब को विशेष

रूप में इसपे ध्यान देना चाहिये कि जो गैंगस्टर्स की एक्टिविटी डे बाय डे बढ़ती जा रही हैं और जो दहशत का माहौल बिजनेस कम्युनिटी में पैदा हो गया है उसको रोका जाये ताकि स्टेट आगे प्रोग्रेस करे और प्रॉस्पर हो। लेकिन जहां तक सवाल पुलिस का है, पुलिस सिर्फ वही काम करती है जो एलजी साहब कहते हैं, दिल्ली सरकार की एक भी बात नहीं सुनी जाती। तो आपके माध्यम से मैं बस यही कहना चाहता हूं कि जो भी लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज़ हैं उनको कहा जाये कि ट्रेडर्स की और बिजनेसमैन की सेफ्टी, सिक्योरिटी को एंश्योर किया जा सके ताकि ऐसी घटनाओं में कमी आ सके। धन्यवाद सर।

माननीय अध्यक्ष: श्रीमान राजेश ऋषि जी।

श्री राजेश ऋषि: अध्यक्ष जी मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं नियम 55 के अन्तर्गत श्री भूपेंद्र जून जी ने जो मुद्दा रखा है व्यापारियों का, उसको मैं आगे बढ़ाते हुए आपके बीच में बात रखना चाहता हूं। अध्यक्ष जी व्यापारी आज दोहरी मार खा रहा है। स्थिति ये हो गयी है व्यापारियों की कि व्यापारी बेचारे आन लाईन ट्रेडिंग से परेशान हैं क्योंकि उनकी दुकानों पर ग्राहक वैसे ही बहुत कम हो गये हैं। व्यापारी वर्ग ही है जो देश को चलाता है, व्यापारी वर्ग ही है जो जीडीपी को आगे बढ़ाता है और व्यापारी वर्ग ही है जो बेरोजगारी कम करता है अपने यहां नौकरी देकर। लेकिन आज उनका विश्वास पुलिस से बिल्कुल उठ चुका है। स्थिति ये हो गयी है कि जहां भी देखो फिरौती के लिये फोन आते हैं, प्राईवेट नंबर से कॉल आती है और

उसके बाद पुलिस के पास वो जब जाते थे तो पुलिस कुछ नहीं कर पाती। इसलिये वो लोग डर गए और घबराये हुए हैं। आज जो मैंने आज पढ़ा नवभारत टाईम्स। ये नवभारत टाईम्स ने अपने एक आर्टिकल में लिखा है 'कारोबारियों को नहीं है पुलिस पर भरोसा' पुलिस पर उनका भरोसा बिल्कुल खत्म हो चुका है और गैंगस्टर कर रहे हैं सीधा सैटलमेंट क्योंकि उनको डर है कि अगर पुलिस के पास जायेंगे और पुलिस उनके लिये कुछ नहीं करेगी तो वो उनकी हत्या भी की जा सकती है। अभी हाल फिलहाल की एक घटना है दैनिक जागरण की। दैनिक जागरण ने एक फर्श बाजार है जहां बिहार कालोनी के रहने वाले प्रदीप जैन जिनसे 10 करोड़ रूपये की फिरौती मांगी गयी। उन्होंने पुलिस को इंफार्म किया लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। उनको डायरेक्ट धमकी दी गयी कि आप अगर पैसा नहीं देंगे तो आपके पूरे परिवार को मार दिया जायेगा। अब अगले आदमी ने बाहर सैटलमेंट कुछ किया होगा इसलिये आज वो बचा हुआ है। मैं अपने जनकपुरी की आपको बताता हूं। मेरे जनकपुरी में एक कारोबारी हैं, मुझे खबर मिली कि उनको किसी ने गोली मार दी। तो मैं जब उनको हॉस्पिटल देखने गया तो मैंने उनसे पूछा, वो बेचारे बेहोश थे उनके साथ घर वाले थे बोले इनके पास बहुत दिन से रंगदारी मांगी जा रही थी और उनके पेट में दो गोलियां लगी हुई थीं। तो मैंने कहा क्या हुआ फिर उसका, बोले कि हमने रंगदारी नहीं दी, हमने पुलिस को इंफार्म किया, सब जगह किया लेकिन कुछ नहीं हुआ। उन्होंने दो क्रिमिनल आये और उसको खड़े हुए दो पेट में गोली मारके चले गये। फिर उसको फोन करके

कहते हैं कि हमने पेट में गोली मारी है सिर में भी मार सकते थे। अगले आदमी ने कहां बाहर सैटलमेंट किया होगा, उनको फिरौती दी होगी उसके बाद ही आज वो जिंदा हैं और घूम रहा है। अभी हाल फिलहाल की मेरे चाणक्य प्लेस की एक घटना है एक बिल्डर को किसी की कॉल आई कि इतना पैसा तुम्हें देना है वो चुपचाप बेचारा ढूंढते ढांढते कहां पहुंचा और उन्हें चुपचाप फिरौती दी, आज वो काम कर रहा है और बहुत से हमारे यहां से इस तरह रंगदारी जब मांगी जा रही है, फिरौती मांगी जा रही है तो लोग अपना व्यापार छोड़ छोड़ के दूसरे शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं। सर व्यापारी एक ऐसा वर्ग है जो हर चीज से डरता है। जीएसटी वाला आ जाये तो उससे भी डरता है, ग्राहक उससे तेजी से बोले तो वो डरता है, लेकिन वही इस देश को चलाता है। मेरी आपसे यही विनती है कि जो एलजी साहब इस समय कर रहे हैं पुलिस की हालत जो इतनी बिगड़ी हुई है उसको सुधारने के लिये आप कुछ यहां से कुछ प्रयास करें। मैं कल अपने घर गया तो मेरे घर के आगे दो पुलिस वाले खड़े थे जब विधान सभा से गया तो मेरे हाथ में एक उन्होंने नोटिस दिया कि कल आपकी हैं न पुलिस कमेटी की मीटिंग है। मैंने कहा कितने बजे की, दो बजे की, मैंने कहा जी आपको तो पता है कि हमारा हाउस चल रहा है तो हम तो आयेंगे नहीं। वो चाहते ही नहीं हैं कि उनकी कमेटी की मीटिंग में एमएलए पहुंचे क्योंकि जब हम पहुंचते हैं तो अपने क्षेत्र के मुद्दे उठाते हैं। मुद्दे जब उठाते हैं तो उनसे कोई कार्रवाई नहीं होती इसलिये वो बुलाना भी नहीं चाहते। एलजी साहब ने पुलिस की जो दिल्ली में

व्यवस्था कर दी है, ऐसी दुर्दशा हो गयी है कि कोई आदमी अगर पीड़ित है और वो थाने में चला जाता है एफआईआर कराने, पुलिस वाले उसी को बैठा लेते हैं वहां पर। वो दूसरी पार्टी को बुलाके सैटलमेंट करके उसी को बंद करने की धमकी देते हैं, उससे क्रॉस एफआईआर कराते हैं और उसको परेशान करने के बाद एफआईआर उसकी दर्ज ही नहीं करना चाहते है। सर स्थिति ये है लोग विश्वास खो चुके हैं पुलिस से। पुलिस का विश्वास खोने का मतलब है कि दिल्ली में रहना मुश्किल हो जायेगा। जिस तरह पुलिस इस समय गुंडागर्दी कर रही है। अभी जून साहब ने जो मुद्दा उठाया है मैं उसका पूरा समर्थन करता हूं और मैं अनुरोध करता हूं कि विधान सभा इस पर कुछ न कुछ संज्ञान ले ताकि दिल्ली पुलिस को सुधारा जा सके क्योंकि हमारे से पहले की सरकारों में दिल्ली पुलिस, एमएलएज़ के अंडर में आती थीं, एमएलए वहां के जो भी थाने थे उसका चेयरमैन होता था लेकिन आज जो चेयरमैन बना दिये गये हैं वो सांसद बना दिये गये क्योंकि वो बीजेपी के हैं और वो लोग कोई काम नहीं करना चाहते, न पुलिस से पूछना चाहते हैं। आज पुलिस ऐसी स्थिति में है कि व्यापारियों को लूटती है, उनके बीट इंचार्ज जगह जगह ठेलों से पैसे वसूलते हैं, जगह जगह रास्ते में गाड़ियां खड़ी कर देते हैं। तो इस चीज को बदलने की बहुत जरूरत है और मैं दैनिक जागरण और आपके नवभारत टाईम्स को भी धन्यवाद दूंगा कि आपने इस चीज को उजागर किया और पब्लिक के बीच में लाये। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बोलने का मौका दिया।

माननीय अध्यक्षः देखिये अभी मैं जिनके नाम आये हुए हैं पूरा.

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः दो मिनट मैं समय दे दूंगा आपको। कुलदीप कुमार जी।

श्री कुलदीप कुमारः धन्यवाद अध्यक्ष जी और बहुत महत्वपूर्ण विषय आज जून साहब ने इस सदन में रखा है। अध्यक्ष जी, दिल्ली देश की राजधानी है और दिल्ली के अंदर जिस प्रकार से लगातार अपराध बढ़ते जा रहे हैं, अध्यक्ष जी, बड़े बड़े गैंगस्टरों के गैंग दिल्ली में सक्रिय हो चुके हैं जो लगातार व्यापारियों को धमकी देते हैं, उन्हें फोन कॉल करते हैं, उन्हें मारने की धमकी देते हैं और यहां तक कि ये धमकी नहीं है केवल, उनके कारोबार पे, उनकी दुकानों पर गोलियां तक चलाई जाती हैं। अध्यक्ष जी आज दिल्ली के अंदर डर का माहौल बना हुआ है, दिल्ली देश की राजधानी है और मुझे लगता है कि अगर दिल्ली एजुकेशन के अंदर नंबर वन बन सकती है, अगर दिल्ली का नाम एजुकेशन में देश में हो सकता है, हैल्थ में हो सकता है तो कानून व्यवस्था में क्यों नहीं हो सकता अध्यक्ष जी। कानून व्यवस्था के माध्यम से दिल्ली के उपराज्यपाल और देश के गृहमंत्री अमित शाह जी जिनके पास इस देश की, दिल्ली की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, जिनके पास, एलजी साहब के पास दिल्ली की कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी है, आज वो गृहमंत्री अमित शाह जी देश भर की पार्टियों को तोड़ने में लगे हुए हैं। उनका ध्यान एमएलएज को खरीदने में है, उनको डराने में

है, उनको धमकाने में है। उनका ध्यान इस बात में नहीं है कि दिल्ली देश की राजधानी है जहां देश के प्रधानमंत्री तक भी रहते हैं, राष्ट्रपति भी रहते हैं, सारे बड़े-बड़े केंद्रीय मंत्री रहते हैं, उस जगह पर सुरक्षा का माहौल अगर इस प्रकार से है अध्यक्ष जी तो ये बहुत दुःख की बात है और साथ-साथ आज उन दिल्ली के व्यापारी भाइयों को एक सुरक्षित माहौल मिले और केवल व्यापारी नहीं, हमारी माताएं, बहनें, महिलाएं भी आज अपने आपको दिल्ली में असुरक्षित महसूस करती हैं और ये डेटा बताता है केंद्र सरकार का, कि दिल्ली जो है वो आज की डेट में हिन्दुस्तान के अंदर असुरक्षित शहरों में नम्बर एक पर है। तो अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि दिल्ली के लोगों को सुरक्षित माहौल मिले, आज जगह-जगह आप जाएंगे, हमारे अभी कल्याणपुरी के अंदर मुझे याद है मेरी विधानसभा क्षेत्र में आता है, खुलेआम एक लड़के को 5 चाकू मार दिये गए, उसकी डैथ हो गई, रोहित जी के घर के पास अभी खुलेआम गोलीबारी कर दी गई। लगातार पूरी दिल्ली के अंदर जगह-जगह आप लोग ये देखेंगे तो एक जमावड़ा अपराधियों का हो चुका है और क्या उनको ये डर ही नहीं है कि हमें दिल्ली पुलिस पकड़ लेगी या हमें पनिशमेंट मिलेगी, उनको तो लगता है भई अगर हमें पुलिस पकड़ लेगी तो थाने में जाएंगे जो कम्पलेंट जैसे राजेश भाई ने बताया, जो कम्पलेंट करेंगे उसको 6 घंटे बैठाया जाएगा। तो आज मैं कहना चाहता हूं कि थाना लेवल कमेटी, पहले दिल्ली के अंदर थाना लेवल कमेटी होती थी, एमएलए उसका चेयरमेन होता था। आज वो थाना लेवल कमेटी को खत्म इसलिए किया

गया ताकि दिल्ली के अंदर अवैध व्यापार को, अवैध कारोबार को इन जैसे गैंगस्टरों को एक्टिव किया जा सके। मैं कहता हूं अध्यक्ष जी कि दिल्ली विधानसभा के विधायकों की जो थाना लेवल कमेटी होती थी उसको तुरंत प्रभाव में रिस्टोर किया जाए और उन माफियाओं पर अंकुश लगाने का काम हो जिससे हमारे व्यापारी भाई अपने आपको सुरक्षित महसूस कर सकें। उन्हें दिल्ली में व्यापार करने के लिए, कारोबार करने के लिए एक सुरक्षित माहौल मिल सके, हमारी बहन-बेटियों को एक सुरक्षित माहौल मिल सके, बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत आभार।

(अपराह्न 3.20 पर विपक्ष के सदस्य सदन में वापस आ गए।)

माननीय अध्यक्षः श्रीमान सोमनाथ भारती जी।

श्री सोमनाथ भारतीः अध्यक्ष महोदय आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष महोदय अपने साथियों के साथ आपके माध्यम से मैं भी इस बात को कहना चाहता हूं दिल्ली पुलिस को, एलजी साहब को, दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर की मुसीबत बहुत बड़ी हो गई है। मेरे क्षेत्र में लगातार गौतम नगर हो, हुमायूंपुर हो, कालू सराय हो, गोलियॉं चली, चाकूओं से हमला किया गया एक दूसरे के ऊपर। लेकिन डीसीपी से वक्त मांगो मिलने का, एलजी साहब से वक्त मांगो मिलने का, कोई मिलने का वक्त नहीं देता। स्थिति ये आ गई है कि एक डीसीपी ने मुझे यहां तक कह दिया की भाई साहब आपको जो कहना है फोन पर कह दो, जब आप मिलने चले आते हो तो मेरा ट्रांस्फर हो जाता है। तो मतलब

इस प्रकार से डराया, धमकाया गया पुलिस वाले लोगों को की आम आदमी पार्टी के विधायकों को ना मिलो, आम आदमी पार्टी के नेताओं को ना मिलो और जनता त्रस्त रहे और भाजपा के सातों सांसद मस्त रहें। पिछले 11 साल से दिल्ली में सांसद भाजपा के हैं, मैं अपनी साथियों की बात को दोहराना चाहता हूं चूंकि उन्होंने थाना लेवल कमेटी की बात उठाई। एक ही नोटिफिकेशन है जिसके माध्यम से डिस्ट्रिक लेवल कमेटी बनता है और उसी के माध्यम से थाना लेवल कमेटी बनता है। चूंकि डिस्ट्रिक लेवल कमेटी को चेयर करता है रिस्पैक्टिव एमपी इसलिए उसको बनने दिया गया, थाना लेवल कमेटी को हैड करता है रिस्पैक्टिव एमएलए उसको नहीं बनाने दिया गया। आज तक इतिहास में कभी-भी कोई भी नोटिफिकेशन पीसमील मैनर में इंप्लीमेंट नहीं किया गया है, सिर्फ यही नोटिफिकेशन है अध्यक्ष महोदय। मैं आपके माध्यम से चाहता हूं कि एलजी साहब से ये पूछा जाए कि भई आपने थाना लेवल कमेटी क्यों नहीं बनने दिया गया। दिल्ली के अंदर लॉ एंड ऑर्डर इतनी बुरी हालत में है, जगह-जगह डकैतियॉं, चोरियॉं, छीना-झपटी, महिलाओं के साथ छेड़खानियॉं, जो हमारे दुकानदार साथी हैं उनसे फिरौती मांगी जा रही है। हर तरफ यही बोलबाला है। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप एलजी साहब से इस बात को संज्ञान में लेकर के आएं कि थाना लेवल कमेटी क्यों नहीं बनने दिया जा रहा है, उसको तुरंत बनाया जाए, धन्यवाद अध्यक्ष जी।

माननीय अध्यक्षः श्री विजेंद्र गुप्ता जी।

श्री विजेंद्र गुप्ता (माननीय नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष जी, दिल्ली में पुलिस को लेकर के यहां पर चर्चा रखी गई है, लेकिन हमारा कहना है कि कुछ मुद्दे ऐसे हैं सीवर है, पानी है।

माननीय अध्यक्ष: पुलिस को लेकर नहीं रखी गई है।

श्री विजेंद्र गुप्ता: ये तमाम मुद्दे जो सीधे तौर पर...।

माननीय अध्यक्ष: विजेंद्र जी कानून व्यवस्था को लेकर रखी गई है, पुलिस को लेकर नहीं रखी गई, कानून व्यवस्था को लेकर रखी है।

श्री विजेंद्र गुप्ता: जी, कानून व्यवस्था से तो पुलिस जुड़ ही जाती है ना।

माननीय अध्यक्ष: हाँ विषय है उनका।

श्री विजेंद्र गुप्ता: लेकिन उन तमाम मुद्दों पर विपक्ष के बार-बार कहने के बाद भी, अब टूटी हुई सड़कें हैं, अगर सदन में हम ये बात उठाना चाहते हैं।

माननीय अध्यक्ष: बोलने दें।

...व्यवधान...

श्री विजेंद्र गुप्ता: तो उसपर आप बात नहीं करने देंगे। लेकिन सड़क पर जाकर पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर खुद, सड़क टूटने की जिम्मेदार और अब कह रही है हम बनाएंगे। 6 महीने से आपने क्या किया?

आप तो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थी। तो सवाल ये है कि जो बात यहां पर आई है।

माननीय अध्यक्षः विजेंद्र जी।

श्री विजेंद्र गुप्ताः मैं उसपर आपको बताना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्षः विजेंद्र जी।

माननीय अध्यक्षः एक सैकंड। दिल्ली के, बंदना जी एक सैकंड। दिल्ली के व्यापारियों से फिरौती मांगी जा रही है, अखबारों में छप रहा है।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः एक सैकंड रूकिये भई।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः भाई साहब बैठिये जरा, बैठ जाइये। विजेंद्र जी बैठिए।

श्री विजेंद्र गुप्ताः लॉ एंड ऑर्डर का विषय है वो भी।

माननीय अध्यक्षः जो फिरौती मांगी जा रही है। आज के दैनिक जागरण में भी आया है, कल नवभारत टाइम्स में भी आया आज कि व्यापारी खुद इतने भयभीत हो गए हैं, उन गैंगस्टर से डायरेक्ट बात कर रहे हैं। क्या दिल्ली के व्यापारियों की लाइफ की चिंता नहीं।

श्री विजेंद्र गुप्ताः मुझे आपने समय दिया मैं मुद्दे पर।

माननीय अध्यक्षः आइये, उसी विषय पर आइये।

श्री विजेंद्र गुप्ताः अध्यक्ष जी दिल्ली के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की जो इशू की बात की जा रही है, जो दिल्ली पुलिस से जुड़े हुए मामले है। उसमें साफ है ये दिल्ली जो एक मैगा मैट्रो पोलिटिन सिटी है और इस मैगा मेट्रोपोलिटिन सिटी में लार्जेस्ट मैट्रो पोलिटिन सिटी भी अगर मैं कहूं thickly populated, highest density वाली जिसको कहते हैं दुनिया की शायद ये जापान, टोक्यो के बाद सबसे यहां की density जो है वो सबसे ज्यादा है और यहां पर जो क्राइम है, किसी भी प्रकार का, उस क्राइम के अगेंस्ट जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए और उस जीरो टॉलरेंस के साथ हम लोग यहां चर्चा कर रहे हैं, लेकिन इसी सरकार को, इसी सदन को, इस लॉ एंड ऑर्डर को संभालने के लिए जो लोग लगे हैं उनपर पूरा विश्वास है और उसका कारण ये है कि मेरे पास एक सूची है, 27 उन पुलिस पर्सनेल की जिनको दिल्ली की सरकार ने उनके शहीद होने पर 27 पुलिस कर्मियों को एक-एक करोड़ रुपया दिया है। तो कहें तो मैं पढ़ भी सकता हूं इनके नाम लेकिन समय लग जाएगा और ये कोई एक दिन में नहीं दिया, ये अलग-अलग विभिन्न दुर्घटनाओं या अलग-अलग प्रकार की इसी प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए जो उन्होंने कदम उठाए और उनकी जान चली गई, उसके लिए ये एक-एक करोड़ रुपया आपने दिया है। तो हमारा ये कहना है कि हमारा जो लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम है, अब लॉ एंड ऑर्डर की जब बात आती

है तो ठीक कहा जितेंद्र महाजन जी ने कि मुख्यमंत्री जी के घर में क्राइम हो गया, महिला को पीटा गया। तो क्राइम जब होता तो इमीजेट वहां पर किस तरह का प्रोटैक्शन हो सकता है वो एक बात है लेकिन हॉं क्राइम करके कोई भाग नहीं सकता और इसलिए वो विभव, वो भाग नहीं पाया, जेल चला गया। इसी तरह और भी जितने क्रिमिनल एक्ट हैं, जो आप कह रहे हैं फिरौती की बात आ रही है या कोई भी आ रही है। हम ये अपेक्षा करते हैं पुलिस से क्योंकि दिल्ली में इस तरह की हरकत करके कोई फ्री नहीं घूम सकता, उसको बख्शा नहीं जाना चाहिए और सिर्फ उसको बख्शा नहीं जाना चाहिए बल्कि ऐसे तमाम गैंग या ऐसे लोग जिनके तार जहां भी जुड़े हैं उनको जड़ से खत्म करने की जरूरत है। अध्यक्ष जी इसी शहर में पूरी दुनिया ने हमारे लॉ एंड ऑर्डर को, हमारे ट्रैफिक सिस्टम, ट्रैफिक जाम एक विषय है, लेकिन ट्रैफिक व्यवस्था जो बनाई गई जी-20 में, जी-20 में जो व्यवस्था हुई उसकी पूरी दुनिया ने तारीफ की। बहुत सारी चीजें हैं यहां पर कहने की लेकिन मैं आज इतना जरूर कहूंगा कि ये सदन।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः चलिए, चलिए।

...व्यवधान...

श्री विजेंद्र गुप्ताः ये सदन इस पर चर्चा करे, लेकिन उसपर राजनीति ना करे और हम आपने जो मुद्दा बोला है अध्यक्ष जी मैं

आपके, आप अध्यक्ष हैं हमारे। मैं आपको पूरा सम्मान करता हूं, दिल की गहराइयों से, आपकी पीड़ा जायज है और आपने जो पीड़ा व्यक्त की है उसका समाधान होना चाहिए और इस तरह की अगर व्यापारियों के साथ कोई भी दुर्व्यवहार या फिरौती की बात आई है सामने जो खबरों में आ रही है, इस सदन की भावनाओं के साथ जुड़ते हुए ऐसी घटनाओं को तुरंत इन पर लगाम लगनी चाहिए और जो लोग इस तरह के कामों में ऐसे एंटी सोशल एलीमेंट, ऐसे गुंडा एलीमेंट, ऐसे फिरौती, मर्डर करने वाले लोगों को तुरंत पुलिस के शिकंजे में आना चाहिए, पकड़ा जाना चाहिये और उनको जड़ से समाप्त करना चाहिए, धन्यवाद।

...व्यवधान....

माननीय अध्यक्षः भई शिव चरण जी अब नहीं, प्लीज। अब समय नहीं है।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः भई सोमनाथ जी आप बोल चुके हैं ना प्लीज, नहीं मैं अब समय नहीं दे रहा हूं। केवल एक महिला को लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पर बंदना जी बोलेंगी और किसी को मैं, केवल एक महिला सदस्य को मैं समय दे रहा हूं। सोमनाथ जी बैठिए प्लीज, बैठिए। बंदना जी, केवल बंदना जी, बस।

श्रीमती बंदना कुमारीः अध्यक्ष जी आपका शुक्रिया आपने बहुत ही ज्वलंत मुद्दे पर मुझे बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष जी, दिल्ली में

लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था इतनी दयनीय हो चुकी है, एक चीज़ को बचाना सरकारी चीज़ को बचाना बड़ी मुश्किल हो गया है। सरकारी प्रोपर्टी को बचाना मुश्किल हो गया है, पीडब्ल्यूडी की ग्रिल रातोंरात काट ली जा रही है, टाइल रातोंरात उड़ जा रही है, हर चीजों को बचाना लॉ एंड ऑर्डर, सब एक-एक चीज़। लेकिन अध्यक्ष जी एक छोटा सा वाक्या, मैं वो छोटा सा वाक्या बताना चाहती हूं। एक दिन मेरे एक जेजे कलस्टर जीपी ब्लॉक जेजे कलस्टर पीतमपुरा में मैं गई। वहां पर टॉयलेट नहीं है, बहुत दिनों से टॉयलेट नहीं है। डीडीए की एक लैंड थी, पहले हम लोग वहां पर टॉयलेट बनाने गए, पुलिस से हमने कहा आज मैं यहां पर टॉयलेट का उद्घाटन करने जा रही हूं और लिखकर दिया कि हो सकता है लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था बिगड़ सकती है, आप वहां पर अपना कुछ साथी भेज दीजिएगा। मैं लिखकर उनको पहले बोलकर लिखित रूप में देकर आई। एक भी पुलिस के साथी नहीं आए, वहां पर टॉयलेट बनाया, डूसिब की जगह पर टॉयलेट बन रही थी, टॉयलेट का उद्घाटन करने मैं गई और भाजपा के कुछ साथियों ने हमारे कार्यकर्ताओं पर, हम पर बुरी तरह से वार किया और 100 नम्बर कॉल मैंने किया, 100 नम्बर कॉल होने के बावजूद भी एक भी पुलिस वहां पर नहीं आई और लास्ट में जब मैंने जाकर थाने में दिया, अपनी रिपोर्ट लिखवाई, थाने में रिपोर्ट देकर सचिवालय में हमारा एक प्रोग्राम था, मैं सचिवालय में चली आई। रास्ते में एसीपी साहब को फोन करती गई, जो सर ये बहुत ही ऐसी दुर्घटना थी आपका एक भी पुलिस ऑफिसर नहीं था, मैंने थाने में कम्पलेंट दे दिया है, इस पर

कार्रवाई करिएगा। थोड़ी देर बाद मेरे पास में एसीपी साहब का फोन आता है, कहते हैं चूंकि मैडम आपने तो कोई एप्लीकेशन दिया है वो जायज़ नहीं है, उसपर एक भी धारा नहीं बनती, जो complainer है जो अगेंस्ट में, जिसकी बात अभी चल रही है, जो एक क्रॉस एफआईआर करवाओ। ये पुलिस का धंधा बन गई है, जो क्रॉस एफआईआर करा के उनकी कम्पलेंट में आपके ऊपर 10 धारा लगती है। उन्होंनें जो कम्पलेंट कराई है, जिन्होंने मारा मुझे, मेरे साथियों को मारा, मेरी पूरी टीम को मारा, उन्होंने मेरे ऊपर 10 एफआईआर बनाई है और वो एफआईआर कहां लिखी जा रही है, मौर्या एन्कलेव पीतमपुरा थाने के अंदर बैठकर। थाने के अंदर बैठकर लिखी जा रही है अध्यक्ष जी और उस पर क्या-क्या धारा थी पता है, जो मेरे हसबैंड बीमार थे, साइट पर थे भी नहीं और उनपर लिखा है लड़कियों की तूने छेड़छाड़ करी। ऐसी-ऐसी एक्ट दुनिया भर की एक्ट लगा दी गई और कहा गया आप बताओ क्या करें? करते हो समझौता कि जेल में डालूं और एसीपी साहब ने मुझे कहा कि मैंने साहिब सिंह वर्मा जी के भतीजा को पीटा है, पकड़कर थाने में और मतलब उनका इन्डायरेक्टली धमकी ये था जो आपके सारे कार्यकर्ता को और आपके हसबैंड को पीटूंगा, मारूंगा क्या कर लोगे आप। इस तरह की धमकी दी गई और सारी जगह मैं मिन्नत करती रही, डीसीपी साहब को फोन किया, सर इस तरह की घटना है एक-एक चीज़ सर्च करिये और मेरे हसबैंड की हालत इतनी सी, आज तक मैंने कोई केस वापस नहीं लिया और पहली बार जीवन में मुझे समझौता करनी पड़ी थाने में। मुझे समझौता करनी पड़ी क्योंकि मेरी

हसबैंड की हालत खराब थी और कहा गया जो तुम समझौता करो, समझौता नहीं करोगे तो सबको जेल में डालूंगा और सबको मिलकर पीटूंगा। तो ये तो पुलिस की स्थिति है, जो कम्पलेंट करेगा, उसी को धमकाया जाएगा, उसी को डराया जाएगा। आज पूरे देश में नहीं, पूरे जगह लोग दहशत में है, पुलिस से डर रहे है, पुलिस से डरे हुए हैं, कहां शिकायत करेंगे कोई। अध्यक्ष जी आज ये सदन को जो थाना लेवल कमेटी हुआ करती थी। अब जैसे मान लीजिए अभी डिस्ट्रिक लेवल कमेटी अभी भाई साहब ने कहा, जो कि आया हमें निमंत्रण, हमें भी निमंत्रण आई, एक बार निमंत्रण आई। तो सिर्फ विधायक जाएगा अकेले, कोई और साथ नहीं जाएगा, ना आरडब्ल्यूए जाएगी, ना सीनियर सिटीजन, एसोसिएशन के लोग जाएंगे और कोई नहीं जाएगा, सिर्फ विधायक जाएगा। विधायक को तुम ऐसे-तैसे करके उनके सब भाजपा के सब लोग जाएंगे। डिस्ट्रिक लेवल कमेटी की मीटिंग होती है, आप हर की फुटेज चैक करवाइये, हर में सिर्फ भाजपा के लोग भरे होते हैं, सिर्फ भाजपा के लोग भरे होते हैं, वो डिस्ट्रिक लेवल कमेटी में सिर्फ विधायक को सिर्फ अकेले जाना अलाउ है। विधायक हर जगह जाएगा अकेले। वहीं पर विधायक को दस तोहमत लगाकर निकाल देंगे। इनके पास एक हथियार बहुत अच्छा है जो आज स्वाति जी ने चाहे विभव भाई पर हुई। एक हथियार इनपर बहुत अच्छा है हमें छेड़ा, हमें मारा, हमें काटा, यही हथियार लेकर घूमते हैं ये। आज उस तरह के दिल्ली में जो स्थिति बना दी है, जो आज सब पर, सब घर में हर आदमी को, हर भाई को, हर लोगों को लगता है, जो ये हथियार बड़ा अच्छा है। भाजपा कार्यकर्ता को आगे करो मुझे छेड़ा गया।

माननीय अध्यक्षः चलो, बंदना जी कन्कलूड करिये प्लीज़।

श्रीमती बंदना कुमारीः तो ये चीजों को कैसे कंट्रोल होगा। अध्यक्ष जी हम सबको मिलकर सोचना पड़ेगा जो ये कैसे कंट्रोल होगी दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था सही होगी। इस बात के लिये ये सदन को गंभीरता से लेनी पड़ेगी नहीं तो पूरी दिल्ली क्या पूरा देश डरा पड़ा है।

माननीय अध्यक्षः अब कन्क्लूड करिये।

सुश्री बंदना कुमारीः और इसको ठीक करना पड़ेगा, बहुत–बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

माननीय अध्यक्षः चर्चा का उत्तर माननीय मंत्री सौरभ भारद्वाज।

माननीय मंत्री (श्री सौरभ भारद्वाज): अध्यक्ष जी, जून साहब ने जो मुद्दा उठाया बेहद गंभीर है और जैसा कि बंदना कुमारी जी ने अभी बोला कि शहर के अंदर कानून व्यवस्था खराब होती जा रही है। विजेंद्र गुप्ता जी ने भी बताया कि जी–20 के अंदर ट्रैफिक सुचारू रूप से चला मगर ये नहीं बताया कि जी–20 पर ट्रैफिक सुचारू चल सके इसके लिये सारे स्कूल, कॉलेज, दफ्तर सब बंद कर दिये गये थे दिल्ली में क्योंकि केन्द्र सरकार को मालूम था कि ट्रैफिक पुलिस की हालत इतनी खस्ता है कि अगर आप जी–20 के दौरान दिल्ली को उसी तरीके से चलायेंगे तो आपके जी–20 में आने वाले लोग अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच ही नहीं पायेंगे। तो ये जिस तरीके से जी–20 के दौरान सब

स्कूल, कॉलेज, दफ्तर सब बंद किये गये ये केन्द्र सरकार और ट्रैफिक पुलिस या कह सकते हैं दिल्ली पुलिस या कह सकते हैं एल.जी. साहब की कार्यप्रणाली को साफ जो है दिखाता है और मैं सिर्फ पुलिस को दोष नहीं दूंगा, इसके अंदर आप किसी भी थाने में चले जाईये एसएचओ का जो रूम होता है वहां पर एक टेबल लगी होती है कि इस थाने की स्ट्रैन्थ कितनी है, कॉन्स्टेबल है, कॉन्स्टेबल, एएसआई, एसआई उस टेबल में आपको दिख जायेगा कि जितनी स्ट्रैन्थ उस थाने की होनी चाहिये उसमें करीब 30 परसेंट कमी है, कई-कई जगह 40 परसेंट कमी है। जब आपके पास बीट कॉन्स्टेबल है ही नहीं तो बीट पर जायेगा कौन। आपके पास एएसआई नहीं है, एसआई नहीं है, इन्वेस्टिगेशन करेंगे, law and order देखेंगे, कोर्ट में जाकर जो है गवाही देंगे, क्या-क्या करेंगे। तो ये एक सौतेला व्यवहार केन्द्र द्वारा किया जा रहा है और इसके अंदर सबसे पहले जरूरी तो ये है कि भर्तियां की जायें, पुलिस की रिक्त जो स्थान है उनकी भर्तियां की जायें और जिस तरीके से एल.जी. साहब बहुत जोश से दिल्ली की चुनी हुई सरकार के कामों के अंदर निरीक्षण करने जाते हैं, कभी नाले पर चले जाते हैं, कभी सड़क पर चले जाते हैं मतलब किसी भी चीज़ का उनको पता चलना चाहिये कि दिल्ली सरकार ये काम करने वाली है, इसका टेंडर हो गया है, इसका वर्क आर्डर हो गया है, तो एक दिन पहले वहां पर जाकर निरीक्षण करने चले जायेंगे ताकि उन लोगों को ऐसा लगे कि ये करवा रहे हैं। फ्ल्ड विभाग का काम होने वाला था हमारे सुरेंद्र कुमार जी बैठे हैं कहां गये हां, ये बेचारे मेरे पास दो बार दफ्तर में आये, मीटिंग की, हमने इनके काम को करवाया, वर्क ऑर्डर हो गया, टेंडर

हो गया इन्होंने उद्घाटन कर दिया, उसके बाद एल.जी. साहब चले गये अखबारवालों को लेकर वहां पर कि ये हालत बहुत खराब है, सिर्फ इसलिये ताकि लोगों को ऐसा लगे कि एल.जी. साहब ने करा दिया है। तो मेरे को इसमें कोई एतराज नहीं है, वो जायें, घूमें मगर कम से कम थानों में भी तो जायें। दिल्ली में 400 थाने हैं, वहां भी जायें ना। रोज़ एक थाने में जायें शाम को, वहां देखें कि आज हमारी बहन-बेटी थाने में घुसकर कम्प्लेंट कराना नहीं चाहती है क्योंकि माहौल ऐसा है थानों के अंदर। रात को जायें, गश्त लगायें इलाकों की कि क्या वहां पर बीट कॉन्स्टेबल आ रहा है, नहीं आ रहा, क्या पुलिस की चौकियां जो रात को लगी हुई हैं वहां पर पुलिस वाले बैठे हैं नहीं बैठे, बैठे हैं तो क्या नशे में धुत्त बैठे हैं या चौकस बैठे हैं। देखिये तो सही। तो ये बहुत जरूरी है कि केन्द्र ने अगर ये जिम्मेदारी जबरजस्ती हड़पी हुई है कि दिल्ली की कानून व्यवस्था को केन्द्र देखेगा तो केन्द्र जो है इसकी जिम्मेदारी भी ले, ये बहुत जरूरी है और मेरा भारतीय जनता पार्टी के साथियों से भी निवेदन रहेगा कि दिल्ली पुलिस की एक तो भर्तियां करायें और एल.जी. साहब को अपने केन्द्र सरकार की तरफ से निर्देश दें कि वो रोज़ एक थाने में जो है जाकर जो है उसका निरीक्षण करें और उसकी प्रैस रिलीज़ दें। भई जैसे दिल्ली के बारे में प्रैस रिलीज़ देते हैं कि यहां ये नहीं हो रहा, यहां ये नहीं हो रहा, वहां पर भी जायें, निरीक्षण दें और एक प्रैस रिलीज़ दें ये मेरा जो है निवेदन रहेगा और चर्चा जो है जून साहब ने शुरू की मैं उनका भी बहुत धन्यवाद करता हूं क्योंकि एक बहुत जो है जरूरी ये मामला था, इस पर चर्चा होनी जो है बहुत दिनों से ड्यू थी, धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः अल्पकालिक चर्चा नियम-55 श्री मदन लाल जी निर्वाचित सरकार को अस्थिर करने के उद्देश्य से केन्द्रीय एजेंसियों द्वारा प्रवर्तन निदेशालय द्वारा केन्द्रीय जांच ब्यूरो एंव आयकर विभाग का दिल्ली सरकार के मंत्रियों, विधायकों के विरूद्ध दुरूपयोग के संबंध में चर्चा प्रारंभ करेंगे।

श्री मदन लालः धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस विषय पर बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष महोदय, 28 दिसम्बर, 2013 दिल्ली में पहली बार लोगों की एक बहुत पंसदीदा सरकार जिसका एक सबसे बड़ा उद्देश्य था करप्शन फ्री सरकार देना लोगों को। उस समय की हालतों को देखते हुये हालांकि ये सरकार पूर्ण रूप से सक्षम नहीं थी, कांग्रेस ने इसे unconditional support किया और सरकार बन गई। माननीय केजरीवाल जी के नेतृत्व में बनने वाली ये सरकार ने आते ही सबसे पहले करप्शन को खत्म करने के लिये काम करना शुरू किया, उसके बाद बिजली, पानी की सुविधायें लोगों को देनी शुरू कीं और एक जनलोकपाल को जो उन्होंने पास कराया था उसको क्योंकि कांग्रेस स्पोर्ट नहीं कर रही थी, माननीय केजरीवाल जी ने ये सरकार 14 फरवरी, 2024 को छोड़ दी। कुछ दिन और गुजरे 14 फरवरी, 2015 इलैक्शन हुआ और लोगों ने पूरे बहुमत के साथ उस सरकार को दोबारा चुना और इस बार 67 लोग 70 में से आम आदमी पार्टी के और 03 आदमी बीजेपी के चुने गये। कांग्रेस का लोगों ने बिल्कुल सफाया कर दिया, जिनका पहली बार 08 लोग थे और जिन्होंने unconditional support तो दी थी पर सरकार को सपोर्ट दिल से नहीं किया था।

यही कारण था कि उस समय जन लोकपाल बिल पास नहीं हो पाया। इस सरकार ने आते ही ना केवल जन लोकपाल बिल को पास कराया बल्कि लोगों के लिये जो जरूरी सुविधायें थीं उनको देने का काम किया। ये बीजेपी के लिये एक चुनौती बन गये थे क्योंकि 2014 में केन्द्र में एक नई सरकार आई और उस सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने आते ही दिल्ली की सरकार को क्योंकि उन्हें लगा ये उनके लिये चैलेंज है। जब पूरे देश में उनका परचम फहरा रहा था तो उन्हें लगा कि ये दिल्ली में जहां उनकी सरकार स्थापित है अगर वहां कोई एक नई सरकार होगी तो उनके लिये चुनौती होगी। उन्होंने दिल्ली की सरकार को तंग करना शुरू कर दिया और हमारे विधायकों को लोभ और प्रलोभन देना शुरू कर दिया। इस कड़ी में सबसे पहला नाम था बिन्नी का। हमारी पार्टी के एक एमएलए थे, पार्टी के साथ जुड़े हुये थे, बीजेपी के प्रलोभन में आकर उन्होंने हम आम आदमी पार्टी के खिलाफ बातें करनी शुरू कर दीं। ये पहला वाकिया था जब बीजेपी ने हमारे एमएलएज़ को allure करना शुरू कर दिया, बहकाना शुरू कर दिया और उसके बाद उन्होंने इस सत्ता को derail करने के लिये, इस सत्ता को खत्म करने के लिये, इस पार्टी को खत्म करने के लिये, इस सरकार के कामकाजों को रोकने के लिये एक षड़यंत्र रचा और बिन्नी के बाद चाहे वो करतार सिंह जी तंवर साहब हों, चाहे वो हमारे एक मंत्री राजकुमार आन्नद जी हों और राजकुमार आन्नद जी तो हमारे साथ India के corruption से जुड़े हुये थे, उनके यहां जब 23 घंटे की रेड हुई तब उन्होंने लोगों को टेलिविज़न में कहा कि मेरा कुसूर केवल ये

है कि मैं आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता हूं, लोगों की भलाई के लिये काम करने वाली सरकार का हिस्सा हूं और ये सरकार जो अनुसूचित जनजातियों के भले के लिये काम कर रही है उसके एक अनुसूचित जाति के एक मंत्री को बर्दाशत नहीं कर रही है। परन्तु कुछ दिन बाद जब उन्हें दोबारा एक ईडी का नोटिस मिला तो उन्होंने हमारी पार्टी से इस्तीफा दे दिया और 10-07-24 को वो हमारी पार्टी छोड़कर चले गये। पर बीजेपी को इससे चैन नहीं था क्योंकि केवल तीन मात्र से उनका काम नहीं चलता था। उन्हें तो दिल्ली की सरकार के अच्छे कामों को रोकना था इसलिये लगातार वो हमारे लोगों को तंग करते रहे और उसमें उन्होंने अपने लोग हमारी पार्टी के लोगों को बहकाने, लालच देने के लिये छोड़ना शुरू कर दिया। उसी कड़ी में एक नाम था संजय पालीवाल नाम के एक एडवोकेट का, वो पहले मेरे पास आया था, मैं चूंकि पटियाला हाउस में वकालत करता था इसलिये उसकी रिपोर्ट नहीं की। वो बाद में बंदना कुमारी जी के पास जा पहुंचा, सर मैं बिल्कुल बहुत कट शोर्ट कर रहा हूं। मैं अपनी बात को जल्दी खत्म, मैं आपको बता रहा हूं ये सरकार कैसे बीजेपी हम लोगों को तंग करके हमारी सरकार को खत्म करना चाहती थी और ये सिलसिला अब से नहीं शुरू हुआ है 2014 से जब से हमारी सरकार बनी है तब से कर रहे हैं। बंदना कुमारी जी के घर गया, बंदना कुमारी जी ने पुलिस को रिपोर्ट की, एक मुकद्मा दर्ज कराया, बीजेपी शांत नहीं हुई तब भी उसके बाद एक और मैम्बर था शेर सिंह डागर वो दिनेश मोहनिया जी के पास जा पहुंचे और दिनेश मोहनिया जी फिर उससे संतुष्ट नहीं थे उनके बहकावे

में नहीं आ रहे थे, दिनेश मोहनिया जी ने एक रिपोर्ट लिखाई और एक मुकद्मा दर्ज किया। स्पीकर साहब मुझे 20 करोड़ का ऑफर मिला, मैंने पार्टी में भी बताया, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी बताया, संजय सिंह जी के साथ मैं तीन दिन प्रैस कान्फ्रैंस करता रहा। ये तरीका था इनका इस पार्टी को खत्म कर इसके लोगों को बरगला के, बहका के, तोड़कर आम आदमी पार्टी को छुड़वाने का। स्पीकर महोदय, दिल्ली की इस पोपुलर गर्वमेंट ने 17-11-2021 को एक्साइज़ पॉलिसी बनाई। एक्साइस पॉलिसी बनने के बाद अगर हम देखें कि क्या इन्होंने जब देखा कि हमारे एमएलएज़ नहीं टूट रहे हैं। ये सिलसिला जो वहां 2013-14 में शुरू हुआ था उससे उनको कामयाबी नहीं मिल रही थी, मात्र बिन्नी के चले जाने के बाद हमारी पार्टी में से कोई और आदमी हिला नहीं था। तब इन्होंने एक्साइज़ के केस को ढूंढना शुरू कर दिया और उसमें एक मुकद्मा दर्ज कर बहुत सारे लोगों के खिलाफ एक्शन लेना शुरू कर दिया। उसी कड़ी में अगर आप देखें तो जो सबसे पहले 1947 में FERA नाम से Foreign Exchange Regulation Act के लिये Ministry of Finance की तरफ से एक डिपार्टमेंट बनाया गया था उसी को बाद में बदलकर इन्होंने 2002 में सर PMLA Act में बदल दिया और PMLA को 2005 में इन्होंने ईडी को एक डिपार्टमेंट के रूप में परमीशन दे दी कि वो इनके खिलाफ एक्शन ले और सबसे पहले उसके विक्टिम हम होने लगे। इसी कड़ी में जहां एक और UPA की गर्वमेंट..

माननीय अध्यक्षः मदन लाल जी प्लीज़ शोर्ट करिये, कन्क्लूड नही कन्क्लूड करिये, जल्दी कन्क्लूड करिये।

श्री मदन लालः एक अगले मिनट में खत्म करूंगा। जहां उन्होंने 1797वें मुकद्में दर्ज किये और 112 केसिज़ में चार्जशीट की जो केवल 6 परसेंट था और उनमें किसी में कन्विक्शन नहीं हुई, वहीं एनडीए की सरकार ने 5155 केस रजिस्टर्ड किये अपने काल में जो 1281 चार्जशीट किये और केवल conviction 36 केसिज़ में थे 63 लोगों के केवल 36 लोग केवल प्वांइट 7 परसेंट लोगों की conviction करवा पाये, परपज़ था extortion करना, परपज़ था डराना और परपज़ था चुनी हुई सरकार को derail करना। इसी कड़ी में अगर हम देखें तो इन्होंने Fugitive Economic Offences Act 2018 बनाया इसी में इन्होंने ED Act में एक प्रोविज़न डाला था की जो CRPC में एक कानून है कि onus complainant party पर होगा complaint police पर होगा कि वो प्रुव करे कि कोई आदमी guilty है इन्होंने उस कानून को बदल दिया और ये कह दिया कि अब onus accused पर होगा कि वो प्रुव करे की मैं वो guilty नहीं हूं। यही कारण था कि जो आदमी ईडी में गिरफ्तार हुआ उनकी बेल नहीं हो पाई और सर सी.एम. साहब को तो कैसे पकड़ा था। सी.एम. साहब को तो जो इनका सबसे बड़ा एक एक्युज़ था चन्द्रमोहन रेड्डी नहीं, शरदचन्द्र रेड्डी, शरदचन्द्र रेड्डी जब पुलिस के पास आया तो 9-11-2022 को उसको बुलाया गया था। 9 नवम्बर, 2022 को उस आदमी ने स्टेटमेंट दी ये अरविंदो फार्मा का मालिक था, शराब के ठेके इसको मिले थे साउथ की lobby का था। जब आया तो उसने कहा की मैं सी.एम. साहब के पास कभी भी शराब के किसी मामले में ना कभी गया ना मेरी कोई बातचीत हुई। शरद रेड्डी को

गिरफ्तार किया, गिरफ्तार करने के बाद उस आदमी को कुछ ही दिन में बेल ये कहकर दी की वो बीमार है और उसे साढ़े चार करोड़ रुपये का electoral bond लिया, कुछ महीनों बाद उसे बेल दे दी गई और उससे 25 करोड़ रुपये लिये, सॉरी साढ़े चार सौ करोड़, माफ़ कीजिये 55 करोड़, 60 करोड़ रुपये उसने अकेले ने दिये electoral bond के रूप में बीजेपी की गर्वमेंट को। सर ये खेल था केवल और केवल तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करने का और वो आदमी जो पहली स्टेटमेंट देता रहा कि मैं कभी नहीं मिला, उस आदमी को जिसको ईडी ने गिरफ्तार किया, जिस आदमी को जेल भेजा कुछ ही दिन में साढ़े चार करोड़ लेकर interim bail दी और बाद में 55 करोड़ रुपये लेकर उसको जमानत देकर सरकारी गवाह बना दिया क्योंकि वो अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ गवाह बन गया था। ये बीजेपी का खेल है। हमारे लगभग सारे जितने एमएलएज़ हैं लगभग आधे के करीब पर मुकद्में दर्ज किये गये हैं अकेले माननीय अरविंद केजरीवाल जी पर 50 मुकद्में हैं, वो मुकद्में, शांत रहिये शांत।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः भई विजेंद्र जी मुझसे बात करिये बात प्लीज़।

श्री मदन लालः जब आप बोलते हैं मैं नहीं बोलता। जब आप बोलते हैं मैं नहीं बोलता हूं, शांत रहिये।

माननीय अध्यक्षः चलिये, मदन लाल जी अब कन्क्लूड अब कन्क्लूड करिये।

श्री मदन लालः सर अकेले अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर माननीय एक्स चीफ मिनिस्टर जी के ऊपर दिल्ली, मुम्बई, बैंग्लोर, गुवाहाटी, यूपी, गोआ, पटना 50 केस हैं। हमारे पूर्व डिप्टी सी.एम. के ऊपर 12 केसिज़ हैं, सत्येन्द्र जैन साहब पर 02 केसिज़ हैं, कैलाश गहलौत जी के ऊपर 02 बार रेड की है, नरेश बाल्यान पर 03 केस हैं, गुलाब सिंह पर 03 केस हैं, अमानात पर 12 केस हैं, विशेष रवि पर 01 केस था acquit हो गये, बंदना कुमारी पर केस है, अखिलेश पति त्रिपाठी जी पर है, राखी बिरलान जी पर है आप खुद के ऊपर 02 केस थे आप बरी हो गये, भगवान का शुक्र मानिये कि केस बरी हो रहे हैं क्योंकि आप सारे इनोसेंट हैं। अब तक हमारे किसी भी एमएलए को मेरी नज़र में, मेरी जानकारी में सज़ा नहीं हुई है इसके पीछे केवल एक कारण है कि सारे के सारे केसिज़ आप लोगों को जानबुझकर फंसाने के लिये, बेइज्जत करने के लिये, defame करने के लिये इस पार्टी के बारे में लोगों में भ्रम फैलाने के लिये रजिस्टर्ड किये गये हैं जिससे लोगों को लगे की शायद ये करप्ट हैं या क्रिमिनल हैं। सर राखी बिरलान जी हमारी डिप्टी स्पीकर हैं उनके खिलाफ भी 03 मुकद्में जिनमें से एक में बरी हो गई 02 अभी पैंडिंग हैं। आपके अलावा ऋतुराज जी पर तो ऋतुराज जी का 01 केस खत्म हो गया है। दिनेश मोहनिया जी पर 09 केस 06 में बरी को गये। सर जरनैल सिंह पर 02 केस, चलो अब तो दोनों खत्म हो गये।

माननीय अध्यक्षः मदन लाल जी फिर चर्चा नहीं हो पायेगी।

श्री मदन लालः सर मैं ये कह रहा हूं कि इतने केस करने के बाद जिस तरीके से इन्होंने ईडी, सीबीआई और इन्कम टैक्स डिपार्टमेंट का सहारा लिया है ये केवल और केवल इस सरकार को गिराने की साजिश बदनाम करने की साजिश और ये काम ना कर पायें ये साजिश है। मैं आपके माध्यम से उन सभी लोगों को जो ऐसा कर रहे हैं निवेदन करना चाहता हूं कि उनकी हरकतों को लोग देख रहे हैं और सबसे ज्यादा कोर्ट देख रही है। कोर्ट ने जिस तरीके से माननीय अरविन्द केजरीवाल जी के केस में, मनीष सिसोदिया जी के केस में और संजय सिंह जी के केस में, जिस तरीके से लताड़ा है, ईडी और सीबीआई को उससे साफ जाहिर होता है कि ये केस उन्होंने जानबूझकर बदनीयती के साथ ऊपर के इशारे पर किये थे।

(समय की घंटी)

श्री मदन लालः मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे इस पर बोलने का मौका दिया। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः श्री जरनैल सिंह जी।

श्री जरनैल सिंहः धन्यवाद स्पीकर साहब। स्पीकर साहब एक बहुत ही गम्भीर मामले पर आपने मुझे समय दिया बहुत-बहुत धन्यवाद उसके लिए। सर साल 2015 में आजाद भारत के इस लोकतंत्र के इतिहास में आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी जीत दर्ज कराकर दिल्ली में सरकार बनाई आम आदमी पार्टी ने। उसके बाद से ही बीजेपी को चिंता

शुरू हो गई। क्योंकि इंतजार कर रहे थे 1998 से भी सरकार बनायेंगे, बनायेंगे। 49 दिन की सरकार के बाद फिर से इनको एक बार लगा शायद अब बन जाये पर दिल्ली वालों ने जो इनको धूल चटाई और जो विश्वास दिखाया आम आदमी पार्टी के प्रति तो इनके सारे सपने चकना चूर हो गए। कल हम सबके प्यारे नेता अरविंद केजरीवाल जी ने बोला और ये फैक्ट है स्पीकर साहब होना तो ऐसा ही चाहिए था कि दिल्ली वालों ने हमें मौका दिया तो हमने यहां काम करके दिखाया। ऐसे काम करके दिखाये जो आज तक नहीं हुए थे। मोहल्ला क्लीनिक बनाये जिसकी सारी दुनिया में तारीफ होती है। दिल्ली के सरकारी स्कूलों को प्राईवेट से बेहतर बनाया। तो आपको किसने रोका है। बीजेपी को भी बहुत सारी स्टेट्स में लोगों ने मौका दे रखा है। सर कह रहे थे हमने 500 सौ स्कूल बनाये तो आप पांच हजार, दस हजार बना सकते हो। हमने पांच सौ मोहल्ला क्लीनिक बनाये तो आप भी हजारों में बना सकते हो। पर आपको करना नहीं आता। आपको दूसरे के कामों को रोड़े डालने आते हैं पर आपको खुद से करना नहीं आता। हमने बसों में किराया फ्री किया आप ट्रेनों में भी कर सकते हो। आपने तो जो बुजुर्गो को साठ साल से ऊपर वालों को छूट मिलती थी वो तक बंद कर दी। तो कुल मिलाकर कहानी का मतलब ये है कि आपको ये काम करने आते नहीं या ये आप काम करना चाहते नहीं और बहादुरी इसमें नहीं होती कि आप दूसरे के कामों से जलन करें, ईर्ष्या करें और अपनी शक्तियों का दुरूपयोग करें और उन कामों को रोकने में अपनी शक्ति लगायें, बहादुरी इसमें है कि आप दूसरे के कामों से सीखें। हम

कहते हैं कि हमने दस स्कूल बनायें तो आप पचास बनाकर दिखायें ना। किसी ने रोका तो नहीं है। तो जिस तरीके से ये एजेन्सीज़ का दुरूपयोग हो रहा है, मुझे लगता है कि शायद यहां बैठे छः-सात लोगों को ही लगता है कि मोदी जी का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। पूरी दुनिया में इस से भारत का नाम खराब हो रहा है कि एक हफ्ता पहले कहीं सीबीआई ने ईडी ने छापा मारा, कुछ दिन बाद वो नेता जाकर भाजपा में शामिल हो गया। ये एक बार नहीं हुआ है स्पीकर साहब और यहां तक कि देश के प्रधान मंत्री जिन नेताओं का नाम लेते थे, जिनको कहते थे मैं एक बारी प्रधान मंत्री बन गया तो सबसे पहले इनको अंदर करूंगा। उन नेताओं तक को ईडी सीबीआई जैसी एजेंसीज से छापा पड़वाकर भाजपा में शामिल किया। तो इससे कोई देश का नाम रोशन नहीं हो रहा। स्पीकर साहब मैं आपके माध्यम से जो भाजपा के साथी यहां बैठे हैं अगर इनकी बात सुनते हों प्रधानमंत्री जी तो ये संदेश दें कि ये आदत और ये काम इस देश के आने वाले समय के लिए बहुत घातक है। लोकतंत्र में जनता ने जो सरकार चुन दी उसको काम करने दे। उनके कामों से ईर्ष्या ना करें बल्कि कोई अच्छा काम हो रहा है तो उससे सीखें और उन्हें जहां आपको मौका मिला है वहां पर implement करें। तो जो ये एक के बाद एक, एक के बाद एक इन्होंने हम पर शोषण किया, हमारे पर जुल्म किये। कहते हैं हर काली रात की एक सवेर होती है। इन्होंने हमारे एक-एक करके नेताओं से शुरू किया, विधायकों से शुरू किया, मंत्रियों तक पहुंचे, हमारे सांसदों तक पहुंचे। उसके बाद भी इनको लगा भई काम नहीं रूक रहे इन्होंने हमारे

मुख्यमंत्री साहब को उठाकर जेल में डाल दिया। पर सच के साथ परमेश्वर होता है। अंततः सत्य की जीत हुई। केजरीवाल साहब बाहर आये। दिल्ली के काम फिर से होना शुरू हुए। इन्हें फिर अपनी हार नज़र आना शुरू हो गई। इन्हें समझ आना शुरू हो गया कि पन्द्रह में तो 70 में तीन आई, बीस में 70 में आठ आ गई। इस बारी फिर 70 में से जीरो आने जा रही है। सबके सबकी जमानत जब्त होने जा रही है भाजपा वालों की और एक बात ये कहना चाहता हूं, जिंदाबाद। तो हम सबको अपने नेता पर उनके नेतृत्व पर पूरा भरोसा है और हमें पूरा मालूम है कि इस बार जनता आपको इस तानाशाही का जवाब 70 में से जीरो सीटें देकर देगी। मैं दो लाईनें बोल कर क्योंकि स्पीकर साहब समय सीमित है, मैं समझता हूं इस चीज को, अपने नेता के बारे में दो लाईनें बोलना चाहूंगा किः

''सहारा हो ना हो मैं नाव ले जाऊंगा मंजिल तक,
सहारा हो ना हो मैं नाव ले जाऊंगा मंजिल तक,
हुनर मल्लाह में होता है चप्पू में नहीं।''

धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः राखी बिरला जी।

श्रीमती राखी बिरलाः बहुत-बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी। समय बेहद कम है तो मैं बस कुछ लाईनों में ही अपनी बात को रखूंगी। मुझसे पूर्व तमाम वक्ताओं ने बहुत गहराई से बहुत सारे आंकड़ों

के साथ, बहुत तर्क के साथ इस महत्वपूर्ण और बेहद ही संजीदा विषय पर अपनी बात रखी है। यूं तो पूरे देश के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर इस कुकृत्य की चर्चा पिछले डेढ़ साल से चल रही है कि किस प्रकार से देश के संविधान की आस्था पर और सवैंधानिक संस्थाओं पर निरन्तर चोट कर कर कुछ संकीर्ण मानसिकता के लोग, कुछ छोटी सोच के लोग, बार-बार इस बात का परिचय दे रहे हैं कि उनको सिर्फ और सिर्फ एक बात समझ आती है एक शब्द समझ आता है वो है तानाशाही। लेकिन डा. भीम राव अम्बेडकर जी के द्वारा लिखे गए संविधान और हजारों-हजार क्रान्तिकारियों के बलिदान की वजह से जो हमारे भारत देश को गौरव प्राप्त हुआ है लोकतंत्र में उस लोकतंत्र के अंदर इन लोगों के तानाशाही वाले मनसूबे तो दूर की बात है इस शब्द के लिए भी कोई जगह नही। अध्यक्ष जी, एक कहावत है जैसा खाओगे अन्न, वैसा होगा मन और जैसे होंगे संस्कार वैसे होंगे आपके आचार, विचार। तो अध्यक्ष जी, जब मैं संस्कारों की बात कर रही हूं तो मुझे बहुत ही भारी मन से ये कहना पड़ रहा है कि जिस पार्टी की सरकार आज देश के केन्द्र में है और देश के 22 राज्यों में है उस पार्टी का जन्म ही दंगों से लोगों को डरा धमका कर वोट लेने से ही हुआ है और वो डरा धमका कर दंगों से सरकार बनाकर जो प्रधानमंत्री के तौर पर बैठे हैं उस चौथी पास राजा की संकीर्ण मानसिकता से सिर्फ और सिर्फ हम लोग इसी बात की उम्मीद कर सकते हैं कि उनके अंदर सिर्फ और सिर्फ ईर्ष्या है ग्लानि है और हर वक्त दूसरे के साथ परस्पर जो है एक कॉम्पीटीशन काम के दम पर जीतने की भावना नहीं है

उनको कैसे नीचा दिखाकर आगे बढ़ा जा सके। ये भावना निरन्तर उनके अंदर पलती है, बढ़ती है। जब कोई पार्टी दंगों के दम पर वोटों की चोरी करके, वोटों की खरीद-फरोख्त करके सरकारों को रातों-रात तोड़कर विधायकों को ड्रा धमका कर अस्तित्व में आती तो उनका गृहमंत्री तडीपार होगा ये बिल्कुल साफ है और नामजद है। ये मैं, मेरा दल या कोई और नहीं कहता, ये चुनाव के माध्यम से कही हुई बातें नहीं है, ये तो भारत की न्याय व्यवस्था के माध्यम से न्यायालयों के अंदर सत्यापित बात है और जब आपकी मानसिकता इतनी संकीर्ण होगी, जब आप अनपढ़ता का परिचय देंगे, जब आप गुंडागर्दी का परिचय देंगे तो निश्चित तौर पर ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि एक पढ़े लिखे, एक प्रभावशाली एक आईआईटियन से एक ऐसा व्यक्ति जो सब कुछ न्यौछावर करता आया है, माँ भारती के लिए और दिल्लीवासियों के लिए तो उससे मोदी जी को डर लगना लाज़मी है। ये बात कहना इस सदन के अंदर बिल्कुल गलत नहीं होगा कि जब-जब मोदी डरता है केजरीवाल से तो ईडी और सीबीआई को आगे करता है। क्योंकि इनके पास कोई विज़न नहीं है, अध्यक्ष जी इनके पास कोई विचार नहीं है, अध्यक्ष जी, इनके पास कोई ऐसे नेता नहीं है जो देश के हजारों लाखों करोड़ बेटे-बेटियों को रोजगार दे सकें। हाँ, इनके पास जुमले जरूर है। पिछली बार कहा था कि हर किसी को पन्द्रह लाख रूपये देंगे। इस बार कहा कि हर किसी को दो करोड़ नौकरी देंगे और फिर कहते हैं अगर मैं ये ना कर पाऊँ तो झोला उठाकर चला जाऊंगा। तो जो व्यक्ति दिमाग में ये रखता कि मैं नहीं कर पाऊंगा तो झोला उठाकर चला जाऊंगा तो

निश्चित तौर पर वो अपनी संकीर्ण मानसिकता का बार-बार परिचय देते हुए अपने से ज्यादा प्रभावशाली विपक्ष के नेताओं को जेल में डालने का काम करेंगे। झूठे षडयंत्र बनाकर उनकी ईमानदारी, उनकी कर्मठता और उनकी सरकार को डी-रेल करने का काम करेंगे। मैं आज कहना चाहती हूं इस सदन के माध्यम से.

(समय की घंटी)

श्रीमती राखी बिरला: बिल्कुल चार लाईन में खत्म करूंगी। मैं इस सदन के माध्यम से आज अध्यक्ष जी ये कहना चहती हूं कि मोदी जैसे और भारतीय जनता पार्टी जैसे लोग एक बार क्या हजारों बार जन्म ले लेंगे ना तब भी अरविन्द केजरीवाल का बाल बांका नहीं कर पायेंगे। क्यों नहीं कर पायेंगे, क्योंकि अरविन्द केजरीवाल, क्योंकि अरविन्द केजरीवाल एक महज नेता नहीं है, अरविन्द केजरीवाल एक क्रान्ति है और वो क्रान्ति जिसने ईमानदारी और काम की राजनीति को 75 साल के बाद इस आजाद भारत के अंदर स्थापित करके दिखाया है। अरविन्द केजरीवाल आज आजाद भारत में पहला ऐसा नेता है जो कहता अगर मैंने काम किया है तो मुझे वोट करना, अगर मैं ईमानदार हूं तो मुझे वोट करना। मैं चैलेंज करती हूं विपक्ष के साथियों को एक बार मोदी जी से कहलवा दो कि अगर मैंने काम करा है तो मुझे वोट कर दो। भाई साहब जमानत जब्त ना कर देना इस देश की जनता, ढूंढ़ते रह जाओगे वोटों को। तो अध्यक्ष जी अरविन्द केजरीवाल जैसे, अरविन्द केजरीवाल जैसे नेता को, अरविन्द केजरीवाल जैसे नेता को मोदी जैसे व्यक्ति और

तडीपार जैसे अमित शाह जैसे व्यक्ति हजारों जन्म लेंगे ना, ना झुका सकते हैं, ना डरा सकते हैं और ना ही हमारी सरकार को तोड़ सकते हैं और जहां तक बात है आम आदमी पार्टी को तोड़ने की आम आदमी पार्टी के लोगों को डराने की तो अध्यक्ष जी मैं ये भी बहुत साफ शब्दों में बता दूं। आम आदमी पार्टी कोई राजनैतिक पार्टी नहीं है। ये एक परिवार है और इस परिवार में ना सिर्फ विधायक, ना सिर्फ मंत्री, ना सिर्फ सांसद हैं, बल्कि इस परिवार के अंदर दिल्ली के दो करोड़ सदस्य हैं जो अपने बेटे के ऊपर अपने भाई के ऊपर और अपने परिवार के ऊपर मजबूती से विश्वास करके खड़े हैं। हम आज फिर इस बात को कहते हैं तुम ईडी को लगा लो तुम सीबीआई को लगा लो तुम्हारे आस पास जितने तुम्हारे हथकंड़े हैं, सब कुछ लगा लो। ना तुम अरविंद केजरीवाल की ईमानदारी पर दाग लगा सकते, ना उसकी कर्मठता पर दाग लगा सकते। ये दाग वापिस तुम्हारे मुंह पर लगेंगे। हेमंत विश्वकर्मा के रूप म्ं, लगेंगे आपके मुंह पर ये दाग आकर। शुभेन्द्र अधिकारी के तौर पर तुम्हारे मुंह पर ये दाग आकर लगेंगे। जो है जो नर्मदा घोटाला हुआ, उसके नाम पर और मोदी सरकार और ईडी के दुरूपयोग की वजह से ना विपक्ष खत्म हो सकता है, ना विपक्ष खत्म होगा। आने वाले समय के अंदर आप देखिये अभी तुम्हारी बैशाखी की सरकार चलती है केन्द्र में दो बाबूओं के दम पर वो बाबू जिस दिन अपना सहारा हटा लेंगे तो हमारे जो चौथी पास राजा हैं वो कुर्सी से नीचे गिरेंगे और संविधान की जय-जय कार होगी। तो अध्यक्ष जी मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूं, आज तक जितनी भी सरकारों ने अपनी

संस्थाओं का दुरूपयोग करा है, इस लोकतंत्र के माध्यम से संविधान के माध्यम से जनता ने उनको जवाब दिया है। वो दिन दूर नहीं दिल्ली में एक बार फिर से जनता भारतीय जनता पार्टी के कान पर इतनी जोरदार तमाचा मारेगी कि वो जो ये आठ सीटें हैं वो भी जीरो पर सिमट जायेगी। अरविन्द केजरीवाल जी को जनता प्यार करती थी, है और करती रहेगी। आज पूरी दिल्ली में एक ही नारा है, मेरा एक केजरीवाल ईमानदार है, मेरा केजरीवाल काम करने वाला है और जब तक केजरीवाल है दिल्ली के विकास को, दिल्ली के बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा को, दिल्ली की विधवा बहनों की पेंशन को और दिल्ली के बच्चों की अच्छी शिक्षा स्वास्थ्य को और बहनों की सुरक्षा को भारतीय जनता पार्टी के ये छोटे छुट भैया नेता ना रोक पाये थे, ना रोक पायेंगे और ना ही इस क्रान्ति को कभी भी अपने रास्ते से भटका पायेंगे। अध्यक्ष जी, आपने मुझे इतने कम समय में मेरे शब्दों को रखने का मौका दिया। बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया। मैं चाहती हूं कि इस विषय को आज से और अभी से हम लोग इतनी गहराई से जन-जन में पहुंचायें कि वोट लेने के लिए किस प्रकार से काम चोर लोग एक काम करने वाले नेता की छवि को धूमिल करने का असफल प्रयास करते हैं। ये इस प्रयास में भी असफल रहे और चुनाव में भी सौ फीसदी असफल रहेगें 70 की 70 सीटें केजरीवाल को अपने बेटे को अपने भाई को दिल्ली की जनता देकर रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। जय हिंद। जय भारत।

माननीय अध्यक्षः श्री विजेंद्र गुप्ता जी। विजेंद्र गुप्ता जी।

श्री ओमप्रकाशः बॉस हमारा भी नंबर है। आप सिवाय डिक्टेटरशिप के कुछ नहीं करते।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः चलिए मैं स्वीकार करता हूं। मैं।

श्री विजेंद्र गुप्ता (माननीय नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष जी, ये एक मैम्बर तो विपक्ष में भी बोला जाएगा।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः नहीं, मैं तानाशाह हूं स्वीकार करता हूं। विजेंद्र गुप्ता जी। प्लीज़। नहीं, नहीं मैं कोई समय नहीं।

श्री विजेंद्र गुप्ताः आप देखो ना दस-दस मिनट बोल रहे हैं मैम्बर

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः तीन लोग बोले हैं उधर से।

श्री विजेंद्र गुप्ताः तो हमारा तो एक भी नहीं बोला।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः तीन बोले हैं, एक आपका बुलवा रहा हूं।

श्री विजेंद्र गुप्ताः मैं तो बोलूंगा ही।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः भाई साहब 7 के पीछे एक आता है।

श्री विजेंद्र गुप्ताः अध्यक्ष जी विपक्ष का नेता तो बोलेगा ही।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः चालू करिए प्लीज चालू करें।

श्री विजेंद्र गुप्ताः एक मैम्बर तो बुलवाओ ना।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः नहीं, विजेंद्र जी समय नहीं है।

श्री विजेंद्र गुप्ताः एक मैम्बर एक मिनट बोलेगें।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः नहीं, मैं नहीं अब।

श्री विजेंद्र गुप्ताः एक मिनट के लिए।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः तो एक आदमी कोई बोल लीजिए।

श्री विजेंद्र गुप्ताः एक मिनट के लिए बोलेगें ना।

माननीय अध्यक्षः या आप बोल लीजिए या वो बोलेगें।

श्री विजेंद्र गुप्ताः ये कैसे मतलब है।

माननीय अध्यक्षः नहीं।

श्री विजेंद्र गुप्ताः ये क्या बात है।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः देखिए सात के हिस्से एक आता है।

श्री विजेंद्र गुप्ताः हां जी तो एक सात के हिस्से एक तो दे रहे हैं।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः हां एक दे रहे हैं तो बात खत्म।

श्री विजेंद्र गुप्ताः मेरे को आप इसमें काउंट करेगें आप।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः ना बिल्कुल नहीं।

श्री विजेंद्र गुप्ताः कमाल कर रहे हैं आप।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः उधर से तीन ही लोग बोले हैं भई। उधर से तीन लोग बोले हैं।

श्री विजेंद्र गुप्ताः तीन कहां बोले, सात बोले हैं।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः मदन लाल जी बोले हैं, जरनैल सिंह जी बोले हैं और राखी बिरला बोली हैं बस। अब तक तीन बोले हैं।

श्री विजेंद्र गुप्ताः वो बोले हैं जरनैल सिंह जी बोले हैं।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः जरनैल जी बोले हैं। भई अब समय ना खराब करो, प्लीज। मेरा हाथ जोड़ के, मैं तानाशाह हूं मैंने बोल दिया है। मैने स्वीकार कर लिया मैं तानाशाह हूं। भई ओमप्रकाश जी। बैठिये, प्लीज बैठिये।

श्री विजेंद्र गुप्ताः एक मिनट दे दो।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः मैं हाथ जोडकर माफी मांग रहा हूं। वो शब्द बोल रहे हैं तानाशाह है। डिक्टेटर हूं। मैं स्वीकार कर रहा हूं मैं डिक्टेटर हूं। विजेंद्र जी शुरू करिये जल्दी से।

श्री विजेंद्र गुप्ताः अध्यक्ष जी एक मैम्बर तो हमारा बोलना चाहिए ना।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः नहीं, क्या कर रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं आप?

श्री ओमप्रकाश शर्माः आप अधिकारों का हनन करते हैं।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः मैं हनन करता हूं। स्वीकार करता हूं। चालू करिये विजेंद्र जी, प्लीज। आप शुरू करिये विजेंद्र जी।

श्री विजेंद्र गुप्ताः अध्यक्ष जी, विपक्ष के बैंच से एक भी मैम्बर को ना बुलवाना, ये ठीक नहीं है।

माननीय अध्यक्षः भाई साहब बैठिये, प्लीज बैठ जाईये। नहीं मैं अलाऊ नहीं कर रहा हूं। जब वो तानाशाह कह कर मुझे सम्बोधित कर रहे है। जब अध्यक्ष को..

(सदस्यों द्वारा आपसी विचार विमर्श)

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः मुझे बुलवाने से बिल्कुल ऐतराज नहीं था। वो सवेरे से आज पांच बार मुझे तानाशाह बोल चुके हैं, पांच बार और अभी पांचवी बार बोला है। ये अधिकार नहीं है। बोलिये।

श्री ओमप्रकाश शर्माः अध्यक्ष जी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।मुझे वैसे तो आपसे गिला है। छह महीने बाद मेरा नंबर आया है लेकिन धन्यवाद। आज पूरे सदन की सहमति के बाद मैं पढ़ रहा हूं ''निर्वाचित सरकार को अस्थिर करने के उद्देश्य से दिल्ली सरकार के मंत्रियों एवं विधायकों के विरूद्ध एजेंसियों का दुरूपयोग।'' मुझे एक फिल्म का नाम याद आता है ''चोर मचाये शोर'' तो आज मैं ये कहना चाहता हूं आपके माध्यम से जिस पार्टी का जन्म India against corruption के द्वारा हुआ और उसने सबसे पहले शीला दीक्षित, लालू यादव, शरद पवार, सुरेश कलमाड़ी सैंकड़ों लोगों के नाम ले ले के उनके जलूस निकाले, उनके पुतले फूंके और पता नहीं जाने क्या क्या किया, उसी शीला जी के साथ मिलकर आपने 2013 में सरकार बनाई, ये आपकी विश्वसनीयता है, आपकी और आप की सरकार की। अब सवाल ये है कि आप बात करते हैं एजेंसियों की Feedback Unit आपने बनाया, खुफिया राजनीतिक जासूसी कराई उसमें आपके ऊपर केस है। शराब नीति एक के ऊपर एक बोतल फ्री पूरी दिल्ली को आप पानी नहीं दे सके लेकिन शराब पेट भर के आपने पिलाई, 2873 करोड़ का घोटाला हुआ, केस पेंडिंग है, पहले जेल में, फिर बेल में और अब बैठे हुए हैं। पहले कहते थे मैं जेल से सरकार चला रहा हूं, अब आकर कहते हैं मैं जेल में था तो सड़कें टूट गयी, अब मैं दोबारा करूंगा। पता नहीं

तब जब कह रहे थे जेल से सरकार चला रहा हूं वो बात सही थी या अब जो हाउस में कह रहे हैं कि अब मैं आया हूं तो सारे काम करूंगा दोनों में से क्या सही है ये तय सदन करेगा। जल बोर्ड में हजारों करोड़ का घोटाला है, सिविक ट्रीटमेंट प्लांट उसके ऊपर भी सीबीआई का केस लगा हुआ है। स्कूल रूम घोटाला जिसके लिये सिसोदिया जी बड़ी लंबी-चौड़ी बात करते हैं, दुनिया के अखबारों में खबर छपवाते हैं चार लाख का कमरा आपने 33 लाख रूपये में बनवाया। बस खरीद घोटाले में एक हजार लो फ्लोर बस में पांच हजार करोड़ का घोटाला है, दिल्ली के

...व्यवधान...

श्री ओमप्रकाश शर्मा: मैं कह रहा हूं। अरे मैं कह रहा हूं भई। अरे मैं कह रहा हूं, हू आर यू, नीचे बैठो। अरे मैं बोल रहा हूं। मेरा जवाब देना। मेरा जवाब देना।

...व्यवधान...

श्री ओमप्रकाश शर्मा: ए मिस्टर, ऐ बैठो नीचे, ऐ नीचे बैठो, जवाब देना। ये मेरा नंबर है बोलने का।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्ष: माईक ऑन करो इधर।

...व्यवधान...

श्री ओमप्रकाश शर्मा: सुनो भाई, ए मिस्टर ये मेरी बारी है।

...व्यवधान...

माननीय परिवहन मंत्री (श्री कैलाश गहलोत): अध्यक्ष जी ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है कि पांच हजार करोड़ का घोटाला है।

श्री ओमप्रकाश शर्मा: मंत्री जी ये मेरा नंबर है बोलने का आप इसका जवाब देना बाद में मेरे बोलने के बाद।

...व्यवधान...

माननीय परिवहन मंत्री: ये मिसलीडिंग स्टेटमेंट है बिल्कुल, इस चीज में कोई मेरिट नहीं है और इनके अगेंस्ट।

श्री ओमप्रकाश शर्मा: यदि मैं गलत कह रहा हूं तो आप मेरा, आप इसकी कम्प्लेंट करो।

माननीय परिवहन मंत्री: मैं अध्यक्ष जी आप से अनुरोध करूंगा कि इनके अगेंस्ट एक्शन लिया जाए। ये किस बेसिज पे कह रहे हैं कि पांच हजार करोड़ का घोटाला है। आपके कहने से क्या होता है।

श्री ओमप्रकाश शर्मा: मैं बोल लूं उसके बाद आप बोल।

माननीय परिवहन मंत्री: आपके कहने से क्या होता है।

श्री ओमप्रकाश शर्मा: तो आपके बोलने से क्या होता है। अरे आपके कहने से क्या होता है। आप कौन हैं।

...व्यवधान...

माननीय परिवहन मंत्री: कौन सा डॉक्यूमेंट है।

श्री ओमप्रकाश शर्मा: अरे नीचे बैठो मेरा नंबर है बोलने का।

माननीय परिवहन मंत्री: मैं अध्यक्ष जी ये पूछना चाहूंगा। मैं अध्यक्ष जी आपसे पूछना चाहूंगा कि जो इन्होंने कहा है कि पांच हजार करोड़ का घोटाला है।

श्री ओमप्रकाश शर्मा: अरे मैंने सब कुछ सही कहा है।

माननीय परिवहन मंत्री: ये कौन सी रिपोर्ट है। कौन सी, आज दो केस सीबीआई में गये हुए हैं आप ।

श्री ओमप्रकाश शर्मा: अरे इतनी तेज मिर्ची क्यों लग रही है।

...व्यवधान...

माननीय परिवहन मंत्री: दो केस सीबीआई में गये हुए हैं।

श्री ओमप्रकाश शर्मा: अरे तीखी मिर्ची लग रही है क्या?

माननीय परिवहन मंत्री: आज तीन और हो गये। सीबीआई ने कौन सी फाइंडिग दी है।

श्री ओमप्रकाश शर्मा: अरे ये बताना ना फिर।

माननीय परिवहन मंत्री: उनके पास कौन सी फाईंडिंग है।

श्री ओमप्रकाश शर्मा: अरे सदन में बताना।

माननीय परिवहन मंत्री: जिसके बेस पर ये पूरे सदन के बीच में खड़े हो के स्टेटमेंट दे रहे हैं कि पांच हजार करोड़ का घोटाला है। आप इनसे पूछिये।

श्री ओमप्रकाश शर्मा: अरे वापस क्यूं लिया, ऑर्डर वापस क्यों लिया?

माननीय परिवहन मंत्री: आप उनसे पूछिये...।

...व्यवधान...

श्री ओमप्रकाश शर्मा: अगर आप सही थे तो ऑर्डर वापस क्यों लिया? अगर ये सरकार ठीक थी तो ये ऑर्डर वापस क्यों लिया गया, मंत्री महोदय इसको बतायें तो मैं अपना वक्तव्य खत्म करूं।

माननीय परिवहन मंत्री: ये हमारी मर्जी। तो आप बताओगे सरकार को क्या करना है।

....व्यवधान...

माननीय अध्यक्ष: हो गया?

श्री ओमप्रकाश शर्मा: अरे मैं बोल रहा हूं मुझे बोलने नहीं देते हो।

माननीय परिवहन मंत्री: हमने कैंसिल कर दिया क्या प्रॉब्लम हो गई उसमें? भई आपके कहने से सरकार चलेगी क्या?

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्ष: हो गया आपका विषय पूरा?

श्री ओमप्रकाश शर्मा: बोलने ही नहीं दे रहे।

माननीय परिवहन मंत्री: तुम्हारे कहने से सरकार चलेगी?

श्री ओमप्रकाश शर्मा: अरे भाई मैं बोल रहा हूं आपको गलत लगता है तो आप बोलना।

...व्यवधान...

माननीय परिवहन मंत्री: नहीं तुम बताओगे सरकार कैसे चलेगी?

श्री ओमप्रकाश शर्मा: अध्यक्ष जी को बोल रहा हूं मैं। मैं आपको तो बोल नहीं रहा।

माननीय परिवहन मंत्री: अध्यक्ष जी अगर ऑर्डर कैंसिल किया तो उसमें घोटाला हो गया, अगर बसें खरीद ली तो घोटाला हो गया।

श्री ओमप्रकाश शर्मा: अरे बहस करनी है।

माननीय परिवहन मंत्री: अगर बसें नहीं आई तो घोटाला हो गया।

माननीय अध्यक्ष: परेशानी यही है।

माननीय परिवहन मंत्री: बसें नहीं आयेंगी तो कहेंगे केजरीवाल सरकार खराब है बसें लेकर नहीं आई। पूरी दिल्ली।

श्री ओमप्रकाश शर्मा: अरे रामलीला क्यों कर रहे हो भाई।

माननीय परिवहन मंत्री: पूरी दिल्ली इनके करतूतों की वजह से परेशान है।

...व्यवधान...

श्री ओमप्रकाश शर्मा: अरे रामलीला क्यों कर रहे हो मंत्री जी। ए मंत्री जी।

माननीय परिवहन मंत्री: जब बसें नहीं आ रही थी तो ये चिल्ला चिल्ला के बोलते थे कि बसें नहीं आ रही, बसें नहीं आ रही।

श्री ओमप्रकाश शर्मा: अरे मंत्री जी, अपना वक्तव्य बाद में देना।

माननीय परिवहन मंत्री: आज जब बसें आ रही हैं तो इनके दर्द है। इनको बहुत बड़ा दर्द है।

श्री ओमप्रकाश शर्मा: अरे हमारा दर्द है हम दवाई ले लेगें। बैठ जाओ।

माननीय परिवहन मंत्री: हर दो महीने में।

श्री ओमप्रकाश शर्मा: अरे बैठो।

माननीय परिवहन मंत्रीः इलैक्ट्रिक बसिज़ ये कैसे आ रही हैं।

श्री ओमप्रकाश शर्माः अरे आप बैठ जाओ।

माननीय परिवहन मंत्रीः अच्छा एक और चीज़ अध्यक्ष जी, एक और चीज़ है।

...व्यवधान...

श्री ओमप्रकाश शर्माः अरे छः महीने बाद बोल रहा हूं, अब तो बोल लेने दो।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः भई ओमप्रकाश जी मंत्री जी बोल रहे हैं, दो मिनट बैठिए। मंत्री जी बोल रहे हैं, दो मिनट बैठिए। मंत्री जी बोल रहे हैं। नहीं, मंत्री जी जब मर्जी आए बोल सकते हैं।

माननीय परिवहन मंत्रीः अध्यक्ष जी एक बड़ी इंट्रस्टिंग चीज़ है।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः मंत्री जब मर्जी आए बोल सकते हैं। बैठिए प्लीज़। आपको समय दूंगा अभी दोबारा। मंत्री जी बोलिए।

माननीय परिवहन मंत्रीः अध्यक्ष जी एक बड़ी इंट्रस्टिंग चीज़ है। दिल्ली सरकार ने।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः रोहित जी आप शांत रहिए प्लीज़।

माननीय परिवहन मंत्रीः माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने एक विजन रखा कि दिल्ली का पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम, दिल्ली का ही नहीं, देश का ही नहीं लेकिन पूरी दुनिया का बेहतरीन पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम होना चाहिए। उस विजन को अचीव करने के लिए और electric vehicle policy दिल्ली में हम लेकर आए उसमें हमने केजरीवाल सरकार ने ये डिसीजन लिया कि 80 परसेंट जो दिल्ली की बसें होगीं वो इलैक्ट्रिक होगीं। आप दो मिनट मुझे सुनिएगा मैं कहां लिंक कर रहा हूं दोनों चीजों को।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः हां बोलिए, बोलिए।

माननीय परिवहन मंत्रीः छह हजार बसों के वर्क आर्डर दिल्ली सरकार प्लेस कर चुकी है। अब इनके पेट में ये दर्द है कि ये बसें कैसे आ रही हैं लेकिन बेचारी इनकी मजबूरी है कि जो टैंडर फ्लोट किया वो टैंडरफ्लोट किया सीएसएल ने, अब इनके हाथ बंधे हुए हैं, मुंह भी बंद हैं। अब तुम कह लो नहीं-नहीं अब तुम कह लो कि एसीबी कंपलेंट करे।

...व्यवधान...

माननीय परिवहन मंत्रीः वो दिख रहा है मुझे। तो आप करो ना फिर, आप, ये जो बसें आ रही हैं, ये जो इलैक्ट्रिक बसिज़ आ रही हैं आप इनमें कम्पलेंट करो। भई ये अब जो बसें आ रही हैं अध्यक्ष जी लगातार दो हजार इलैक्ट्रिक बसिज़ हम दिल्ली की सड़कों पर निकाल चुके हैं।

माननीय अध्यक्षः एक सैकेंड कैलाश जी। कैलाश जी एक सैकेंड माननीय मंत्री जी। ओमप्रकाश जी मैं आपको कानून के हिसाब से बताना चाह रहा हूं, जैसा मैंने पहले भी कहा नियम 270 के अंतर्गत मंत्री जी किसी भी चर्चा में कभी भी खड़े होकर बोल सकते हैं।

...व्यवधान...

माननीय परिवहन मंत्रीः मैं अध्यक्ष जी ये कह रहा हूं कि पिछले।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः भई अब मत, अब डिस्टर्ब मत करिए, प्लीज़।

माननीय परिवहन मंत्रीः मैं अध्यक्ष जी ये कह रहा हूं कि पिछले एक डेढ़ साल में हम दो हजार इलैक्ट्रिक बसें दिल्ली की सड़कों पे उतार चुके हैं।

...व्यवधान...

माननीय परिवहन मंत्रीः आ रहा हूं, उसी पर आ रहा हूं। ये जो कह रहे हैं बार बार सैन्ट्रल गवर्नमेंट, सैन्ट्रल गवर्नमेंट मात्र कुछ परसेंट जो है वो केन्द्र सरकार ने सबसीडी दी। अगर आप इन बसिज़ का खर्चा देखें ये हमने बार–बार कही है और माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने भी ये बार–बार स्टेटमेंट इनको दिया, सर आपको याद होगा जब पहली हमने जब खेप इलेक्ट्रिक बसिज की जब हमने inaugurate की, flag off किया तो इन्होंने हल्ला मचाया था। अगर इन बसिज़ का अगर आप 12 साल का अगर खर्चा देखें तो लगभग दो हजार करोड़ आता है सर, उस दो हजार करोड़ में से केवल और मैं ये चाह रहा हूं कि एक–एक चीज़ रिकार्ड हो ताकि आने वाली जनरेशन इस चीज़ को पढ़े। अध्यक्ष जी दो हजार करोड़ में से केवल 200 करोड़ रुपये केन्द्र सरकार ने दिया है, केवल 200 करोड़ रुपये। अब ये उस चीज़ को हल्ला मचाये जा रहे हैं। माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने कहा उस टाइम स्टेटमेंट थी सर आपकी ये कि भई अगर दिल्लीवासियों को बढ़िया सुविधा मिल रही है तो सारा क्रेडिट केन्द्रीय सरकार ले ले हमें कोई दिक्कत नहीं है लेकिन fact is…

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः बता तो रहे हैं 200 करोड़ रुपये दिए हैं सिर्फ 2000 में से।

माननीय परिवहन मंत्रीः लेकिन fact is

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः बता तो रहे हैं 200 करोड़ रुपये दिए हैं सिर्फ 2000 में से।

माननीय परिवहन मंत्रीः लेकिन fact is

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः बता दिया उन्होंने 200 करोड़, शांत रहिए अब।

माननीय परिवहन मंत्रीः 2000 करोड़ में से मात्र 200 करोड़ रुपये इन्होंने केन्द्र सरकार ने दिए हैं। अब मैं ये कह रहा हूं कि जब दिल्ली सरकार कोई टैंडर करती है।

...व्यवधान...

माननीय परिवहन मंत्रीः हां, हां 200 करोड़ कह तो रहे हैं भई कान ठीक है हमारे तो 200 करोड़। दो हजार करोड़ में से केवल 200 करोड़ रुपये दिए हैं। अब एक बड़ी इंट्रस्टिंग चीज़ है जब दिल्ली सरकार जब कोई टैंडर करती है तो उसमें करप्शन हो गया। जब हम कोई बसों का ऑर्डर कैंसिल कर देते हैं तो उसमें करप्शन हो गया। ये 2000 बसें आ गई हैं इसमें करप्शन नहीं हुआ कोई क्या? मैं पूछ रहा हूं? भई अब ये एसीबी में कम्पलेंट करें। अब ये सीबीआई में कम्पलेंट करें लेकिन ये करेगें कैसे इनकी औकात नहीं है ये कम्पलेंट करने की, इनकी औकात नहीं है। मैं कह रहा हूं ये सदन में, ये सपने में भी नहीं बोल सकते हैं कि जी इन बसों में करप्शन हुआ है और अगर आप में हिम्मत है तो आप सीबीआई को कम्पलेंट कर दो कल। भई

अगर आप सीबीआई को कम्पलेंट कर दो तो मैं अध्यक्ष जी कह रहा हूं मैं कल से सदन में आना छोड़ दूंगा, करके दिखाओ आप, आप करके दिखाओ। दो हजार बसों में जो करप्शन हुआ है अगर ये मानते हैं तो करके दिखाओ कम्पलेंट। बेकार की बातें करते रहते हो।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः भई अब ओमप्रकाश जी खड़े हों। नहीं बैठ जाइए नीचे, नहीं बैठ जाइए नीचे, मैं आग्रह कर रहा हूं। आप नीचे बैठ जाइए अभी। कोई point of order नहीं है, कोई point of order नहीं है। शोएब जी मैं इसीलिए मना कर रहा था मुझे पता है कि क्या करना है इन्होंने बैठिए, बैठ जाइए, बैठ जाइए बिष्ट जी। वो ओमप्रकाश जी की बारी है वो बोल रहे थे ना बीच में, बीच में बोल रहे थे ना ओमप्रकाश जी, उनको रोका है ना। बैठिए, बैठिए।

श्री मोहन सिंह बिष्टः यदि ये गलत बोल रहे हैं आपको उसमें हाथ खड़ा करके स्पीकर से कहना चाहिए प्वाइंट ऑफ आर्डर..

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः कोई आवश्यकता नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। किताब पढ़ लीजिए पहले रूल की।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः रूल की किताब पढ़ लीजिए। बैठिए।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः चलिए ओमप्रकाश जी, मैं रूल की किताब दे रहा हूं। ये लीजिए पढ़ लीजिए किताब। किताब पढ़ लीजिए बैठ कर। बैठ जाइए अब। अब बैठ जाइए समय मत खराब करिए। मोहन सिंह जी मैं बोल रहा हूं बैठिए, बैठिए।

...व्यवधान...

श्री ओमप्रकाश शर्माः अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी, अरे यार ये तो फिर खड़े हो गए।

माननीय परिवहन मंत्रीः ये बसों का घोटाला.. ये बसों का घोटाला..

...व्यवधान...

श्री ओमप्रकाश शर्माः अरे मंत्री जी मेरे पास 15 घोटाले हैं

माननीय परिवहन मंत्रीः पहले किसी और ने लिया हुआ था अब वो शांत हैं अब इन्होंने पकड़ लिया।

...व्यवधान...

श्री ओमप्रकाश शर्माः मंत्री जी।

माननीय अध्यक्षः चलिए, चलिए।

माननीय परिवहन मंत्रीः पहले हर सेशन में।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः विजेंद्र गुप्ता जी बोलते थे।

माननीय परिवहन मंत्रीः पहले हर सेशन में यहां के एक माननीय सदस्य हैं जो उछल-उछल के बोलते थे बसों में घोटाला हो गया, बसों में घोटाला हो गया। अब वो तो शांत हैं।

...व्यवधान...

श्री ओमप्रकाश शर्माः अरे हम तो कह रहे हैं ना अब।

...व्यवधान...

माननीय परिवहन मंत्रीः अब इन्होंने पकड़ लिया आपने गलत चरण पकड़ लिए हैं, आपने चरण गलत पकड़ लिए हैं।

माननीय अध्यक्षः कैलाश जी बैठिए प्लीज बैठिए।

...व्यवधान...

श्री ओमप्रकाश शर्माः अच्छा आप बैठिए। पधारिए, पधारिए। माननीय स्पीकर साहब मैंने आठ दस प्वाइंट उठाए एक में ही मंत्री जी विचलित हो गए हैं। मेरा कोई ऐसा मानस नहीं था कि मैं मंत्री जी को विचलित करूं। ये जो मैं कह रहा हूं, सुनिए, मैं जो कह रहा हूं ये हर मीडिया पर चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलैक्ट्रोनिक मीडिया हो, हर

जगह ये चीज़ भरी पड़ी है अगर आपने इसका खंडन करना है तो आप विस्तार से बाद में करिए। आप तो मंत्री हैं।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्ष: ओमप्रकाश जी आप बहस में मत पड़िए प्लीज़। अपना विषय जारी रखिए।

श्री ओमप्रकाश शर्मा: चलिए, ठीक है ठीक है।

माननीय अध्यक्ष: समय सारा खराब होगा।

...व्यवधान...

श्री ओमप्रकाश शर्मा: धन्यवाद मंत्री जी धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: आप अपना विषय जारी रखिए।

...व्यवधान...

श्री ओमप्रकाश शर्मा: अरे ठहर जाओ

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्ष: फिर आप तानाशाह बोलोगे मुझे।

श्री ओमप्रकाश शर्मा: दिल्ली में 24 प्रमुख।

माननीय अध्यक्ष: शुरू करिए, शुरू करिए प्लीज़।

माननीय अध्यक्षः श्री ओमप्रकाश शर्माः दिल्ली के 24 प्रमुख अस्पताल के निर्माण कार्यों में घोटाला, दिल्ली सरकार के तीन अधिकारियों ने स्वास्थ्य मंत्री को नोट लिख कर दिया और एक विशेष रूप से एलएनजेपी में 465 का बजट बढ़कर 1125 करोड़ कर दिया गया। महा घोटाला, शीश महल घोटाला, 45 करोड़ का रेनोवेशन हुआ ज़मीन की कीमत पता नहीं, पेड़ कितने काटे पता नहीं, कायदे कानून का सबका उल्लंघन कर दिया और पापबोध ये है सब कुछ करने के बाद भी अब नौरात्रों के बाद आप उसमें रह नहीं सकेंगे। तो ये आपका पैनिक बटन घोटाला आपने कारों से, टैक्सियों से, बसों से 500 करोड़ रुपया इकट्ठा किया वो घोटाला। सुरमेक पंजीकरण घोटाला एक लाख 11 हजार 516 फर्जी पंजीकरण किए गए। मुख्यमंत्री आवास में मारपीट। मंत्री आपके संदीप कुमार जी ने राशन कार्ड में क्या किया उन शब्दों को मैं बोलना नहीं चाहता हूं।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः चलिए, ओमप्रकाश जी।

श्री ओमप्रकाश शर्माः परिवार पे कुत्ते छोड़ने वाले हों चाहे जाली डिग्री वाले हों। इतने काम करने के बाद।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः चलिए, बैठिए, बैठिए।

श्री ओमप्रकाश शर्माः आप सीबीआई और ईडी।

माननीय अध्यक्षः चलिये, ओम प्रकाश जी अब बैठिये प्लीज़।

श्री ओमप्रकाश शर्माः से झगड़ा करते हैं, आपका तो इतिहास ये दाग अच्छे हैं केजरीवाल जी।

माननीय अध्यक्षः चलिये बैठिये ओमप्रकाश जी बैठिये, आप मुझसे बात करिये।

श्री ओम प्रकाश शर्माः ये दाग आपको मुबारक हों और मैं ये समझता हूं आप जो सत्तर का ख्वाब देख रहे हैं न कहीं ऐसा न हो जो पार्लियामेंट में हुआ है। जो जीरो बटा सात हो गया है। कहीं सत्तर बटा जीरो दोबारा से न हो जाये धन्यवाद।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः विजेन्द्र जी, बड़ा संक्षेप में रखिये आप लंबा बोलते हैं थोड़ा, प्लीज़।

श्री विजेंद्र गुप्ताः अध्यक्ष जी, यहां पर अब ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब ने डीटीसी की बात की।

माननीय अध्यक्षः नहीं उस चर्चा में मत जाईये।

श्री विजेंद्र गुप्ताः मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा।

माननीय अध्यक्षः मैं बहस नहीं करवाना चाहता। जो विषय है उस पर बोलिये।

श्री विजेंद्र गुप्ताः वो मामला आज भी बसों की कीमत 870 करोड़ रुपये पेमेंट 4500 करोड़ की थी उसमें इसलिये वो घपला है, चलिये वो अलग बात है। आज जिस मुद्दे पर हम लोग बात कर रहे हैं देखिये ये देश कानून से चलता है। यहां पर कानून का राज है। राजा हो या रंक, कानून सबके लिये बराबर है। मुझे याद है हालांकि मैं बहुत छोटा था उस समय 1975 में देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थीं और उनके अगेंस्ट इलाहाबाद कोर्ट ने अन्फेयर मींस का केस चुनाव जो लड़ी थी वो उसमें धांधली करके वो जीती हैं, उनके खिलाफ फैसला दे दिया और जिसकी वजह से वो डिस्क्वालिफाई हो गयीं। वो बात अलग है। लेकिन अदालत ने उनके खिलाफ फैसला दिया और वो डिस्क्वालिफाई हो गयी और जिसकी वजह से देश में उन्होंने इमरजेंसी लगा कर पूरे संवैधानिक व्यवस्था को चूर चूर कर दिया। तो ये देश कानून से चलता है, कानून अपना काम करता है, कानून अपना काम करे इसका हमें गर्व है क्योंकि हम दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हैं। अभी अमेरिका के राष्ट्रपति ने भी भारत की जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, चुनावी प्रक्रिया है उसको बधाई दी है और कहा है कि इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी सबसे स्ट्रेंथन है। अब मेरा कहना है कि केजरीवाल साहब का वीडियो वायरल है। जब वो खुद ईडी और सीबीआई की बात करते हुए कह रहे हैं कि हम इन सब भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ ईडी और सीबीआई से कार्रवाई करवायेंगे और उन्होंने सूची भी जारी की थी। वो बात अलग है कि सत्ता में आने के बाद वो स्वयं और उनकी पार्टी भ्रष्टाचार में लिप्त हो गयी। शराब नीति कोई छोटा मामला नहीं है।

शराब नीति में भी वही हुआ जो बस खरीद में हुआ था। जैसे ही मामला प्रकाश में आया बस खरीद वापस ली, उसी तरह से शराब नीति वापस ले ली। क्यों? मोबाईल क्यों तोड़े गये, रिकॉर्ड क्यों मिटाये गये, कन्वर्सेशन क्यों हटाई गयी। और इस सबके बाद भी आप दोनों की बेल यहां से वहां आप गये, आप लोगों को इस्तीफे देने पड़े। ये हमारी कानून की शक्ति है जिसके कारण ही ये स्थिति उत्पन्न हुई है। बेल के वक्त भी अगर मेरी बात गलत हो या हो सकता है उसमें कुछ सुधार की गुंजाइश हो तो स्वागत है आप सबका, क्या आपकी बेल मेरिट पर हुई है, या आपकी बेल मुकद्दमें की कमजोरी के कारण हुई है? अदालतों ने, सुप्रीम कोर्ट ने भी जो अपराध आपके ऊपर जो आरोप हैं उसके बारे में बल्कि आपको कंडीशनल बेल दी गयी है। और जो कंडीशनल बेल दी गई है उसका..

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः जून साहब नहीं प्लीज, प्लीज अभी बोलना है सबने, उत्तर देंगे वो। नहीं, मैं जून साहब नहीं। प्लीज़।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः जून साहब बैठिये प्लीज़।

...व्यवधान...

श्री विजेंद्र गुप्ताः बैठ जाईये। मुझे मालूम है आपके नेता यहां बैठे हैं आपकी टिकट उनके हाथ में है। आप बैठिये।..

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः जून साहब बैठिये।

...व्यवधान...

श्री विजेंद्र गुप्ताः आप बोलिये। क्योंकि अब सुप्रीमो यहां है और ये आपकी किस्मत है या बदकिस्मती है कि सुप्रीमो यहां बैठे हैं।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः विजेन्द्र जी, आप बोलिये इधर मुझसे बात करके बोलिये।

श्री विजेंद्र गुप्ताः मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जो एजेंसीज़ अच्छा काम करें क्योंकि आप व्यक्तिगत आहत हुए हैं, आप व्यक्तिगत भ्रष्टाचार के मामले में आरोपित हैं लेकिन आप जिनके साथी हैं जो पहले यूपीए था अब वो इंडी अलाइंस है जिनके साथ आप हैं, जिनकी नीतियों के साथ आप हैं। एक प्रकार से जब आपका समझौता है तो उनके बारे में भी मैं बताना चाहता हूं कि उस यूपीए, इंडी का 10 साल राज रहा 2004 से 2014 तक और उन्होंने ईडी और सीबीआई ने उनके राज में 5000 करोड़ रुपये की रिकवरी की थी मात्र 5000 करोड़ रुपये की रिकवरी हुई 10 साल में और अब मोदी जी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, एनडीए की सरकार है तो 10 सालों में सवा लाख करोड़ रुपये की रिकवरी हुई है। ये भ्रष्टाचार के मामले में, एक तरफ 5000 करोड़ रुपये की रिकवरी करने वाले लोगों के साथ

आप खड़े हैं जबकि आप उनको बंद करना चाहते थे, उनके भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े थे और एक तरफ वो लोग हैं जिन्होंने, मोदी जी ने लालकिले की प्राचीर से ये ऐलान किया था कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस है। अध्यक्ष जी, मशीनें तक टूट गई नोट गिनने की इतने नोट पकड़े हैं लेकिन आपका एक बयान नहीं आया उस दौरान। आपने एक बार भी नहीं कहा कि ये जो सैकड़ों करोड़ रुपये कैश पकड़े जा रहे हैं ये लोग इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इससे साफ है कि आप का एजेंडा बदल चुका है, आपकी नीयत बदल चुकी है, आपकी नीति बदल चुकी है और अब आपका सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार में विश्वास है और देश की संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करना, अराजकता फैलाना ये आपका मोटो है, धन्यवाद।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः श्रीमान मनीष सिसोदिया जी।

श्री मनीष सिसोदियाः बहुत-बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, मैं 18-19 महीने बाद इस सदन में बोल रहा हूं खड़े होकर और ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम कुकर्मों, कुचक्रों, साजिशों के बावजूद मैं सीना चौड़ा करके यहां खड़ा हुआ हूं तो इसलिए खड़ा हुआ हूं कि ईमानदारी से काम करता रहा हूं। अभी ये भाजपा नेता बोल रहे थे विजेंद्र गुप्ता जी देश में कानून का राज है। यही तो फख्र है और इसी वजह से तो मैं आज यहां बैठा हूं कि कानून का राज है। अगर इनके पिताजी का राज होता तो मैं जेल में

सड़कर मर गया होता, अगर इनके पप्पा का राज होता तो। देश में कानून का राज है। देश में कानून का राज है इसीलिए आज यहां बैठे हैं और आपकी आंख में आंख डालकर कह रहे हैं कि चोट्टो छोड़ेंगे नहीं तुमको। देश में कानून का..

...व्यवधान...

श्री मनीष सिसोदिया: अध्यक्ष जी वो लाइन इन्होंने पूरी नहीं की इनके दिल का भी मुझे पता है इनका दिल मसोस रहा था, बोले ये कहना चाह रहे थे देश में कानून का राज है, भाजपा में कानून का राज नहीं है। देश तो कानून से ही चलता है लेकिन भाजपा 75 साल वाले कानून से नहीं चलेगी, उनको भी द्:ख है इस बात का।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्ष: भई, ये अब ठीक नहीं है देखिए। अजय महावर जी, मैं चेतावनी दे रहा हूं, प्लीज़।

श्री मनीष सिसोदिया: तो देश में कानून का राज है अध्यक्ष जी इसीलिए कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जितने विपक्ष के नेताओं पर इन्होंने गैर-कानूनी काम किये इनके हर गैर-कानूनी काम पर इनको कानूनी गालियां पड़ रही हैं सुप्रीम कोर्ट से लेकर, हाईकोर्ट से लेकर अब तो लोअर कोर्ट भी इनको गालियां देने लगे हैं। क्या कर रही हैं एजेंसियां, क्या कर रहे हो तुम लोग ये सवाल बीजेपी से पूछे जा रहे हैं, ये ईडी और सीबीआई से नहीं पूछे जा रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट

से लेकर लोअर कोर्ट तक कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो लताड़ रहे हैं एजेंसियों को वो एक्चुअली तो भारतीय जनता पार्टी को लताड़ रहे हैं क्योंकि देश में कानून का राज है और ये लोग गैर-कानूनी काम कर रहे हैं, असंवैधानिक काम कर रहे हैं। कानून का राज है इसीलिए इनको गालियां पड़ रही हैं चारों तरफ, पूरे देश में थू-थू हो रही है इनकी कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता क्या मिल गई एजेंसियों का खुल्ला दुरुपयोग होने लगा और सिर्फ नेताओं के खिलाफ नहीं अध्यक्ष महोदय, हम तो नेता हैं लड़ने के लिए निकलते हैं घर से, जिस दिन सोचते हैं कि राजनीति में जाएंगे उस दिन लड़ने के लिए तैयार होकर निकलते हैं कि लड़ना है कोई रैड कारपेट लेकर यहां नहीं बैठेगा। लेकिन इस देश के व्यापारियों के खिलाफ देखिये कश्मीर से कन्याकुमारी तक अगर आप PMLA के केसेज देख लीजिए, देश के हजारों नहीं लाखों व्यापारियों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने शोषण का अड्डा बना रखा है ईडी को, PMLA के नोटिस दिलवाते हैं 4 बड़े व्यापारियों को जेल में भेज देते हैं और उसके बाद कहते हैं भईया देखो 4 बड़े व्यापारी और 4 बड़े नेता जेल में डाल रखे हैं एक साल से निकलने नहीं दिया, आतंकवादियों वाले कानून, ड्रग माफियाओं वाले कानून लगाकर तुमको भी जेल में डाल देंगे चंदा दे दो और चंदा देना पड़ता है बेचारे को। व्यापारियों का ऐसा शोषण कर रखा है आप दिखा लीजिए हाई नेटवर्थ इनकम के कितने लोग भारत छोड़कर गये हैं और उनमें से कितने लोगों को PMLA का नोटिस दिया गया था शर्म से डूब मरेंगे भारतीय जनता पार्टी वाले अगर ये डेटा सामने आ जाए तो।

बात हम सिर्फ अपोजीशन की नहीं कर रहे हैं, मैं तो 17 महीने इनके कुकर्मों के कारण जेल में रहकर आया हूं कानून का राज नहीं था इसलिए जेल में रहकर आया हूं। कानून तोड़-तोड़कर राज बना रहे हैं। 17-18 महीने मुझको जेल में रखा, मुझको नुकसान हुआ, मैं अपने परिवार से दूर रहा, असेंबली से विधान सभा से दूर रहा, मैं लोगों से दूर रहा ये मुझको नुकसान हुआ लेकिन असली नुकसान तो देश को हुआ, जनता को हुआ, दिल्ली की जनता को हुआ जिसने भरोसा करके शिक्षा मंत्री बनवाया था, केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बनवाया था। केजरीवाल जी ने शिक्षा मंत्री का काम दिया था, मैं स्कूल बनवा रहा था, अस्पताल बनवा रहा था, टीचर्स युनिवर्सिटी बनवाई थी उसका क्या हाल है, स्किल युनिवर्सिटी बनवाई थी उसका क्या हाल कर रखा है इन लोगों ने। मैंने स्पोर्ट्स की युनिवर्सिटी, स्किल युनिवर्सिटी, टीचर्स युनिवर्सिटियां बनवाई। टीचर्स को फिनलैंड भेज रहे थे पढ़ने के लिए शिक्षा की ट्रेनिंग के लिए, आज भी पंजाब के टीचर्स को भेजकर आया हूं फिनलैंड, हमारे यहां दिल्ली के रुकवा दिये। ये नुकसान हुआ, मैं होता तो इन चीजों के लिए 4 वाइस लड़ रही थीं पांचवी वाइस बनकर मैं भी लड़ता और इनको करते, लेकिन नुकसान हुआ।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात पर आऊँगा उससे पहले भाई मदन लाल जी ने जहां से बात शुरु की कि बात सिर्फ मेरी नहीं है, बात सिर्फ सर की नहीं है केजरीवाल साहब की, बात यह है कि लोकतांत्रिक रूप से जब जनता ने इनको इनकी औकात दिखा दी कि भाई तुम्हारी औकात 7-8 सीट से ज्यादा नहीं है और पहले तो 3 सीट

से ज्यादा नहीं थी उस वक्त इन्होंने क्या खेल शुरु किया दिल्ली में एजेंसियों के दुरुपयोग का। उन्होंने, मदनलाल जी ने थोड़ा सा डेटा पढ़ा 50 केसेज दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री के ऊपर लगा रखे हैं। 12 केसेज मेरे ऊपर लगा रखे हैं इनमें से ज्यादातर खत्म हो गये हैं। हमारे केसेज में से ज्यादातर खत्म हो गये हैं। ये जो बचे हैं ये भी खत्म हो जाएंगे। इन्होंने 3 केसेज सत्येन्द्र जैन के ऊपर लगाये जिनमें से 2 केस खत्म हो गये, खारिज हो गये, 1 बच रहा है अभी वो भी खारिज हो जाएगा। इन्होंने 1 केस गोपाल राय जी के ऊपर लगाया 2012 का निकाल कर, गोपाल राय जी उससे डिस्चार्ज हो गये हैं ये कानून के राज की बात कर रहे हैं। 3 केस इन्होंने कैलाश गहलौत जी के ऊपर लगाये 2015 में, वो भी खत्म हो जाएंगे, ये कौन से कानून के राज की बात कर रहे हैं। नरेश बाल्यान जी हमारे एमएलए साहब हैं उनके ऊपर अध्यक्ष महोदय इन्होंने 3 केस लगाये नरेश बाल्यान साहब के ऊपर तीनों केसेज में नरेश भाई डिस्चार्ज होकर निकले हैं, शर्म आनी चाहिए इनको। गुलाब सिंह यहीं बैठे हुए थे अभी, गुलाब भाई पीछे पहुंच गये, गुलाब भाई इनके ऊपर 3 केसेज लगाये तीनों में डिस्चार्ज होकर निकले हैं गुलाब सिंह जी, तीनों केसेज में डिस्चार्ज होकर निकले हैं। अमानतुल्ला खान, उनके ऊपर इन्होंने 20 केस लगा रखे हैं, 17 में डिस्चार्ज हो चुके हैं वो और बाकी 3 में भी डिस्चार्ज होयेंगे। विशेष रवि भाई, करोल बाग से एमएलए, एक केस लगाया उसमें उनको एक्युटल मिल चुका है। बंदना कुमारी बहन हमारी बैठी हैं इनके ऊपर 6 एफआईआर की गई और 6 की 6 एफआईआर झूठी साबित हुई

इनके ऊपर जो की गई, 6 एफआईआर की गई बंदना बहन के ऊपर। राखी बहन हमारी बैठी हैं इनके ऊपर 3 केस लगाये गये उनमें से 1 से अक्विटल हो चुका है, 2 में से भी अक्विटल होने वाला है इनका। आप अध्यक्ष की चेयर पर बैठे हैं न्यूट्रल हैं चूंकि आप इस पार्टी के टिकट से जीते थे इन्होंने आपको भी नहीं छोड़ा, आपके ऊपर भी इन्होंने 2 केस लगाये और उसमें भी अक्विटल हो गया।

...व्यवधान...

श्री मनीष सिसोदिया: आप लोगों ने लगाये। ऋतुराज झा, 2 केस लगाये दोनों में डिस्चार्ज हो चुके हैं ऋतुराज भाई हमारे। दिनेश मोहनिया 9 केस लगाये, 9 में से 8 में डिस्चार्ज हो चुके हैं और एक में अभी कोग्नीजेंस लेंगे तो उसमें भी डिस्चार्ज ही निकलेंगे। जरनैल सिंह 2 केस लगाये दोनों में डिस्चार्ज हो चुके हैं। संजीव झा, 3 केस लगाये, 2 में डिस्चार्ज हो चुके हैं, 1 अभी बाकी है उसमें भी डिस्चार्ज होएंगे। ये बता रहे हैं कानून का राज है कौन से कानून की बात कर रहे हैं ये सारे के सारे केसेज कौन से कानून में आते हैं? बीजेपी के झूठ बोलने के झूठ फैलाने के और एजेंसियों के दुरुपयोग के अलावा किसी कानून में नहीं आते हैं ये।

मुझको जेल भेजा, अरविंद केजरीवाल जी को जेल भेजा, हम तो स्कूल बनवा रहे थे यहां बैठकर काम कर रहे थे। 30 हजार करोड़ का बजट होता था, इसी विधान सभा में पहला बजट पास किया था 30 हजार करोड़ का और उससे पहला बजट जिस बार मैं वित्त मंत्री के

रूप में बजट पेश किया उससे पहला बजट रिकार्ड है विधान सभा का उठाकर देख लीजिए 25 हजार करोड़ का बजट था और उससे पहले के बजट जो थे वो कभी 24 हजार करोड़ रुपये, 23 हजार करोड़, पिछले 5-7 साल हमारे आने से पहले देखेंगे तो 20 हजार करोड़ से 25 हजार करोड़ पहुंचने में 5-7 साल लगते थे बजट को लेकिन केवल 5 साल के अंदर-अंदर 30 हजार करोड़ का बजट 75 हजार करोड़ रुपये पहुंचा दिया। अगर बेईमानी करनी होती तो उसमें से अगर .001 परसेंट कर देते मेरी पार्टी के कई साल के लिए फंड इक्ट्ठा हो जाता अध्यक्ष महोदय लेकिन नहीं करनी थी इसीलिए 30 हजार करोड़ का जो बजट था वो धीरे-धीरे करके, ईमानदारी से टैक्स क्लेक्शन करके, ईमानदारी से नीतियां बनाकर, ईमानदारी से खर्च करके उसको किया तब 30 हजार करोड़ का बजट 75 हजार करोड़ रुपये पहुंचा। ये एजेंसियों का दुरुपयोग करते हैं हम कानून का सदुपयोग करते हैं। हम अपनी दी हुई पावर का सदुपयोग करते हैं इसलिए 30 हजार करोड़ का बजट 75 हजार करोड़ रुपये हो गया और झूठे आरोप लगाते हैं फिर। मैं इन केसेज की डिटेल में नहीं जाऊँगा, जाऊँगा तो एक-एक एमएलए खुद बता सकता है कि किस-किस तरह से लगाये थे।

मेरे ऊपर जो सबसे संगीन आरोप लगाया गया मैं उसके ऊपर बात करना चाहता हूं दो मिनट अध्यक्ष महोदय आपकी अनुमति से। इन्होंने मेरे ऊपर आरोप लगाया, कौन सा आरोप, बात तो कह रहे थे भ्रष्टाचार की लेकिन आरोप कौन सा लगाया जो आतंकवादियों की फंडिंग और ड्रग माफिया की फंडिंग के ऊपर कानून लगाये जाते हैं वो मेरे ऊपर

लगाये, मैं आतंकवादी हूं, मैं ड्रग माफिया की फंडिंग करता हूं, क्या अरविंद केजरीवाल जी आतंकवादी हैं, अरविंद केजरीवाल जी ड्रग माफिया की फंडिंग करते हैं? हमारे ऊपर आरोप लगाये जा रहे हैं कि मतलब जो कानून दुनियां भर में बनाये गये इसलिए कि आतंकवादियों की फंडिंग रोकनी है, आतंकवादियों की फंडिंग करने वालों के ऊपर लगाये जाते हैं, ड्रग माफिया की फंडिंग करवाने वालों के ऊपर लगाये जाते हैं वो कानून मनीष सिसोदिया के ऊपर लगाये जा रहे हैं, वो कानून अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर लगाये जा रहे हैं ताकि जमानत न मिल सके। आरोप कोई भी ऐसे ही लगा दो उसके बाद कानून की धाराएं ऐसी–ऐसी लगा दो आतंकवादियों वाली, ड्रग माफियाओं वाली ताकि जमानत न मिल सके और फिर यहां होके बोलें जमानत–जमानत।

तो अध्यक्ष महोदय, कुल मिलाकर देखें तो इन्होंने जो साजिश रची, मनोहर कहानी रची उसमें निकला कुछ नहीं, निकलेगा भी कुछ नहीं और अभी तक जब इन्होंने खूब छान मारा, छापे मारे मेरे घर पर, एक चवन्नी नहीं मिली इनको मेरे घर से। सीबीआई वाले भी दुखी होकर गये जी क्यों पूरा दिन लगा दिया आपके घर पर। फिर इनको लगा नहीं–नहीं उसके लॉकर में कुछ होगा, लॉकर में पहुंच गये सीबीआई वाले, इन्होंने उसको कहा सीबीआई वालों को लॉकर में छानकर आओ, लॉकर में रखा होगा, 2 साल से लॉकर खुला नहीं है इसका, जरूर लॉकर में कुछ होगा, लॉकर में भी निकला छुनझुना, बच्चे का झुनझुना निकला चांदी का एक। फिर जो है खूब पड़ताल की इन्होंने अफसरों से की, इधर की, उधर की, मेरे गांव में ढूंढ़ा, रिश्तेदारों से पूछा, सबसे

पूछा। इन्होंने व्यापारियों से पूछा, जितने लोगों को लाइसेंस दिये गये थे, सबसे पूछा भई किसी ने पैसे दिये, सबने ऑन रिकार्ड कहा जी कोई नहीं दिये, न किसी ने मांगे, न किसी ने दिये, सबने ऑन रिकार्ड कह रखा है एजेंसीज के स्टेटमेंट में लेकिन बीजेपी उनके पीछे पड़ी हुई थी। मैं सर कस्टडी में रहा हूं, सीबीआई की कस्टडी में रहा हूं और ईडी की कस्टडी में रहा हूं और जब मैं कस्टडी में बैठता था तो बेचारों के पास, अफसरों के पास भी पूछने के लिए तो कुछ होता नहीं था 10-15 मिनट आधे घंटे बात करते थे 24 घंटे कस्टडी में रखते थे तो मेरे से गप्पे मारते थे, बताते थे फिर धीरे-धीरे वो खुलने लगे बताने लगे क्या मामला है, जी क्यों हमें करना पड़ रहा है। बेचारे इज्जत भी करते थे, बोले जी थोड़ी सी हमारे भी घर में प्रॉब्लम है, बच्चों को समझ नहीं आ रहा कैसे पढ़ाएं थोड़े उनके बारे में भी गाइड कर दो। मैं तो बैठकर उनके बच्चों के बारे में शिक्षा गाइड कर रहा था वहां बैठकर। लेकिन थोड़ी बहुत जो बात हुई उनसे, थोड़ी बहुत पूछताछ के नाम पर उन्होंने कुछ स्टेटमेंट लिये और जो बताया उन्होंने जब कॉन्फिडेंस में, मैं भी चौंक गया, भारतीय जनता पार्टी सीबीआई और ईडी दोनों के पीछे पड़ी हुई थी कि ये शराब घोटाले को 10 हजार करोड़ का घोटाला बनाओ। अधिकारियों ने कहा साहब 10 हजार करोड़ में से कोई चवन्नी तो मिले तब तो 10 हजार करोड़ की बात करें इनके यहां तो किसी के यहां चवन्नी नहीं मिल रही, कहां से 10 हजार करोड़ का बनाएं। तो कई महीने तक ये लोग बीजेपी वाले सीबीआई और ईडी के अफसरों के पीछे पड़े रहे कि इसको 10 हजार करोड़ का घोटाला बनाओ, 10

हजार करोड़ का घोटाला बनाओ। सीबीआई और ईडी वाले अफसरों ने हाथ खड़े कर दिये साहब नहीं बन पाएगा। फिर उन्होंने कहा अच्छा चलो 10 हजार करोड़ का नहीं तो 1000 करोड़ का बना दो। फिर उन्होंने कहा साहब एक रुपया तो मिला होता, कोई चवन्नी तो मिली होती किसी के यहां से, नहीं मिल रही, वो जो वित्त मंत्री था उसी के घर से कुछ नहीं मिल रहा, कहीं से कुछ नहीं मिल रहा कैसे 1000 करोड़ का बना दें। तो फिर उन्होंने कहा अच्छा चलो ऐसा करो 100 करोड़ का बना दो। 10 हजार करोड़ का नहीं बना, 1000 करोड़ का नहीं बना, 100 करोड़ का नहीं बना, उस पर भी उन्होंने कह दिया साहब कोई चवन्नी तो मिले, एक रुपये का भी नहीं बना पा रहे हम तो।

तो फिर इन्होंने उनको जो भी किया होगा डराया-धमकाया होगा, जो भी किया होगा फिर किसी को पकड़ा, इसको पकड़ा उसको पकड़ा, इधर से पकड़ा, जेल में डाला उसके ऊपर वही आरोप लगाये आतंकवादियों वाले, ड्रग माफिया वाले तो जो आदमी 10-10, 12-12 बार कह चुका था साहब मेरे से तो मांगा नहीं, मेरे से तो किसी ने पूछा नहीं, मैंने तो किसी को दिया नहीं उसकी स्टेटमेंट है उन लोगों की, अचानक उनमें से किसी आदमी को ये धमकाते हैं बेटा जेल है सड़ जाएगा, तुझे बाहर निकालने का एक ही रास्ता है, तू मनीष सिसोदिया का नाम ले, अरविंद केजरीवाल का नाम ले। जो आदमी कह चुका था, उसकी स्टेटमेंट हैं और यही होगा ट्रायल में देखियेगा। जिसके स्टेटमेंट हैं कि साहब मैं तो मनीष जी से कभी कहीं मिला भी हूं तो मेरी तो हिम्मत

ही नहीं पड़ती थी उनसे बात करने की। जो आदमी रिटन में स्टेटमेंट दे रहा है इन्वेस्टिगेशन में कि मैं तो कभी मनीष जी से मिलता था मेरी तो हिम्मत ही नहीं पड़ती थी बात करने की, उसको जेल में डाला, 6 महीने बाद उससे एक स्टेटमेंट लिया मेरे खिलाफ कुछ-कुछ उससे बुलवाया, मुझको उठाकर अंदर जेल में डाल दिया। जब मेरी बेल का मैटर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे ही इनकी हरकतों के कारण कहा था कि तुम जो ये कानून के सबूत-वबूत लेकर आये हो जो सो-कॉल्ड तुम्हारे सबूत हैं, दो क्वेश्चन में फ्लैट हो जाएंगे तुम्हारे सबूत, ये बात सारे अखबारों में फ्रंट पेज पर छपी थी जब मैं जेल में था। दो क्वेश्चन में फ्लैट हो जाएंगे तुम्हारे सारे सबूत ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। ये सबूत लाये ये हमारे खिलाफ जिसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है भई दो क्वेश्चन में फ्लैट हो जाएंगे जब ट्रायल में चलेगा तो।

तो मुझे जेल में रखा फिर उसके बाद में फिर हुआ भई अब संजय भाई को कैसे डालें। मैं जब अंदर कस्टडी में था ईडी और सीबीआई की वहां अंदर के अधिकारी मुझे बता देते थे देखो जी आपको लाए हैं, पहले 10 हजार करोड़ की बात कर रहे थे बीजेपी वाले, फिर 1000 करोड़ पर आ गये, फिर 100 करोड़ पर आ गये, बोले कुछ तो कर दो यार, कुछ तो लगा दो यार तब भी नहीं लगाया तो बोले एक स्टेटमेंट के आधार पर ही लगाओ इनको अंदर डालो, बस जी हमें करना पड़ रहा है, क्या करें नौकरी करनी है। फिर बोले, वो बता देते थे मेरे को, बोले अभी तो हमें आदेश है संजय सिंह को भी

लाना है और बाद में थोड़े समय बाद केजरीवाल जी को भी लाना है चुनाव से पहले, पहले ही बता दिया था। बोले अच्छा जी मैंने कहा चुनाव से पहले, हां बोले चुनाव से पहले करेंगे कुछ, ऐसा ऊपर से जब आदेश आएगा करेंगे। खैर संजय भाई को ले गये वहां भी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि देखो अगर हम केस की मैरिट पर चले गये तो तुम्हारा केस डिस्टर्ब हो जायेगा, इसलिए बैटर है इसको बेल देने दो। थोड़ी देर बाद में ईडी वाले बोले जाके बीजेपी वालों से पूछके सर दे दो बीजेपी वाले कह रहे दे दिया। मतलब आकाओं का मतलब बीजेपी होता है वहां। संजय भाई को भी बेल हो गई। अरविन्द केजरीवाल जी के खिलाफ क्या लगाया, एक आदमी सीएम साहब से टाइम मांगता है मिलने का एमपी है। वो उसने टाइम मांगा, बोला जी मैं मिलना चाहता हूँ, मेल भेजा। एक बार भेजा, दो बार भेजा मेल भेजा। उसको टाइम दे दिया गया। मिल गया, मिल के चला गया सर से पूछ रहा है कि भई मेरी कोई जमीन है, कुछ ट्रस्ट है हमारी उसके लिए कुछ जमीन उमीन चाहिए कहीं इतनी बात कह के चला गया। लोग एमपी हैं आ सकते हैं। सर भी मिल लिए। अब जब सर के खिलाफ कुछ नहीं मिला, उन लोगों से भी कुछ नहीं मिला जिन लोगों से मेरे खिलाफ बुलवा लिया था। तो फिर उस एमपी को पकड़ा क्योंकि वो इनका पुराना फंडर भी था। उसको पकड़ा, बोले जी अब केजरीवाल जी के खिलाफ बोलो। उसको पकड़ के ले गए। उसने बोला जी मैं गया तो था मिलने, लिखित में 6 मिनट बातचीत हुई थी। 10-12 अफसर मौजूद थे बातचीत में। साहब मैंने तो जमीन की बात की थी उनसे। कह के वो आ गया।

फिर उन्हें लगा यार केजरीवाल जी को किस बहाने से पकड़े अब। अब तो ये ना 10 हजार करोड़ काम कर रहा है, ना एक हजार करोड़ काम कर रहा है, ना 100 करोड़ काम कर रहा है। मनीष सिसोदिया वाले पे भी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि ये तो क्वेश्चन 2 मिनट में फ्लैट हो जायेंगे, तुम्हारे क्वेश्चन फ्लैट हो जायेंगे अब क्या करें। तो इन्होंने उस आदमी के बेटे को गिरफ्तार किया, एमपी साहब के और उसको 6 महीने जेल में रखा और 6 महीने जेल में रखने के बाद उसको लालच दिया और मैं इन्हीं का भाजपाई शब्द यूज कर रहा हूँ जानबूझके क्योंकि ईडी वही बोलती है कोर्ट में या ईडी वही बोलती है अपने उसमें जो ये उसको डिक्टेड करते हैं। इन्होंने उसको शब्द को यूज किया और इनके वकील ने वहां पर वो शब्द यूज किया है कि साहब ऐसे लोलीपोप तो हमको देने पड़ते हैं। लोलीपोप दिया उसको। 6 महीने एक भाजपाई फंडर एमपी के बेटे को 6 महीने जेल में रखा और फिर उसको जैसा ईडी खुद मानती है लोलीपोप दिया तेरे को बचा लेंगे, तेरे को जमानत करवा देंगे, केजरीवाल जी का नाम ले दे। तो जो आदमी पहले कह रहा था जी मैं तो 6 मिनट मिला 10-12 अफसरों की मौजूदगी में मिला था, उसने एक स्टेटमेंट दिया जी मेरे से पैसे मांगे थे। उसका बेटा बाहर आ गया। अब ये तो इसीलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये ट्रायल में चलेगा तो दो क्वेश्चन में फ्लैट हो जायेगा। अरे एक आदमी जो पहले कह रहा है जी 6 मिनट मिला था, मांग के अपॉइंटमेंट मिला था, रिकॉर्ड पर अपॉइंटमेंट मांगा हुआ है और 10-12 अफसरों की मौजूदगी में मिला था। 10-12 अफसरों की मौजूदगी

में 6 मिनट की मीटिंग में केजरीवाल जी ने तेरे से 100 करोड़ भी मांग लिए और तू पहले मना भी कर रहा था जी मैं तो जमीन मांगने गया था। ये कोई केस हैं क्या, ये मजाक हैं लेकिन क्योंकि इनके पास पावर है। इनके पास पावर है कि केजरीवाल जी जो काम कर रहे हैं दिल्ली में उनको कह सकते हैं भई ये तो आतंकवादी है डालो अंदर, ये ड्रग माफिया है डालो अंदर। वो कानून लगा-लगा के अंदर डाल रहे हैं, तो एजेंसियों के दुरूपयोग का तो इनको पीएचडी अवॉर्ड मिलना चाहिए। इस देश में इससे ज्यादा और इससे मैं आपकी अनुमति से शब्द यूज कर रहा हूँ इससे ज्यादा टुच्चेपने के काम पे एजेंसियों का दुरूपयोग कहीं नहीं हुआ। कभी नहीं हुआ इस भारत के इतिहास में। भारत का इतिहास जब लिखा जायेगा, इस समय का इतिहास जब आगे लिखा जायेगा तो इनको इतनी लानतें दी जायेंगी कि ऐसे-ऐसे टुच्चेपने की हरकतों पर उतर आये थे एजेंसियों को लेकर, जिन एजेंसियों को इतने शानदार काम के लिए बनाया गया था उनको इतने टुच्चे-टुच्चे कामों पर लगा दिया इन्होंने। हमको तो छोड़ दीजिए मैं अपनी बात कन्क्लूड करूं, हम तो चलिए यहां लड़ रहे हैं इनकी आंखों में आंख डालके, तमिलनाडु में एक किसान उसको बीजेपी के किसी छुट भइये नेता से झगड़ा हो गया। बीजेपी के नेता ने उसको ईडी का नोटिस दिलवा दिया जो आतंकवादियों को दिलवाया जाता है। ऐसी-ऐसी टुच्ची हरकतों पर ऊतर आये हैं ये एजेंसियों के दुरूपयोग पर और देश के, जहां से मैंने बात शुरू की वहीं खत्म करूंगा कि हमारी बात फिर भी नेताओं की लड़ाई है, राजनीतिक लड़ाई है। सर कटाने के लिए निकल के आये हैं, जेल

जाने से डरते नहीं हैं, सर भी काट देंगे तो डरेंगे नहीं। लेकिन इस देश का व्यापारी हजारों लोगों को, लाखों लोगों को नौकरियां दे रहा है इस देश की इकोनॉमी में योगदान दे रहा है और लाखों लड़के-लड़कियों को नौकरी दे रहा है। आज तुम अपने चंदे और धंधे के लिए कितने नोटिस, ईडी के कितने नोटिस व्यापारियों को दिलवा रहे हो जरा गिरेवान में झांक के देखों शर्म आयेगी अपने ऊपर। शर्म आयेगी अपने ऊपर कि हम कर क्या रहे हैं ये देश के व्यापारियों के साथ। नेताओं के साथ जो कर रहे हो वो तो कर ही रहे हो। वो तो इतिहास का हिस्सा बना ही रहे हो लेकिन इस देश के व्यापरियों के साथ क्या कर रहे हो तुम। नौकरी देने वाले आदमी के घर पे ईडी का नोटिस भेज देते हो और फिर उसको समझाते हैं लोग जाके देख भई फलाना बड़ा व्यापारी डेढ़ साल से जेल में है, फलाना बड़ा नेता डेढ़ साल से जेल में है चंदा दे दे नहीं तो तेरा धंधा खत्म। चंदा दे देता है बेचारा, इलैक्ट्रोल बॉन्ड उसको सबसे बड़ा सबूत है। तो मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ कि जिस तरह से ईडी और सीबीआई का दुरूपयोग हो रहा है। इनको शर्म आनी चाहिए। इनको लानत है इस बात पर और मुझे लगता है कि बीजेपी को माफी मांगनी चाहिए देश से बात अरविन्द केजरीवाल जी या मनीष सिसोदिया या आम आदमी पार्टी के जिनका मैंने नाम लिया है एमएलएज की नहीं है, बात पूरे देश के साथ ये लोग गद्दारी कर रहे हैं ईडी और सीबीआई का दुरूपयोग करके। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय।

माननीय अध्यक्षः माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री अरविन्द केजरीवाल जी।

श्री अरविंद केजरीवालः आदरणीय अध्यक्ष महोदय, ईडी और सीबीआई पर आने के पहले थोड़ी-सी दिल्ली की सड़कों की बात कर लेता हूँ मैं। पिछले दो दिन से मैं मुख्यमंत्री आतिशी जी के साथ दिल्ली की सड़कों का मुआयना करने के लिए निकला था। मेरे को याद है जेल जाने के पहले सड़कों की इतनी बुरी हालत नहीं थी, लेकिन मुझे बताया गया कि इन लोगों ने जो रेग्यूलर रिपेयर होती है, रेग्यूलर मेंटेनेंस होती है वो भी नहीं होने दी। तो अभी सड़कों की हालत थोड़ी ज्यादा खराब हो गई है दिल्ली की। तो अभी मैं एक चिट्ठी लिख रहा हूँ आतिशी जी को जोकि चूंकि सबके हित से संबंधित है तो मैं थोड़ा-सा पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। प्रिय आतिशी जी पिछले दो दिन मैं आपके साथ दिल्ली की अलग-अलग सड़कों का इंस्पैक्शन करने गया। इन सड़कों का काफी बुरा हाल है। मार्च महीने में जब मुझे गिरफ्तार किया गया था तब दिल्ली की सड़कें ठीक थीं। अभी कुछ दिन पहले मुझे इनका एक बड़ा नेता मिला। मैंने उससे पूछा कि मुझे गिरफ्तार करके उन्हें क्या मिला तो उसने मुस्कुरा के कहा दिल्ली सरकार को हमने डिरेल कर दिया। दिल्ली को हमने ठप्प कर दिया। उसका जवाब सुन के मैं हैरान रह गया। तो क्या मुझे गिरफ्तार करने का उनका मकसद दिल्ली को ठप्प करना था। क्या उनका मकसद दिल्ली वालों को परेशान करना था। जनता के परेशान होने से कोई व्यक्ति या कोई पार्टी कैसे खुश हो सकते हैं। जाहिर है कि इनका मकसद था दिल्ली के काम रोक के आम आदमी पार्टी की सरकार को बदनाम करना ताकि ये लोग दिल्ली के चुनाव जीत जायें। कोई पार्टी

वोट लेने की खातिर और चुनाव जीतने की खातिर इतना कैसे गिर सकती है कि दो करोड़ लोगों की जिंदगी बेहाल कर दे। हम लोग ऐसे नहीं हैं, हम लोग राजनीति में जनता की सेवा करने के लिए आये हैं। अब हमें युद्धस्तर पे काम करना पड़ेगा। दिल्ली के सभी रूके हुए काम शुरू करवाने हैं। इस बार बारिश भी बहुत हुई है। इस वजह से दिल्ली की कई सड़कें खराब हो गई हैं। कृपया सभी मंत्रियों और विधायकों के साथ सड़क पर ऊतर कर एक एसेस्मेंट करवा लें कि कौन-कौन सी सड़कें खराब हैं और उनका तुरंत रिपेयर शुरू करवा दें। हमें रात-दिन मेहनत करनी पड़ेगी। दिल्ली के सभी रूके हुए काम चालू करवाने होंगे। दिल्ली के लोगों के साथ मिलके उनकी सभी परेशानियों को दूर करना पड़ेगा। मैं एक मिनट ये चिट्ठी आतिशी जी को देना चाहता हूँ।

माननीय अध्यक्षः नहीं आप रूकिये, आप रूकिये।

श्री अरविंद केजरीवालः मेरा सभी विधायकों से भी निवेदन है, खासकर आम आदमी पार्टी के विधायकों से कि इन लोगों ने हमारा काफी समय खराब कर दिया पिछला। पहले मनीष जी को गिरफ्तार करके फिर मुझे गिरफ्तार करके और उसके पहले कोरोना हो गया था उसमें काफी टाइम चला गया था। अब अपने को रात-दिन मेहनत करनी पड़ेगी। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। हम सब लोग जनता की सेवा करने के लिए ही राजनीति के अंदर आये हैं। तो आने वाले कुछ दिनों के अंदर हमें ये सबकी ड्यूटी लगाई जायेगी। सबको रात को या सुबह अर्ली मोर्निंग निकल के सड़कों का मुआयना करना पड़ेगा। जो-जो सड़के

टूटी हुई हैं उनकी एक एसेस्मेंट कर लेते हैं और उन सारी सड़कों का एक साथ रिपेयर करने का खासकर पीडब्ल्युडी की सड़कें जो रिपेयर करने का ऑर्डर आतिशी दे देंगी ताकि सारी सड़कें एक साथ रिपेयर की जा सकें। अब उस मुद्दे पर आते हैं जिसपे चर्चा चल रही है ईडी और सीबीआई के। मैंने 4-5 दिन पहले मोहन भागवत जी को एक चिट्ठी लिखी थी। उस चिट्ठी में मैंने मोहन भागवत जी से 5 मुद्दों की बात की थी और उसमें एक मुद्दा ये भी था कि जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी इस देश के सबसे भ्रष्ट नेताओं को ईडी और सीबीआई से डराकर या पैसों का लालच देकर दूसरी पार्टियों से तोड़-तोड़ के अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हैं, क्या मोहन भागवत जी उनसे सहमत हैं। मोदी जी ने खुद कुछ दिन पहले जिनको भ्रष्टाचारी बोला, अमित शाह जी ने खुद कुछ दिन पहले जिनको भ्रष्टाचारी बोला, भारतीय जनता पार्टी ने खुद जिन लोगों को कुछ दिन पहले भ्रष्टाचारी बोला, कुछ दिन के बाद उनको अपनी पार्टी में शामिल करा लेते हैं। 27 जून, 2023 को प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अजीत पवार पर 70 हजार करोड़ रुपये के घोटाले का आरोप है हम इनको जेल भेजेंगे। 27 जून, 2023 और 5 दिन के बाद 2 जुलाई को उनको अपनी सरकार में शामिल करके उनको उपमुख्यमंत्री बना दिया। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कुछ शर्म आती है। चलो हम तो सारे के सारे खराब हैं पर आपका प्रधानमंत्री 27 जून को जिस आदमी पे 70 हजार करोड़ रुपये के भ्रष्टाचार का आरोप लगाता है और 5 दिन के बाद 2 जुलाई को उसको अपना उपमुख्यमंत्री बना लेता है, क्या मुंह दिखाते हो यार जब अपने

गली में अपने घर जाते हो आप लोग। पूरी दुनिया को क्या मुंह दिखाओगे कि ऐसी पार्टी में आप लोग हो। 22 जुलाई, 2015 को भारतीय जनता पार्टी एक वो निकालती है आसाम के अंदर उसमें कहती है कि हेमंत विश्वशर्मा बहुत बड़ा भ्रष्टाचारी है 22 जुलाई, 2015 को और एक महीने के बाद 23 अगस्त, 2015 को उसको अपनी पार्टी में शामिल कर लेते हैं। ऐसे 25 नगीने हैं मोदी जी के। हीरे हैं जो चुन-चुन के मोदी जी ने दूसरी पार्टियों से इक्ट्ठे किये हैं। ये मोदी जी के बहुत करीब हैं चुन-चुन के वो दूसरी पार्टियों से लेकर आये। उनके ऊपर जितना कचरा था, गंद था सारा साफ किया मोदी जी ने। सारे केस उनके धोये। अजीत पवार एनसीपी के होते थे इनके ऊपर Economic Offensive Wing का केस था, ईडी का केस था दोनों केस बंद करवा दिये मोदी जी ने। प्रफुल्ल पटेल एनसीपी के नेता थे सीबीआई का केस था, ईडी का केस था दोनों केस बंद करवा दिये मोदी जी ने, अपनी पार्टी में शामिल कर लिया प्रधानमंत्री जी ने। प्रताप सरनायक शिव सेना का नेता था इसपे ईडी का केस था, ईओडब्ल्यु का केस था दोनों केस बंद करवा दिये मोदी जी ने बीजेपी में शामिल कर लिया। हेमंत विश्वशर्मा कांग्रेस का नेता था, सीबीआई का केस था ठण्डे बस्ते में डाल दिया इसको अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। हसन मुशरिफ एनसीपी का नेता था, ईडी का केस था ठण्डे बस्ते में डाल दिया मोदी जी ने इसको अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। भावना गवाली शिव सेना की नेता थी, ईडी का केस था इसपर। यामिनी और यशवंत जादव शिव सेना के नेता थे, ईडी का केस था, इनका केस ठण्डे बस्ते में

डाल दिया। सीएम रमेश, रविन्द्र सिंह, संजय सेठ, शुभेन्दु अधिकारी, के. गीता, सोवन चटर्जी, छगन भुजबल, कृपा शंकर सिंह, दिगंबर कामत, अशोक चौहान, नवनी जिंदल, तपसरे, अर्चना पाटिल, गीता कोड़े, बाबा सिद्की, ज्योति मिंडा, सुजाना चौधरी ये इनकी ईमानदारी है। ये जीरो टॉलरेंस है। शर्म नहीं आती लाल किले के ऊपर खड़े होकर पूरे देश को बेवकूफ बनाते हैं। कहते हैं ईमानदार हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। ये 25 नगीने हैं वो पहले नवरत्न होते थे अकबर के जमाने में अब ये 25 रत्न हैं प्रधानमंत्री जी के जिनको। मैं आरएसएस के अंदर कई ऐसे लोग हैं प्रचारक कहते हैं उनको जिन्होंने अपनी जिंदगी जो है वो आरएसएस को दी है। वो जब घर-घर जाते होंगे क्या कहकर वो जनता का सामना करते होंगे कि जिस आदमी को प्रधानमंत्री ने दो दिन पहले कहा कि 70 हजार करोड़ का घोटाला हो गया। सारे बीजेपी वाले आरएसएस वालों ने व्हाट्सएप ग्रुप पर उसको भेजा लोगों को कि 70 हजार करोड़ का घोटाला आज प्रधानमंत्री ने 5 दिन बाद उसको अपने यहां शामिल करके उसको उप-मुख्यमंत्री बना दिया क्या शक्ल दिखाते हैं ये लोग। मैं पूछना चाहता हूँ सारे आरएसएस के कार्यकर्ताओं से, मैं पूछना चाहता हूँ सारे बीजेपी के नेताओं से कि कैसे आप लोग अपनी गली अपने मोहल्ले के अंदर जाते हो और मैं आरएसएस वालों के ऊपर ज्यादा दया आती है उन्होंने कइयों ने अपनी जिंदगी आरएसएस के लिए दे दी और अब उनका एक ही, उनको अब टिकट नहीं मिलती। कांग्रेस वालों को इसको-उसको ला लाकर टिकटें देते हैं उनका काम दरी बिछाने का रह गया बस। कभी कांग्रेसियों के लिए

दरी बिछाते हैं, कभी एनसीपी वालों के लिए दरी बिछाते हैं, कभी शिवसेना वालों के लिए दरी बिछाते हैं। आरएसएस के कार्यकर्ताओं का काम अब केवल दरी बिछाने का रह गया कभी इस नेता के लिए दरी क्योंकि उनको टिकटें मिलती नहीं मिलती। इसके अलावा इन्होंने कई सरकारों की चोरियां की हैं, टोपल किया सरकारों को उखाड़कर फैंका। मार्च 2016 से लेकर मार्च 2024 तक प्रधानमंत्री मोदी जी ने 13 राज्य सरकारों को 15 बार गिराने की कोशिश और उसमें से 10 सरकारों को गिराने में सफल हो गए। ये सरकारें नहीं गिरायीं, ये सरकारों की चोरी की है। ईडी और सीबीआई को भेज कर, उनको धमकी देकर, उनको लालच देकर, पैसे से खरीदकर उनकी सरकारों की चोरी की है इन लोगों ने। ये कोई मामूली वो नहीं है कि सरकारें गिरा दीं। उत्तराखंड में मार्च 2016 में इन्होंने 9 कांग्रेस के एमएलए तोड़कर और हरीश रावत की गिराई। 2016 में अरूणांचल प्रदेश में 33 पीपीए के 43 में से 33 एमएलए तोड़के वहां पर सरकार गिरा दी। वहां सरकार बना ली। गोवा में जुलाई 2019 में इनको बहुमत नहीं मिला, मार्च 2017 के रिजल्ट्स में नतीजन इन्होंने 12 कांग्रेस के एमएलए तोड़कर सरकार बना ली। कर्नाटक में 2019 में इनको बहुमत नहीं मिला इन्होंने 17 कांग्रेस के और जेडीएस के एमएलए तोड़के सरकार बना ली। मध्यप्रदेश में 2020 में इनको बहुमत नहीं मिला और इन्होंने 22 एमएलए तोड़कर, ये बहुत सारे केस हैं। 10 सरकारें तोड़कर इन्होंने सरकार बना ली और आज इन्होंने एमसीडी के ऊपर गलत तरीके से कब्जा कर लिया, एमसीडी की चोरी कर ली आज इन लोगों ने। मोहन भागवत जी से मैंने ये ही चिट्ठी

लिखी थी कि क्या राजनीति में शुचिता होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, आरएसएस ने अब खुलेआम कह दिया भई जो मन में आये करो। आरएसएस ने खुली छूट दे दी है बीजेपी को। ये ही मैंने मोहन भागवत जी से पूछा था क्या मोदी सरकार की बेईमानियों और भ्रष्टाचार का आरएसएस समर्थन करती है, अगर नहीं करती है तो मोहन भागवत जी की जिम्मेदारी बनती है कि खुले शब्दों में, सख्त शब्दों के अंदर पूरे देश के सामने वो ये कहें कि मोदी जी जो सरकार चला रहे हैं वो सरकार बेईमान है, वो सरकार भ्रष्टाचारी है और वो इसका समर्थन नहीं करते हैं। ये मोहन भागवत जी की जिम्मेदारी है कि पूरे देश के अंदर वो ये स्टेटमेंट दें। आज इन्होंने एमसीडी के अंदर जो किया चुनी हुई, मैंने जेल के अंदर सुभाष चन्द्र बोस, भगत सिंह इनको बहुत पढ़ा। इन लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी लगा दी, जान इन्होंने दे दी अपने देश को आजाद कराने के लिए। किस लिए आजाद कराया इन्होंने देश, इसीलिए तो आजाद कराया था कि देश के अंदर एक जनतंत्र होगा, जनता चुनेगी, जनता के चुने हुए नुमाइंदे वो सरकार चलाएंगे, जनता के सपने पूरे करेंगे। इसलिए थोड़े ही करा था कि एक एलजी आकर बैठ जाएगा, अफसर आकर बैठ जाएंगे और चुने हुए लोगों को दरकिनार करके और अपनी मर्जी से सरकार चलाएंगे। दिल्ली के लोगों ने एक मेयर को चुना। दिल्ली के लोगों ने काउंसिलरों को चुना। दिल्ली के लोगों ने एक सदन को चुना, एमसीडी को चुना, दिल्ली नगर निगम को चुना और उनको कहा भई अब आप दिल्ली की व्यवस्था चलाओ दिल्ली के नगर निगम को चलाओ। कानून के अंदर दिल्ली नगर निगम

के कानून में लिखा है कि जो सदन है, सदन की अध्यक्षता मेयर करेगी, एलजी ने आज आर्डर पास कर दिया कि अब अध्यक्षता एडिशनल कमिश्नर करेगा। कल आपको भी हटा देंगे, कल लोकसभा स्पीकर को भी हटा देंगे। वहां पर लिख देंगे अब होम सेक्रेटरी जो है लोकसभा की अध्यक्षता करेगा। राज्यसभा की अध्यक्षता अब जो है वो डिफेंस सेक्रेटरी करेगा। ये क्या हो रहा है इस देश के अंदर। क्या इसीलिए हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान गंवाई थी। खत्म कर दिया जनतंत्र इन लोगों ने। एलजी दिल्ली चलाएगा और एडिशनल कमिश्नर जो है वो नगर निगम की अध्यक्षता, कानून के अंदर लिखा है कि मेयर अध्यक्षता करेगा। कानून के अंदर लिखा है कि मेयर ही कंपीटेंट है नगर निगम की, कॉरपोरेशन की, सदन की मीटिंग बुलाने के लिए। कब मीटिंग बुलाई जाएगी, किस दिन बुलाई जाएगी, कितने बजे बुलाई जाएगी ये मेयर तय करेगा जैसे आप तय करते हैं, अध्यक्ष तय करता है कि मीटिंग किस दिन होगी एडजोर्न होगी, नहीं होगी, किस दिन होगी ये मेयर तय करता है, एलजी ने कर दिया, कमिश्नर ने कर दिया। उसमें लिखा हुआ है कि 72 घंटे का नोटिस दिया जाएगा कोई नोटिस कल रात को 10 बजे नोटिस निकाल दिया कि आज 1 बजे, उसमें कोई कानून के अंदर उनको पावर ही नहीं है, न कमिश्नर को पावर है न एलजी को पावर है ये तो गुंडागर्दी मचा रखी है। उसके अंदर लिखा है कि नोटिस जो है सबके घर भेजा जाएगा, किसी के घर नोटिस नहीं पहुंचा आज। किसी के घर एक व्हाट्सएप कर दिया व्हाट्सएप आधों को मिला आधों को नहीं मिला आधे दिल्ली के बाहर

हैं। ये क्या ये चुनाव कराया है इन लोगों ने। तो आज इन्होंने एमसीडी की चोरी की है जो कि पूरे देश के सामने है और इसकी हम सख्त निंदा करते हैं। एक चीज़ और बहुत जरूरी है सारे सब लोगों को मैं आगाह करना चाहता हूं। ये लोग जानते हैं कि ये लोग दिल्ली हार रहे हैं, बुरी तरह से हार रहे हैं। अब जो मेरे को पता चला है इन्हीं के नेताओं ने मेरे को बताया है। इनके नेताओं ने मुझे बताया है कि बहुत बड़े स्तर पर आम आदमी पार्टी के वोट काटने का और ७र्जी वोट डलवाने का काम इन लोगों ने शुरु कर दिया है। इन लोगों ने हर कॉलोनी में कुछ पेड इम्पलाइज़ रखे हैं। वो पेड इम्पलाइज घर-घर जा रहे हैं जी सब लोग समझ लेना वो घर-घर जा रहे हैं उनसे पूछ रहे हैं आप किस पार्टी को वोट देते हो जी, किस पार्टी के हो। अगर कोई गलती से कह दे आम आदमी पार्टी का हूं तो उसका वोट कटवा देंगे। तो एक तो मैं दिल्ली की जनता को कहना चाहता हूं कि रोज इलेक्शन कमीशन की वेबवाइट पर जाकर अपना वोट चैक कर लेना कि वोट कटवा तो नहीं दिया किसी ने। दूसरा अगर कोई आपके घर पूछने आए कि आप किस पार्टी को वोट देते हो आप कह देना बीजेपी को वोट देते हैं फिर आप सेफ हैं फिर आपका वोट नहीं कटेगा। आप झूठ बोल देना बीजेपी को वोट देते हैं फिर आपका वोट सेफ है आपका वोट नहीं कटेगा और डेली अपने वोट चैक करना और सारे मैं विधायकों को भी कहना चाहता हूं कि अपने-अपने विधानसभा के अंदर जितने बूथ लेवल के आपके वॉलियेंटर्स हैं उनको आगाह कर दीजिए डेलीबेसिस पर चैक करें किसका वोट कटा किसका वोट डला, वो ठीक

डल रहे हैं, गलत डल रहे हैं इसके ऊपर अपने को निगाह रखनी है और इतनी बुरी राजनीति मैंने कभी नहीं देखी थी। मेरा तो छोटा सा राजनीतिक जीवन है, मैं तो 10-12 साल से ही राजनीति में हूं लेकिन इतनी बुरी राजनीति मैंने देश के अंदर कभी नहीं देखी थी और मैं उम्मीद करता हूं कि हमसे जो बन पड़ेगा हम वो सब करेंगे देश की राजनीति को साफ करने के लिए, उसी के लिए आए हैं देश की राजनीति को साफ करना और जनता की सेवा करनी है। भगवान हमें अपना आर्शीवाद दे और हमें दिशा दिखाता रहे बहुत-बहुत शुक्रिया।

माननीय अध्यक्षः माननीया मुख्यमंत्री आतिशी जी चर्चा का उत्तर देंगी।

माननीया मुख्यमंत्री (श्रीमती आतिशी): माननीय अध्यक्ष जी, आज मैं आम आदमी पार्टी के सभी विधायकों की तरफ से कहूंगी कि ये सत्र और ये दिन हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है क्योंकि तकरीबन डेढ़ साल के बाद हमारी पार्टी के राम और लक्ष्मण अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी दोनों एक साथ इस सदन में बैठे हुए हैं, तो इस बात की आम आदमी पार्टी के सभी विधायकों को बहुत खुशी है। लेकिन हम सबके मन में दुःख भी है। हम सबके मन में दुःख भी है क्योंकि वो व्यक्ति, वो नेता अरविंद केजरीवाल जी जिनको दिल्ली की जनता ने प्रचंड बहुमत से जिताकर भेजा भारतीय जनता पार्टी के षड़्यंत्रों की वजह से, भारतीय जनता पार्टी ने जो उन पर कीचड़ उछला, भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें झूठे केसों में जो

फंसाया, भारतीय जनता पार्टी ने 6 महीने उन्हें जेल में रखा उसकी वजह से अरविंद केजरीवाल जी को इस्तीफा देना पड़ा और आज वो इस मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठे हुए हैं जिस पर दिल्ली की जनता ने उन्हें बिठाया था, इस बात का हम सबको बहुत दु:ख है। पिछले 2 साल से आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल जी को परेशान करने में भारतीय जनता पार्टी की और उनकी एजेंसीज़ ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। हमारी पार्टी के कोई ऐसे विधायक नहीं होंगे, कोई ऐसे नेता नहीं होंगे, कोई ऐसे मंत्री नहीं होंगे जिनके खिलाफ इनकी सीबीआई ने, ईडी ने, इनकम टैक्स ने, एसीबी ने केस नहीं किये होंगे। हमारे सब नेताओं के घरों पर रेड हो गई, उनके ऑफिस पर रेड हो गई, उनके पैतृक गांव पर रेड हो गई। मनीष जी के तो लॉकर पर रेड हो गई और मिला उनको क्या, एक झुनझुना। हम सबने इतने सालों से देखा है कि जब सीबीआई, ईडी कहीं रेड करती है तो बड़े-बड़े नोटों की गड्डियां मिलती हैं। सीबीआई और ईडी उनकी रंगोली बनाती है। सोने के बिस्कुट मिलते हैं। शैल कंपनीज के कागज मिलते हैं। अवैध प्रापर्टीज के कागज मिलते हैं। सैकड़ों और हजारों रेडों के बाद भी आम आदमी पार्टी के एक भी नेता से भ्रष्टाचार का एक रुपया भी नहीं मिला भारतीय जनता पार्टी की एजेंसीज को, क्यों? क्योंकि आम आदमी पार्टी एक ईमानदार पार्टी है। आम आदमी पार्टी जनता के, लोगों के लिए काम करने वाली पार्टी है लेकिन फिर भी इन्होंने एक के बाद एक आम आदमी पार्टी के नेताओं को गिरफ्तार किया। इन्होंने दिल्ली को मोहल्ला क्लीनिक देने वाले सत्येन्द्र जैन जी को गिरफ्तार किया।

इन्होंने दिल्ली की शिक्षा क्रांति के जनक मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार किया। इन्होंने संजय सिंह जी जो आम आदमी पार्टी के सांसद हैं उन्हें गिरफ्तार किया। और जब इतनी कोशिश के बावजूद भी आम आदमी पार्टी के दिल्ली सरकार के काम नहीं रोक पाए तो इन्होंने दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को भी गिरफ्तार किया, सिर्फ षड़्यंत्र रचने के लिए, सिर्फ दिल्ली वालों के काम रोकने के लिए, सिर्फ आम आदमी पार्टी को बदनाम करने के लिए। अध्यक्ष महोदय, अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार क्यों किया इसे समझने के लिए हमें दिल्ली के लोकतंत्र का इतिहास समझना पड़ेगा और शायद देश का भी। 2013 से पहले अगर आप दिल्ली का इतिहास देखिये तो सरकारें आती थीं, सरकारें जाती थीं, पार्टियां आती थीं, पार्टियां जाती थीं, मुख्यमंत्री आते थे मुख्यमंत्री जाते थे, लेकिन एक आम इंसान की जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ता था। जब एक तारीख आती थी न तो जब एक पति अपनी पत्नी को अपनी तनख्वाह देता था तो वो यही सोचती थी कि इतने से पैसे में महीना कैसे चलेगा। जब 25 तारीख आती थी तो हर महिला हर गृहिणी आपको बतायेगी कि घर में पैसे खत्म हो जाते थे, कैश खत्म हो जाता था तो वो सोचती थी कि अगले 5 दिन हम कैसे अपना गुजारा करेंगे। एक परिवार अपना पेट काट-काटकर बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजता था। अपने गहने गिरवी रखकर, अपना घर गिरवी रखकर अपने परिवार वालों को ईलाज कराता था। लड़कियां जब अपनी पढ़ाई खत्म कर लेती थीं, बारहवीं की पढ़ाई खत्म कर लेती थीं तो उनको कह दिया जाता था कि जी कॉलेज बहुत

दूर है आने-जाने का खर्चा बहुत ज्यादा है तो तुम तो कोरेसपोंडेंस से घर से पढ़ लो। ये हाल होता था दिल्ली के लोगों का, दिल्ली के आम लोगों का, दिल्ली के गरीब लोगों का, लेकिन 2015 में दिल्ली में एक चमत्कार हुआ। दिल्ली के लोगों ने अपने बेटे, अपने भाई अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री चुनकर भेजा और तभी से दिल्ली वालों की, दिल्ली की महिलाओं की, दिल्ली के बच्चों की हाथों की लकीर बदल गई, उनकी तकदीर बदल गई। अरविंद केजरीवाल जी वो आदमी हैं जिन्होंने दिल्ली वालों को 24 घंटे बिजली दी फिर भी जीरो बिजली का बिल दिया। अरविंद केजरीवाल जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने गरीब बच्चों को वर्ल्ड क्लास शिक्षा दी इंजीनियर बनने का मौका दिया, डॉक्टर बनने का मौका दिया आंथ्रोप्रिन्योर बनने का मौका दिया, ये हैं अरविंद केजरीवाल जी। ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने परिवारों को उस व्यथा से निकाला कि परिवार के एक सदस्य के ईलाज के लिए हमें अपना घर गिरवी रखना पड़ता था, इन्होंने सब सरकारी अस्पतालों में वर्ल्ड क्लास ईलाज दिया, मोहल्ला क्लीनिक में फ्री दवाइयां दी। लड़कियों को कॉलेज में पढ़ने का मौका दिया क्योंकि बस यात्रा फ्री कर दी। बुजुर्गों को फ्री तीर्थयात्रा दी और ये सब तब किया जब साथ में उन्होंने दिल्ली को और मैं ये बता दूं भारतीय जनता पार्टी की तो 22 राज्यों में सरकार है 1 राज्य में भी न ये फ्री बिजली देते हैं, न पानी देते हैं, न अच्छे स्कूल देते हैं, न अच्छे अस्पताल देते हैं फिर भी घाटे में चलती हैं इनकी सरकारें। अरविंद केजरीवाल जी ने फ्री बिजली दी, पानी दिया, स्कूल दिये, अस्पताल दिये, मोहल्ला क्लीनिक दी, फ्री बस यात्रा दी,

तीर्थ यात्रा दी और फिर भी देश की इकलौती मुनाफे में चलने वाली सरकार दी, ये हैं अरविंद केजरीवाल जी की सरकार, ये है आम आदमी पार्टी की सरकार। क्यों कर पाये क्योंकि अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार हैं। क्यों कर पाये, क्योंकि आईआईटी से पासआउट इंजीनियर हैं, पढ़े-लिखे हैं इनको काम करवाना आता है इसलिए 10 साल में इतना बेहतर काम कर पाये। अब भारतीय जनता पार्टी की क्या समस्या थी। अपने तो किसी भी राज्य में वो काम करके नहीं दिखा सकते थे। अपने तो किसी भी नेता पर ईमानदारी का ठप्पा नहीं लगा सकते थे। कहीं अच्छे स्कूल नहीं दे सकते थे। कहीं अच्छे अस्पताल नहीं दे सकते थे, तो उन्होंने सोचा जी हम एक काम करते हैं, इस ईमानदारी से काम करने वाले नेता पर कीचड़ उछालते हैं और तभी सीबीआई का केस किया, ईडी का केस किया, परेशान किया अरविंद केजरीवाल जी को, उनके सारे नेताओं को क्यों उनकी ईमानदारी पर कीचड़ उछालना चाहते थे, दिल्ली वालों के काम रोकना चाहते थे और इसीलिए काम रोकने के लिए अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाल दिया। लेकिन अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि ये ईडी और सीबीआई और एसीबी दिल्ली पुलिस में बहुत ताकत हैं लेकिन मैं आपको बता दूं आपकी ईडी और सीबीआई और दिल्ली पुलिस से बहुत ज्यादा ताकत दिल्ली की मांओं की दुआओं में है, दिल्ली की बहनों के आर्शीवाद में है, दिल्ली के बच्चों के प्यार में है और उसी प्यार और उसी आर्शीवाद की वजह से अरविंद केजरीवाल जी बाहर आए हैं। अरविंद केजरीवाल जी चाहते तो इस्तीफा नहीं देते। सुप्रीम कोर्ट ने जितनी तीखी टिप्पणी

इनकी सीबीआई और ईडी और सेंट्रल एजेंसीज पर की, सुप्रीम कोर्ट ने तो उनके मुंह पर तमाचा मारा और कहा कि केन्द्र सरकार की एजेंसियां पिंजरे में कैद एक तोते की तरह हैं। शायद कोई और नेता होता तो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने से पहले दो मिनट भी नहीं सोचता लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने इस देश के इतिहास में ईमानदारी की और नैतिकता की मिसाल कायम की है और इस्तीफा देकर दिल्ली के लोगों को कहा कि अगर आपको मेरी ईमानदारी पर भरोसा है, मैं तभी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठूंगा। मैं तो भारतीय जनता पार्टी से ये पूछना चाहती हूं कि आपके किसी नेता में ऐसी हिम्मत है क्या? मैं दिल्ली वालों को ये भी भरोसा दिलाना चाहती हूं कि अब अरविंद केजरीवाल जी जेल से बाहर आ गये हैं। पिछले 6 महीने से जब से अरविंद केजरीवाल जी जेल में थे भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली वालों के काम रोकने की हर साजिश की। बुजुर्गों की 6 महीने तक पेंशन रोके रखी, विधवाओं की पेंशन रोके रखी, दिल्ली जलबोर्ड के पैसे रोक दिये, सड़कें तुड़वा दीं, हॉस्पिटल में, मोहल्ला क्लीनिक में दवाइयां रुकवा दीं लेकिन अब अरविंद केजरीवाल जी जेल से बाहर आ गये हैं और मैं दिल्ली वालों को ये भरोसा दिलाती हूं कि अरविंद केजरीवाल जी के मार्गदर्शन में दिल्ली वालों के सारे रुके हुए काम अगले 6 महीने में होने वाले हैं जैसा अरविंद केजरीवाल जी ने खुद दिल्ली वालों को वादा किया था। अभी कुछ देर पहले महाजन जी किसी के भाषण के दौरान जीरो-जीरो-जीरो कई बारी कह रहे थे, तो मुझे लगता है कि हमारे भाजपा वालों को भी, दोस्तों को पता ही है कि फरवरी में आने वाले

चुनावों का क्या नतीजा होने वाला है। इस बार तो अभी वहां पर हाउस में 8 सीटें आपके पास हैं पर जो षड़्यंत्र आपने दिल्ली के बेटे, दिल्ली के भाई अरविंद केजरीवाल के खिलाफ रचा है, अध्यक्ष महोदय अगली बार आपके पास अपोजीशन की कुर्सियों में एक भी व्यक्ति बैठने के लिए नहीं होगा दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल जी को 70 में से 70 सीटें देकर भेजेंगे और फिर से दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाएंगे बहुत-बहुत धन्यवाद, जय हिन्द, जय भारत।

माननीय अध्यक्षः अब श्रीमती आतिशी, माननीय मुख्यमंत्री प्रस्ताव करेंगी कि दिनांक 26 सितम्बर, 2024 को सदन में पुरःस्थापित 'दिल्ली माल एवं सेवा कर (तृतीय संषोधन) विधेयक, 2024 (वर्ष 2024 का विधेयक संख्या-03)' पर विचार किया जाए।

माननीया मुख्यमंत्री (श्रीमती आतिशी): Hon'ble Speaker Sir, I move that the 'The Delhi Goods & Services Tax (Third Amendment) Bill, 2024 (Bill No. 03 of 2024) introduced in the House on 26 September, 2024, be taken into consideration.

(मुख्यमंत्री द्वारा प्रस्ताव करने के बाद)

माननीय अध्यक्षः यह प्रस्ताव सदन के सामने है-

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें

जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें

(सदस्यों के हाँ कहने पर)

हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता

प्रस्ताव पारित हुआ।

यदि कोई सदस्य इस विधेयक के संबंध में अपने विचार व्यक्त करना चाहे, तो अपने विचार व्यक्त कर सकता है।

<u>विधेयक पर खण्डवार विचार।</u>

अब विधेयक पर खण्डवार विचार होगा। प्रश्न है कि खण्ड-02 से 05, विधेयक का अंग बनें। यह प्रस्ताव सदन के सामने है-

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें

जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें

(सदस्यों के हाँ कहने पर)

हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता

प्रस्ताव पारित हुआ।

खण्ड-02 से 05 विधेयक का अंग बन गये। अब प्रश्न है कि खण्ड-1, प्रस्तावना, शीर्षक और अनुसूची विधेयक का अंग बनें-

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें,

जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें,

प्रस्ताव पारित हुआ।

(सदस्यों के हाँ कहने पर)

हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता

खण्ड–1, प्रस्तावना, शीर्षक और अनुसूची विधेयक का अंग बन गये।

विधेयक को पारित करना

अब श्रीमती आतिषी, माननीय मुख्यमंत्री प्रस्ताव करेंगी कि दिनांक 26 सितम्बर, 2024 को सदन में पुरःस्थापित 'दिल्ली माल एवं सेवा कर (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2024 (वर्ष 2024 का विधेयक संख्या–03)' को पारित किया जाए।

माननीया मुख्यमंत्री (श्रीमती आतिशी): Hon'ble Speaker Sir, I move that the 'The Delhi Goods & Services Tax (Third Amendment) Bill, 2024 (Bill No. 03 of 2024) introduced in the House on 26 September, 2024, be passed.

(मुख्यमंत्री द्वारा प्रस्ताव करने के बाद)

माननीय अध्यक्षः यह प्रस्ताव सदन के सामने है–

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें

जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें

(सदस्यों के हाँ कहने पर)

हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता

प्रस्ताव पारित हुआ।

विधेयक पास हुआ।

सदन को अनिश्चित काल तक के लिये स्थगित करने से पहले मैं सदन की नेता एवं माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती आतिशी, सभी मंत्रीगण, माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री विजेंद्र गुप्ता तथा सदन के सभी माननीय सदस्यों का हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ।

इसके अलावा सत्र के संचालन में सहयोग देने के लिए विधान सभा सचिवालय तथा दिल्ली सरकार के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ-साथ विभिन्न विभागों और सुरक्षा एजेंसियों तथा मीडिया का भी धन्यवाद करता हूँ।

अब मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे राष्ट्र गान के लिए खड़े हों।

<u>राष्ट्रगान : जन-गण-मन</u>

अब सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित की जाती है सभी का बहुत-बहुत आभार।

© दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1991 की धारा 18 (2) के उपबंधों तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 281 (2) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रकाशित तथा ग्राफिक प्रिंटर्स, 2965 /41, बीडनपुरा, करोल बाग, नई दिल्ली-110 005 द्वारा मुद्रित।